

**मुख्य पाठ्यक्रम**

**समूह - II**

**पुनरावृत्ति परीक्षा प्रश्न-पत्र**

**मई, 2025**



**अध्ययन बोर्ड (अकादमिक)**

**भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान  
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)**

**नई दिल्ली**

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रकाशक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी प्रारूप में, या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या अन्यथा, पुनरुत्पादित, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

संस्करण	:	मार्च, 2025
वेबसाइट	:	<a href="http://www.icaai.org">www.icaai.org</a>
विभाग/समिति	:	अध्ययन बोर्ड (अकादमिक)
ई-मेल	:	<a href="mailto:bosnoida@icaai.in">bosnoida@icaai.in</a>
कीमत	:	
आईएसबीएन सं.	:	
प्रकाशक	:	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आईसीएआई भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 7100, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली- 110 002, भारत की ओर से प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय
		अध्ययन बोर्ड में टाइपसेट और डिजाइन
मुद्रण	:	

# अंतर्वस्तु

पृष्ठ संख्या

उद्देश्य एवं दृष्टिकोण.....	i – viii
पुनरावृत्ति परीक्षा प्रश्न-पत्र का उद्देश्य.....	i
परीक्षा की योजना एवं तैयारी.....	ii
विषय-वार प्रयोज्यता.....	iii
<b>प्रश्न-पत्र-वार आरटीपी</b>	
प्रश्न-पत्र 4: प्रत्यक्ष कर कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान.....	1 – 36
प्रश्न-पत्र 5: अप्रत्यक्ष कर कानून.....	37 – 65
प्रश्न-पत्र 6: एकीकृत व्यावसायिक समाधान.....	66 – 109
मानकों/मार्गदर्शन टिप्पणियों/विधायी संशोधनों आदि की मई, 2025 की मुख्य परीक्षा हेतु प्रयोज्यता.....	110 - 113

## पुनरावृत्ति परीक्षा प्रश्न-पत्र, मई, 2025 – उद्देश्य एवं दृष्टिकोण

(छात्रों को सलाह दी जाती है कि इस पुनरावृत्ति परीक्षा प्रश्न-पत्र से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें)

### I. पुनरावृत्ति परीक्षा प्रश्न-पत्र का उद्देश्य

पुनरावृत्ति परीक्षा प्रश्न-पत्र अध्ययन बोर्ड (बीओएस) द्वारा अपने छात्रों को प्रदान किए जाने वाले कई शैक्षिक इनपुट में से एक है। छात्रों इसे आरटीपी के नाम से जानते हैं, यह अध्ययन बोर्ड के बहुत पुराने प्रकाशनों में से एक है, जिसका महत्व और प्रासंगिकता परीक्षा के दृष्टिकोण से समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है।

पुनरावृत्ति परीक्षा प्रश्न-पत्र के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- छात्रों को आगामी परीक्षा हेतु उनकी तैयारियों का आकलन करने में मदद करना;
- छात्रों को आगामी परीक्षा हेतु प्रासंगिक सभी नवीनतम घटनाक्रमों की जानकारी एक ही जगह पर प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना;
- छात्रों के आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाना; तथा

छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आरटीपी में पाठ्यक्रम के विभिन्न वर्गों पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसलिए आरटीपी के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करना अति-आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आरटीपी से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि आरटीपी में दिए गए प्रश्नों को हल करना शुरू करने से पहले छात्रों को अध्ययन सामग्री और वैधानिक अपडेट्स/न्यायिक अपडेट्स, जहाँ भी लागू हो, को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए।

यहां जिन विषयों पर प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक चुना गया है तथा इन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है। छात्रों को स्व-मूल्यांकन करने और ठीक से तैयारी हेतु उनमें एक केंद्रित दृष्टिकोण विकसित के लिए विस्तृत उत्तर दिए गए हैं।

फाउंडेशन, इंटरमीडिएट तथा फाइनल स्तर के छात्रों के लिए वर्चुअल मोड में निःशुल्क संचालित किए जाने वाले प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों द्वारा लाइव लर्निंग क्लासेस छात्रों को घर रहते हुए आसानी से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने में बहुत मदद करते हैं क्योंकि इन क्लासेस को स्मार्ट फोन, लैपटॉप, आई-पैड, टैबलेट आदि जैसे हैंड-हेल्ड डिवाइसों के माध्यम से कभी भी कहीं भी लाइव देखा जा सकता है या रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स को

बाद में देखा जा सकता है। इसके अलावा, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एमसीक्यू प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पोर्टल पर बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) को हल करने का प्रयास करें, जो तय समय सीमा के भीतर खुद का मूल्यांकन करने का एक प्लेटफॉर्म है।

छात्र निदेशक, अध्ययन बोर्ड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, ए-29, सेक्टर-62, नोएडा 201309 (उत्तर प्रदेश) को आरटीपी में किसी तरह का सुधार करने के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। आरटीपी बीओएस नॉलेज पोर्टल के अंतर्गत संस्थान की वेबसाइट <https://boslive.icai.org> पर भी उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

## II. परीक्षा की योजना एवं तैयारी

यह सबसे उचित रहेगा कि आरटीपी मिलने से पहले आप बीओएस नॉलेज पोर्टल पर उपलब्ध सभी विषयों की प्रासंगिक अध्ययन सामग्री (प्रश्न-पत्र 4 और प्रश्न-पत्र 5 के संदर्भ में वैधानिक अपडेट और प्रश्न-पत्र 4 में न्यायिक अपडेट के साथ) को पढ़ चुके हों। उसमें चर्चा की गई अवधारणाओं/प्रावधानों/संशोधनों/मामलों को ठीक से समझें।

अध्ययन सामग्री के साथ-साथ वैधानिक अपडेट्स एवं न्यायिक अपडेट्स को अच्छी तरह से पढ़ने के पश्चात्, आरटीपी में दिए गए प्रश्नों को स्वयं हल करना शुरू करना चाहिए। अध्ययन सामग्री में दी गई अवधारणाओं और प्रावधानों को दोहराने तथा खुद को अपडेटेड रहने हेतु आरटीपी एक प्रभावी साधन है। आरटीपी आपकी तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसलिए आपको उसमें दिए गए प्रश्नों को स्वयं हल करना चाहिए और उसके पश्चात् अपने उत्तरों की तुलना उसमें दिए गए उत्तरों से करना चाहिए।

### परीक्षा संबंधी युक्तियाँ

परीक्षा में एक छात्र का प्रदर्शन कितना अच्छा होगा यह उसकी तैयारी के स्तर और गहराई पर निर्भर करता है। हालाँकि, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एक छात्र को परीक्षा में अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये उपयोगी सुझाव नीचे दिए गए हैं:

- परीक्षा हॉल में समय से पहुंचें।
- प्रश्न पत्र मिलने पर सबसे पहले उसे ध्यान से तथा अच्छी तरह से पढ़ लें। प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु आपको अलग से 15 मिनट का समय दिया जाता है।
- अपने समय की योजना बनाएं ताकि प्रत्येक प्रश्न को उचित समय दिया जा सके।

- फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। इसलिए जिस प्रश्न का उत्तर आप सबसे अच्छे तरीके से दे सकते हैं, उसे पहले हल करना चाहिए।
- सभी प्रश्नों को करने का प्रयास करें। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रत्येक प्रश्न को तय समय के भीतर हल करें। कुछ समय उत्तरों की जांच करने के लिए भी रखें।
- उत्तर शुरू करने से पहले प्रश्न को कई बार ध्यान से पढ़ें ताकि यह समझ सकें कि क्या उत्तर देना आवश्यक है।
- एक-एक कर प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दें; एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों का उत्तर अलग-अलग स्थानों पर न दें।
- साफ और सुपाठ्य लिखें।
- उत्तर में हमेशा संक्षिप्त और मुख्य बात ही लिखें और अनावश्यक पृष्ठ भरने का प्रयास न करें।
- उत्तर की तार्किक अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
- यदि कोई प्रश्न स्पष्ट नहीं है, तो आप अपनी धारणाएँ बता सकते हैं तो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
- परीक्षा हॉल से बाहर निकलने से पहले अपने उत्तरों को ध्यान से देखें तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करें।
- केस परिदृश्य आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में, केस में दिए गए तथ्यों को ध्यान से पढ़ें। साथ ही, सही उत्तर चुनने से पहले, उस पर आधारित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्नों तथा सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ें।

### III. विषय-वार प्रयोज्यता

#### प्रश्न-पत्र - 4: प्रत्यक्ष कर कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान तथा 31.10.2024 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, परिपत्र तथा अन्य विधायी संशोधन मई, 2025 की परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं। मई, 2025 की परीक्षा हेतु प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष नि.व.2025-26 है।

अध्ययन सामग्री का नवंबर 2024 संस्करण, जिसमें चार मॉड्यूल (मॉड्यूल 1 से 4) हैं, मई, 2025 की परीक्षा हेतु उपयुक्त है।

उपर्युक्त अध्ययन सामग्री को मई, 2025 परीक्षा हेतु आरटीपी में दिए गए वैधानिक अपडेट के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें 31.10.2024 तक की जारी महत्वपूर्ण

अधिसूचनाएँ/परिपत्र शामिल हैं, लेकिन यह अध्ययन सामग्री के नवंबर, 2024 संस्करण में शामिल नहीं हैं, जो मई, 2025 परीक्षा हेतु भी प्रासंगिक हैं। मई, 2025 परीक्षा हेतु न्यायिक अपडेट <https://resource.cdn.icai.org/84599bos68185.pdf> पर उपलब्ध है, जो मई, 2025 परीक्षा हेतु भी प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण है।

आपको वैचारिक स्पष्टता पाने तथा संशोधनों के प्रभाव और न्यायालय के फैसलों की व्याख्या को समझने हेतु अध्ययन सामग्री के नवंबर, 2024 संस्करण के साथ-साथ मई, 2025 की परीक्षा के लिए वैधानिक अपडेट्स और न्यायिक अपडेट्स को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अवधारणाओं को आसानी से समझाने के लिए तालिकाओं, आरेखों व फ्लो चार्ट का अधिक उपयोग किया गया है। वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा किए गए संशोधन और नवीनतम अधिसूचनाएं और परिपत्र **इटैलिकाबोल्ड इटैलिक** में दिए गए हैं। अध्ययन सामग्री में दिए गए उदाहरण और रेखांकन आपको अवधारणाओं के इस्तेमाल को समझने में मदद करेंगे। प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न हल करें और फिर, आपने कितना समझा, यह जानने के लिए दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें।

अंत में, इस आरटीपी में दिए गए प्रश्नों को अलग-अलग हल करें और परीक्षा हेतु आप कितने तैयार हैं, यह जानने के लिए दिए गए उत्तरों के साथ उनकी तुलना करें।

#### प्रश्न-पत्र – 5: अप्रत्यक्ष कर कानून

फाइनल लेवल में अप्रत्यक्ष कर कानून का विषय दो भागों, अर्थात् भाग I: माल एवं सेवा कर जिसके लिए 80 अंक हैं और भाग II: सीमा शुल्क एवं विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) जिसके लिए 20 अंक हैं, में विभाजित कर दिया गया है। इस प्रश्न-पत्र के संबंध में, मई 2025 की परीक्षा में निम्नलिखित लागू हैं:

- (i) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधान, जिनमें जारी की गई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र तथा किए गए अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं।
- (ii) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधान, जिनमें जारी की गई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र तथा किए गए अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं।

टिप्पणी - वार्षिक केंद्रीय वित्त अधिनियमों द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017, आईजीएसटी अधिनियम, 2017, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में किए गए संशोधन बाद में अधिसूचित तिथि से प्रभावी किए गए हैं। प्रासंगिक वित्त अधिनियमों द्वारा किए गए केवल वे संशोधन जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं, मई 2025 की परीक्षा हेतु उपयुक्त हैं। इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2024 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा किए गए वे संशोधन जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं, मई 2025 की परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं।

तदनुसार, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16, 109 और 171 में किए गए संशोधन, जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं, मई 2025 की परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं और वित्त अधिनियम, 2024 और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा किए गए शेष संशोधन उक्त परीक्षा हेतु उपयुक्त नहीं हैं।

इसके अलावा, यह ध्यान देना चाहिए कि वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9, 9क और 9ग में तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में किए गए संशोधन और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में नई धारा 65क को सम्मिलित करना 31.10.2024 तक प्रभावी नहीं हुए हैं और इस प्रकार, मई 2025 की परीक्षा हेतु उपयुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(4), 95, 102, 103, 104, 105 और 106 में किए गए संशोधन और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में नई धारा 101क, 101ख और 101ग को सम्मिलित करना 31.10.2024 तक प्रभावी नहीं हुए हैं और इस प्रकार, मई 2025 की परीक्षा हेतु उपयुक्त नहीं हैं।

इसके अलावा, पाठ्यक्रम से हटाए गए विषयों की विषयवार सूची "मई 2025 परीक्षा हेतु अध्ययन दिशानिर्देश" के ज़रिए दी गई है। इसे इस संशोधन प्रश्न पत्र के अंत में संलग्न "मई 2025 मुख्य परीक्षा हेतु मानकों/मार्गदर्शन नोटों/विधायी संशोधनों आदि की प्रयोज्यता" के भाग के रूप में दिया गया है।

छात्र ध्यान दें कि अध्ययन सामग्री का नवंबर 2024 संस्करण मुख्य प्रश्न-पत्र 5: अप्रत्यक्ष कर कानून के लिए उपयुक्त है। छात्रों की आसानी के लिए अध्ययन सामग्री को चार मॉड्यूल में बांटा गया है। पहले तीन मॉड्यूल जीएसटी पर आधारित हैं और चौथा मॉड्यूल सीमा शुल्क और एफटीपी पर आधारित है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों पर अध्ययन सामग्री के भाग I: वस्तु एवं सेवा कर की विषय-वस्तु वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों पर आधारित है,

जिसमें जारी की गई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र तथा किए गए अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं।

भाग II: सीमा शुल्क एवं एफटीपी में चर्चा की गई अध्ययन सामग्री वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों पर आधारित है, जिसमें जारी की गई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ और परिपत्र तथा किए गए अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं। सीमा शुल्क कानूनों पर मॉड्यूल में "महत्वपूर्ण चुने गए केस" के तहत प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए केस लॉ को पढ़ें।

इस आरटीपी में दिए गए प्रश्नों को अलग-अलग हल करें और परीक्षा की अपनी तैयारी का आकलन करने हेतु दिए गए उत्तरों से उनकी तुलना करें। प्रश्नों के समाधान में अप्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों को ठीक से समझने के लिए इस आरटीपी में दिए गए वर्णनात्मक प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए गए हैं। इससे आपकी वैचारिक स्पष्टता बढ़ेगी तथा इनके इस्तेमाल और विश्लेषणात्मक कौशल को निखारने में मदद मिलेगी ताकि आप पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी परीक्षा दे सकें।

### प्रश्न-पत्र – 6: एकीकृत व्यावसायिक समाधान

'केस स्टडी' एकीकृत व्यावसायिक समाधान (आईबीएस) पाठ्यक्रम का खास हिस्सा है, जो सीए फाइनल लेवल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहां, छात्रों को फाइनल लेवल पर पांच मुख्य विषयों तथा स्वाध्याय मॉड्यूल समूह क और ख से मिले अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रश्न-पत्र में, छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे केस स्टडी को हल करने में विभिन्न विषयों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करें।

### उपयुक्त प्रकाशन

मुख्य प्रश्न-पत्र 1, 2, 3, 4, 5 (नवंबर, 2024) के मुख्य प्रश्न-पत्र की अध्ययन सामग्री

- एसपीओएम समूह-क (अप्रैल, 2023) की अध्ययन सामग्री संशोधनों के साथ इसपर उपलब्ध है –

<https://resource.cdn.icai.org/83835bos67607.pdf>

- एसपीओएम समूह-ख की अध्ययन सामग्री (अक्टूबर, 2023)

- आईबीएस केस स्टडी डाइजेस्ट<sup>1</sup> (जुलाई 2024 संस्करण)
- केस स्टडीज़ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं -  
[https://boslive.icai.org/sm\\_chapter\\_details.php?p\\_id=18&m\\_id=74](https://boslive.icai.org/sm_chapter_details.php?p_id=18&m_id=74)

टिप्पणी - उपरोक्त इनपुट पर अध्ययन दिशानिर्देशों (मई, 2025 परीक्षा के लिए) के साथ, जहाँ भी लागू हो, विचार किया जा सकता है।

### मूल्यांकन का तरीका

इस प्रश्न-पत्र का मूल्यांकन 40% एमसीक्यू के माध्यम से तथा 60% वर्णनात्मक प्रश्नों के रूप में किया जाएगा, प्रत्येक केस स्टडी हेतु 25 अंक होंगे। परीक्षा ओपन बुक होगी, जिससे रटने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।

### आरटीपी केस स्टडीज

इस पुनरावृत्ति परीक्षा प्रश्न-पत्र में दो केस स्टडी दिए गए हैं। केस स्टडी के अनुसार डेटा नीचे सारणीबद्ध है:

केस स्टडी	उद्योग	विषय-वस्तु	विषय
1	कृषि रसायन उद्योग 	वित्तीय रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून, रणनीतिक प्रबंधन, रणनीतिक लागत प्रबंधन	जस्ट इन टाइम, एसए 250, मूल्य संवेदनशीलता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 235, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1क), इंड एस 20, बिक्री विचरण, ईवीए पर आधारित वित्तीय प्रदर्शन

<sup>1</sup> केस स्टडी डाइजेस्ट में 50 केस स्टडी दिए गए हैं, जिनमें से कई विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले समकालीन बिजनेस मॉडल पर आधारित हैं। इन क्षेत्रों में पेय उद्योग (विशेष रूप से टी सेगमेंट), ई-कॉमर्स, परिवहन, दूरसंचार, विमानन क्षेत्र, खाद्य एवं आतिथ्य, निर्माण उद्योग, स्वास्थ्य सेवा व फास्ट फ़ेशन उद्योग शामिल हैं। प्रत्येक केस स्टडी इन क्षेत्रों में सफलता पाने में मददगार करने वाली अभिनव रणनीतियों और पद्धतियों का गहन विश्लेषण देती करती है।

2	<p>हीरा एवं आभूषण उद्योग</p> 	<p>वित्तीय रिपोर्टिंग, अप्रत्यक्ष कर, लेखा परीक्षा, रणनीतिक प्रबंधन, कॉर्पोरेट और आर्थिक कानून, रणनीतिक लागत प्रबंधन</p>	<p>इंड एस 24, सीजीएसटी नियमों का नियम 28, जीवन चक्र लागत निर्धारण, विकेंद्रीकृत संरचना, एसए 550, कंपनी अधिनियम की धारा 2(76)(viii), सेबी एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 2(1)(जेडबी), अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण मूल्य निर्धारण</p>
---	--	--	---

**एक समय दृष्टिकोण**

कई विषयों पर आधारित 'केस स्टडी' को हल करने से छात्रों का विश्लेषणात्मक कौशल और निर्णय लेने का कौशल बढ़ेगा। इस समय एवं एकीकृत दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होता है कि छात्र लगातार बदलते बिजनेस के माहौल में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हों।

यदि छात्रों को किसी भी विषय में कठिनाई होती है, तो वे विभिन्न विषयों में दिए गए "सारांश" का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें प्रत्येक विषय में महत्वपूर्ण अवधारणाओं और प्रावधानों को जल्दी से दोहराने के लिए अवधारणाओं और प्रावधानों को आरेखों, चार्ट तथा तालिकाओं के ज़रिए समझाया गया है।





## प्रश्न-पत्र - 4 :

### प्रत्यक्ष कर कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान और 31.10.2024 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र, मई 2025 की परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं। संबंधित कर निर्धारण वर्ष नि.व.2025-26 है। अध्ययन सामग्री के नवंबर, 2024 संस्करण में वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान और 31.10.2024 तक जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र शामिल हैं। उक्त अध्ययन सामग्री को निम्नलिखित वैधानिक अपडेट्स के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें 31.10.2024 तक जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र शामिल हैं, लेकिन अध्ययन सामग्री और मई, 2025 परीक्षा के लिए न्यायिक अद्यतन में शामिल नहीं हैं, जो <https://resource.cdएन.icai.org/84599bos68185.pdf> पर वेबहोस्टेड है।

#### वैधानिक जानकारी

- आईएफएससी में स्थित निर्दिष्ट इकाईयों को किए गए कुछ भुगतानों के संबंध में टीडीएस प्रावधानों की गैर-प्रयोज्यता [अधिसूचना संख्या 28/2024 दिनांक 7.3.2024]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक(1क)/(2) के साथ पठित धारा 197क(1च) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना के ज़रिए अधिसूचित किया है कि किसी भी 'भुगतानकर्ता' द्वारा किसी आदाता को, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की इकाई है, किए गए निर्दिष्ट भुगतानों के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती किए जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट है:-

तालिका: आईएफएससी की इकाई द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतानों की सूची

क्र.सं.	आईएफएससी इकाई (भुगतानकर्ता)	प्राप्य की प्रकृति	प्रासंगिक टीडीएस प्रावधान
1.	बैंकिंग इकाई	बाहरी वाणिज्यिक ऋण/उधार पर ब्याज आय	धारा 195
		प्रोफेशनल शुल्क	धारा 194ज

		रेफरल शुल्क	धारा 194ज
		ब्रोकरेज आय	धारा 194ज
		फैक्टरिंग एवं फॉरफ़ाइटिंग सेवाओं पर कमीशन आय	धारा 194ज
2.	आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय	बीमा कमीशन	धारा 194घ
3.	वित्त कंपनी	बाहरी वाणिज्यिक ऋण/उधार पर ब्याज आय	धारा 195/194क
		लाभांश आय	धारा 194
		फैक्टरिंग और फॉरफ़ाइटिंग सेवाओं पर कमीशन आय	धारा 194ज
4.	वित्त इकाई	बाहरी वाणिज्यिक ऋण/उधार पर ब्याज आय	धारा 195/194क
		लाभांश आय	धारा 194
		फैक्टरिंग और फॉरफ़ाइटिंग सेवाओं पर कमीशन आय	धारा 194ज
5.	फंड प्रबंधन इकाई	प्रोफेशनल शुल्क	धारा 194ज
6.	ब्रोकर डीलर	लाभांश	धारा 194
7.	निवेश सलाहकार	निवेश सलाहकार शुल्क	धारा 194ज
8.	पंजीकृत वितरक	वितरण शुल्क और कमीशन शुल्क	धारा 194ज
9.	कस्टोडियन	प्रोफेशनल शुल्क	धारा 194ज
		कमीशन शुल्क	धारा 194ज
10.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	धारा 194ज
11.	इन्वेस्टमेंट बैंकर	इन्वेस्टमेंट बैंकर शुल्क	धारा 194ज

12.	डिबेंचर ट्रस्टी	ट्रस्टीशिप शुल्क	धारा 194ज
13.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा या “आईटीएफएस”	कमीशन आय	धारा 194ज
14.	फिनटेक संस्था	तकनीकी शुल्क/प्रोफेशनल शुल्क	धारा 194ज
		कमीशन आय	धारा 194ज

उपर्युक्त निर्दिष्ट भुगतानों के संबंध में टीडीएस प्रावधानों की गैर-प्रयोज्यता हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है:

'भुगतानकर्ता (पेयी)' को दाता (पेयर) को एक विवरण-सह-घोषणा (स्टेटमेंट-कम-डिक्लेरेेशन) देनी होगी जिसमें उन दस लगातार निर्धारण वर्षों से संबंधित पिछले वर्षों का ब्यौरा देना होगा जिनके लिए 'भुगतानकर्ता' ने धारा 80ठक(1क)/(2) के अंतर्गत कटौती का दावा करने का विकल्प चुना है, और

ऐसा विवरण-सह-घोषणा (स्टेटमेंट-कम-डिक्लेरेेशन) उन दस लगातार कर निर्धारण वर्षों से संबंधित प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए प्रस्तुत एवं सत्यापित किया जाना चाहिए, जिसके लिए 'भुगतानकर्ता' धारा 80ठक(1क)/(2) के अंतर्गत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है।

'दाता', 'भुगतानकर्ता' से ऐसे स्टेटमेंट-कम-डिक्लेरेेशन की कॉपी मिलने की तारीख के बाद 'भुगतानकर्ता' के खाते में भेजे गए या जमा किए गए ऐसे भुगतानों पर कर नहीं काटेगा; तथा स्रोत पर कर कटौती के विवरण में 'भुगतानकर्ता' को किए गए उन सभी भुगतानों का ब्यौरा देगा जिन पर इस अधिसूचना के मद्देनजर कर नहीं काटा गया है।

उपरोक्त छूट 'भुगतानकर्ता' को केवल उन पिछले वर्षों के दौरान उपलब्ध है जो 'भुगतानकर्ता' द्वारा घोषित दस लगातार मूल्यांकन वर्षों से संबंधित हैं, जिसके लिए धारा 80ठक के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है। 'दाता (पेयर)' किसी अन्य वर्ष के लिए ऊपर बताए गए भुगतानों पर कर कटौती करने हेतु उत्तरदायी होगा।

**टिप्पणी** – कृपया इन निर्दिष्ट आईएफएससी इकाइयों की परिभाषा के लिए उपरोक्त अधिसूचना देखें।

2. आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर धारा 197क(1घ) और धारा 10(15)(viii) की प्रयोज्यता [परिपत्र संख्या 26/2016 दिनांक 4.7.2016]

धारा 197क में वो परिस्थितियां निर्दिष्ट हैं जिनमें अधिनियम के खंड XVII के तहत स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक नहीं है। धारा 197क(1घ) में प्रावधान है कि किसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट द्वारा भुगतान किए गए ब्याज से कोई कर नहीं काटा जाना चाहिए।

- किसी अनिवासी या भारत में सामान्यतः निवासी न होने वाले व्यक्ति द्वारा 1.4.2005 को या उसके बाद जमा की गई राशि पर, या
- किसी अनिवासी या भारत में सामान्यतः निवासी न रहने वाले व्यक्ति से 1.4.2005 को या उसके बाद ऋण लेने पर।

धारा 10(15)(viii) में प्रावधान है कि ऐसा ब्याज ऐसे अनिवासी या भारत में सामान्यतः निवासी न होने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

ऑफशोर बैंकिंग यूनिट को विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(यू) में विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित बैंक की शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) के तहत अनुमति प्राप्त की है।

आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स (आईबीयू) भारतीय बैंकों या विदेशी बैंकों की भारत में उपस्थिति वाली शाखाएं हैं, जो आईएफएससी में आरबीआई योजना दिनांक 1.4.2015 के अनुसार स्थापित की गई हैं, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। इसलिए, आईबीयू विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 (यू) में परिभाषित ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स के रूप में विचार किए जाने हेतु आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं।

इसलिए, सीबीडीटी ने इस परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि धारा 197क(1घ) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आईबीयू द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर, किसी अनिवासी या ऐसे व्यक्ति द्वारा 1.4.2005 को या उसके बाद किए गए जमा पर, जो भारत में सामान्य रूप से निवासी नहीं है, या ऐसे व्यक्तियों से 1.4.2005 को या उसके बाद लिए गए ऋण पर कर काटने की आवश्यकता नहीं है।



## प्रश्न

## केस परिदृश्य।

श्री देवांश एक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो पिछले 15 वर्षों से यू.के. में रह रहे हैं। वह हर साल एक महीने के लिए अपने माता-पिता से मिलने भारत आते हैं। साल के बाकी महीने वह यू.के. में ही रहते हैं।

उन्होंने परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अल्फा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड और डेल्टा लिमिटेड के शेयरों में निवेश किया है। अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड गिफ्ट आईएफएससी, गुजरात में निगमित कंपनियां हैं, जो ऐसे व्यवसाय कर रही हैं जिसके लिए इसे किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस तरह का केंद्र स्थापित करने हेतु मंजूरी दी गई है। डेल्टा लिमिटेड नई दिल्ली में शामिल एक कंपनी है। श्री देवांश को अल्फा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड और डेल्टा लिमिटेड से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः ₹62,500, ₹87,300 और ₹21,800 का लाभांश आय हुआ है। इन शेयरों में निवेश हेतु ऋण ली गई राशि पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उनके द्वारा किया गया ब्याज व्यय क्रमशः ₹12,000, ₹20,000 और ₹7,000 है।

श्री देवांश ने 1 अप्रैल, 2021 को गिफ्ट आईएफएससी में स्थित कंपनी गामा लिमिटेड को 50 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भी ऋण दी है। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। उन्होंने 1 अप्रैल, 2022 को एसईजेड की आईएफएससी बैंकिंग इकाई में 30 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भी जमा की है। ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है। गामा लिमिटेड को फी लिमिटेड से जनवरी, 2025 में 5,41,200 रुपये का लाभांश प्राप्त होना है, जो कि गिफ्ट आईएफएससी में स्थित एक कंपनी है। जो इसे 28 जनवरी, 2025 को मिला था।

अल्फा लिमिटेड ने नि.व. 2023-24 से धारा 80ठक(1क) के तहत कटौती का लाभ उठाना शुरू कर दिया है, जबकि बीटा लिमिटेड ने लाभ उठाना शुरू नहीं किया है, जबकि इसने 1.4.2021 को परिचालन शुरू कर दिया है। अल्फा लिमिटेड ने वि.व. 2024-25 के लिए धारा 80ठक(1क)/(2) के तहत कटौती के दावे के बारे में भुगतानकर्ताओं को घोषणा प्रस्तुत की।

ऊपर दी गई जानकारी से, बहुविकल्पीय प्रश्नों 1 से 6 तक का सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- वि.व. 2024-25 के दौरान श्री देवांश की लाभांश आय पर कर देयता क्या है? अधिभार और उपकर को नज़रअंदाज़ करें।  
(क) ₹ 4,360

- (क) ₹ 15,522  
(ख) ₹ 17,160  
(ग) ₹ 19,340
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु श्री देवांशु द्वारा गामा लिमिटेड को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज आय पर कर देयता, अधिभार, यदि कोई हो, और उपकर को छोड़कर, है-
- (क) शून्य  
(ख) ₹ 25,000  
(ग) ₹ 50,000  
(घ) ₹ 1,00,000
3. नि. व. 2025-26 हेतु श्री देवांशु की एसईजेड में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में जमा राशि पर ब्याज आय पर कर देयता, अधिभार, यदि कोई हो, और उपकर को छोड़कर, है -
- (क) ₹ 12,000  
(ख) ₹ 24,000  
(ग) ₹ 48,000  
(घ) शून्य
4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फाई लिमिटेड से गामा लिमिटेड की लाभांश आय पर कर देयता क्या है, यह मानते हुए कि दोनों कंपनियां मुख्य रूप से विमान पट्टे पर देना व्यवसाय करती हैं और उन्होंने धारा 115खकक का विकल्प चुना है?
- (क) ₹ 61,913  
(ख) ₹ 1,23,827  
(ग) ₹ 1,36,209  
(घ) शून्य
5. यह मानते हुए कि, इस एमसीक्यू के प्रयोजन के लिए, अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड आईएफएससी में स्थित बैंकिंग इकाइयाँ हैं और दोनों कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20-20 लाख रुपये के बराबर प्रोफेशनल शुल्क प्राप्त होना है, दाता (पेयर) द्वारा कटौती योग्य कर कितना है?

- (क) शून्य, शून्य
- (ख) शून्य, ₹ 2 lakhs
- (ग) ₹ 2 लाख, शून्य
- (घ) ₹ 2 लाख, ₹ 2 लाख

6. यह मानते हुए कि, इस एमसीक्यू के प्रयोजन के लिए, अल्फा लिमिटेड शिपिंग बिजनेस में लगी एक अर्हक कंपनी है, वह किस तारीख तक टनधारिता कर योजना (टनज़ टैक्स स्किम) का विकल्प चुन सकती है, यदि इसकी निगमन तिथि 1.4.2022 है?

- (क) 30.6.2022
- (ख) 31.3.2032
- (ग) 30.6.2032
- (घ) 30.6.2033

#### केस परिदृश्य II

01.05.2024 को, एबीसी लिमिटेड (एक सूचीबद्ध कंपनी) ने 1:10 के अनुपात में 50 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर राइट शेयर पेश किए। शेयरधारकों में से एक, श्री साहिल के पास राइट इश्यू की पेशकश की तारीख को एबीसी लिमिटेड के 50,000 शेयर थे। उन्होंने 30% राइट्स अपने पास रखे और शेष राइट शेयर अपने मित्र, श्री जय के पक्ष में 28.05.2024 को 15 रुपये प्रति शेयर पर छोड़ दिए।

श्री साहिल ने अपने मूल शेयरों में से 10,000 शेयर 15.07.2024 को 65 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हस्तांतरित किए। उन्होंने 21.6.2021 को 2,38,000 रुपये की कीमत पर ये 10,000 शेयर हासिल किए थे। इसके अलावा, श्री जय ने श्री साहिल से हासिल किए गए शेयरों को 80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 26.02.2025 को हस्तांतरित किया।

एक्सवार्डजेड प्राइवेट लिमिटेड ने 14.12.2024 को ₹160 प्रति शेयर के मूल्य पर 80,000 शेयर पुनर्खरीद किए। ऐसे शेयर वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 20 रुपये प्रति शेयर (10 रुपये अंकित मूल्य और 10 रुपये प्रीमियम) पर जारी किए गए थे। इस तरह के पुनर्खरीद किए गए शेयरों में श्री साहिल के 6,250 शेयर (जिन्हें उन्होंने 28.5.2022 को 36.80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हासिल किया) और श्री राहुल के 250 शेयर (जो उन्हें उनके पिता से विरासत में मिले थे) शामिल हैं। राहुल के पिता ने ये शेयर 24.5.2020 को 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हासिल किए थे। इस लेन-देन के अलावा, श्री राहुल की "वेतन" मद के तहत 12,42,000 रुपये (गणना की गई) की आय है, जिस पर नियोक्ता द्वारा कोई कर नहीं काटा जाता है। मान लीजिए कि श्री साहिल की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोई अन्य आय नहीं है।

एबीसी लिमिटेड के शेयरों से संबंधित एसटीटी का भुगतान किया गया है।

ऊपर दी गई जानकारी से, एमसीक्यू 7 से 12 तक का सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

7. क्या एक्सवाइज्ड प्राइवेट लिमिटेड को शेयरों की पुनर्खरीद पर अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो ऐसे अतिरिक्त आयकर की राशि कितनी होगी?
- (क) नहीं, चूंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए इसे शेयरों की पुनर्खरीद पर अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) हां, शेयरों की पुनर्खरीद पर 26,09,152 रुपये अतिरिक्त आयकर के रूप में चुकाना आवश्यक है।
- (ग) नहीं, इसमें अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुनर्खरीद 1.10.2024 को या उसके बाद होगा।
- (घ) हां, 23,29,600 रुपये का अतिरिक्त आयकर देना होगा।
8. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान श्री साहिल को होने वाले पूंजीगत लाभ की राशि की गणना करें?
- (क) दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ 1,82,000 रुपये और अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 52,500 रुपये
- (ख) दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ 4,12,000 रुपये और अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 52,500 रुपये
- (ग) दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ 2,87,000 रुपये और अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 75,000 रुपये
- (घ) दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ 57,000 रुपये और अल्पकालीन पूंजीगत लाभ 52,500 रुपये
9. श्री साहिल पर निर्धारण वर्ष 2025-26 हेतु कर देयता की राशि की गणना करें। मान लें कि श्री साहिल धारा 115खकग के तहत कर का भुगतान कर रहे हैं।
- (क) शून्य
- (ख) ₹ 68,720
- (ग) ₹ 14,120
- (घ) ₹ 66,120

10. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु श्री जय की कर देयता की गणना करें। मान लें कि उनकी वेतन आय ₹4,25,000 (गणना की गई) है और उन्होंने डिफॉल्ट कर व्यवस्था से हटने का विकल्प चुना है।
- (क) शून्य  
 (ख) ₹ 7,020  
 (ग) ₹ 4,290  
 (घ) ₹ 6,750
11. क्या शेयरों की पुनर्खरीद से होने वाली आय श्री राहुल पर कर योग्य है? यदि हाँ, तो कितनी राशि और किस मद के अंतर्गत कर योग्य होगी?
- (क) शेयरों की पुनर्खरीद से होने वाली आय श्री राहुल पर धारा 10(34क) के आधार पर छूट प्राप्त होगी।  
 (ख) "अन्य स्रोतों से आय" मद के अंतर्गत 40,000 रुपये का लाभांश अर्जित होगा तथा 2,500 रुपये की दीर्घकालिक पूंजी हानि होगी।  
 (ग) "पूंजीगत लाभ" मद के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के रूप में 37,500 रुपये अर्जित किए।  
 (घ) ₹37,500 "अन्य स्रोतों से आय" मद के अंतर्गत लाभांश के रूप में
12. श्री राहुल द्वारा 2025-26 हेतु देय कुल आय और कर की गणना करें। मान लें कि वह धारा 115खकग के अनुसार कर का भुगतान कर रहे हैं।
- (क) कुल आय – ₹12,82,000; देय कर – ₹96,260  
 (ख) कर योग्य आय – ₹12,79,500; देय कर – ₹99,740  
 (ग) कर योग्य आय – ₹12,82,000; देय कर – ₹1,00,256  
 (घ) कर योग्य आय – ₹12,79,500; देय कर – ₹95,740
13. ग्लोबलटेक इंक., यूएसए में निगमित एक कंपनी है, जिसकी वैश्विक परिसंपत्ति 50 करोड़ रुपये और भारतीय परिसंपत्ति 25 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इसका टर्नओवर यूएस \$ में 90 करोड़ रुपये के बराबर है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित 10 बोर्ड मीटिंग में से केवल 4 भारत में आयोजित की गईं। हालांकि, कंपनी के व्यवसाय के संचालन हेतु प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक निर्णय इन बैठकों में भारत में लिए गए थे। भारतीय कंपनी इनोवेट लिमिटेड, भारत में एक परियोजना से संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु

ग्लोबलटेक इंक को तकनीकी सेवाओं के लिए अपना शुल्क बताना चाहती है। मान लें कि ऐसा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी समझौते के तहत नहीं दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्लोबलटेक इंक की आवासीय स्थिति तय करें। क्या इनोवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई तकनीकी सेवाओं के शुल्क पर कर कटौती की आवश्यकता है। यदि हाँ, तो किस दर पर (अधिभार एवं उपकर को अनदेखा करें)?

- (क) अनिवासी; तथा धारा 195 के अंतर्गत 20% की दर से कर कटौती योग्य है।
- (ख) अनिवासी; तथा धारा 195 के अंतर्गत 35% की दर से कर कटौती योग्य है।
- (ग) निवासी; तथा धारा 195 के अंतर्गत 35% कर कटौती योग्य है।
- (घ) निवासी; तथा धारा 194जे के अंतर्गत 10% की दर से कर कटौती योग्य है।

14. विनिर्माण में संलग्न एक घरेलू कंपनी तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड के लाभ व हानि का विवरण, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित मदों के डेबिट(नामे)/क्रेडिट(जमा) के बाद ₹1,07,00,000 का शुद्ध लाभ दर्शाता है।

क. लाभ व हानि विवरण में जमा (क्रेडिट):

- (i) खाली जमीन से प्राप्त किराया ₹2,55,000
- (ii) कंपनी के स्वामित्व वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी से प्राप्त किराया (सकल) ₹5,30,000 (किरायेदार द्वारा 10% की दर से कर कटौती)
- (iii) आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज ₹48,000
- (iv) प्लॉट की बिक्री पर लाभ 8,00,000 रु.
- (v) फरवरी, 2025 में एबीसी इंक, न्यूयॉर्क, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से लाभांश ₹6,00,000

ख. लाभ व हानि विवरण में नामे (डेबिट):

- (i) लाभ व हानि विवरण में लगाया गया मूल्यहास ₹11,86,000.
- (ii) स्वच्छ भारत कोष में ₹ 85,000 का दान।
- (iii) कर्मचारियों की पेंशन योजना में वास्तविक योगदान: ₹1,90,000

- (iv) ट्रांसपोर्टर को अकाउंट पेयी चेक द्वारा ₹68,000 का भुगतान किया गया, लेकिन स्रोत पर कोई कर नहीं काटा गया। (ट्रांसपोर्टर के पास पैस है और उसने घोषणा की है कि वह धारा 44कड के अंतर्गत आता है और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके पास 10 से अधिक माल गाड़ी नहीं थी)
- (v) कर्मचारियों को 4,48,000 रुपये का बोनस दिया गया। हालांकि, भुगतान 18 दिसंबर, 2025 को किया गया।
- (vi) आयकर के लिए 4,20,000 रुपये का प्रावधान (इस पर 70,000 रुपये ब्याज सहित)
- (vii) धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत अनुमोदित एवं अधिसूचित विश्वविद्यालय को 1,00,000 रुपये का अंशदान।
- (viii) एबीसी इंक, न्यूयॉर्क में शेयर खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर 1,50,000 रुपये का ब्याज

#### अतिरिक्त जानकारी:

- (1) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार मूल्यहास 18,00,000 रुपये। हालांकि, ऐसे मूल्यहास की गणना करते समय, कंप्यूटर पर लागू दर को (i) प्रिंटर और स्कैनर जैसे सहायक उपकरण तथा (ii) ईपीएबीएक्स के लिए अपनाया गया है। 01.04.2024 तक इन वस्तुओं का लिखित मूल्य नीचे दिया गया है:
  - (क) प्रिंटर और स्कैनर ₹3,00,000
  - (ख) ईपीएबीएक्स ₹5,00,000
- (2) 18 नवंबर, 2024 को ₹34,00,000 में खरीदे गए संयंत्र एवं मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार मूल्यहास की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है।
- (3) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु खाताबही में स्रोत पर कर कटौती किए बिना ₹1,00,000 की लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान किया गया था। धारा 194ज के तहत स्रोत पर कर कटौती के बाद अक्टूबर 2024 में लेखा परीक्षकों को इस शुल्क का भुगतान किया गया और इस तरह से काटा गया कर 12 दिसंबर, 2024 को जमा किया गया।

- (4) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने कच्चे माल की खरीद हेतु 90,000 रुपये के बकाया बिल का प्रावधान किया। इस बकाया राशि में से कंपनी ने 20 अगस्त, 2024 को 45,000 रुपये नकद भुगतान किया।
- (5) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 1,00,000 इक्विटी शेयर 90 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर जारी किए हैं। शेयरों के जारी होने के समय उचित बाजार मूल्य 60 रुपये प्रति शेयर है।
- (6) मार्च, 2025 में प्लॉट 58,00,000 रुपये में बेचा गया, जिसे कंपनी ने जनवरी, 2023 में 50,00,000 रुपये में अधिग्रहित किया था।
- (7) धारा 80गगघ के अंतर्गत निर्दिष्ट पेंशन योजना के लिए पात्र वेतन और महंगाई भत्ता 10,00,000 रुपये है।
- (8) कंपनी ने सितंबर, 2024 में शेयर पूंजी के 10% की दर से 5,20,000 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।
- (9) लागत मुद्रास्फीति सूचकांक - वित्त वर्ष 2022-23: 331; वित्त वर्ष 2024-25: 363
- निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए धारा 115खकक के अनुसार तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड की कुल आय और कर देयता की गणना करें, जिसमें प्रत्येक मद के प्रावधान का कारण बताएं।
15. वत्सल, विहान और वायु वीएसके एंड कंपनी में बराबर के भागीदार हैं, जिसका गठन 01.06.2024 से हुआ था। यह फर्म एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा निर्मित जूतों की अधिकृत डीलर है। इसने लाभ व हानि खाते के अनुसार निम्नलिखित मदों के डेबिट/क्रेडिट के बाद 4,50,000 रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया:
- जनरेटर और कंप्यूटर पर मूल्यहास ₹1,10,000
  - कार्यरत साझेदारों में से प्रत्येक का वेतन 82,000 रुपये प्रति माह।
  - साझेदारों को पूंजी पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। फर्म की पूंजी पर कुल ब्याज 3,60,000 रुपये लाभ व हानि खाते में डेबिट किया जाएगा।
  - पंजीकृत राजनीतिक दलों को नकद 80,000 रुपये और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा 70,000 रुपये का दान।
  - साझेदार वत्सल को उनके परिसर को गोदाम के रूप में उपयोग करने हेतु ₹36,000 प्रति माह का मासिक किराया दिया गया तथा यह 01.10.2024 से फर्म द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

परिसर का मार्केट रेंट 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। भुगतान किए गए किराए पर स्रोत पर कोई कर नहीं काटा गया।

- (vi) फर्म को शोरूम के उद्घाटन के पहले दिन ग्राहकों को दिए जाने वाले सोने के सिक्कों की लागत पर 5 लाख रुपये खर्च उठाने पड़े। प्रत्येक सोने के सिक्के की कीमत 10,000 रुपये से कम थी और उस दिन लकी झा के माध्यम से चुने गए प्रत्येक खरीदार को एक सिक्का दिया गया था। इन सिक्कों पर स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की गई।

#### अतिरिक्त जानकारी:

- (i) मूल परिसंपत्तियों पर धारा 32 के अंतर्गत मूल्य ह्रास 2,43,000 रुपये स्वीकार्य है।
- (ii) 10.07.2024 को एक पंजीकृत ट्रेडमार्क 3,00,000 रुपये में खरीदा गया। फर्म ने 01.12.2024 से ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि पिछले मालिक के विलेख को लेकर कुछ विवाद था और नवंबर 2024 में ही अदालत के आदेश में इसे मंजूरी दी गई थी।
- (iii) सभी साझेदार कार्यकारी साझेदार हैं, तथा वेतन और ब्याज साझेदारी विलेख द्वारा तय हैं।

आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु फर्म की कुल आय की गणना करनी है।

16. धारा 12कख के तहत पंजीकृत एक्सवाईजेड चैरिटेबल ट्रस्ट को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रस्ट के अंतर्गत रखी गई परिसंपत्ति से 500 लाख रुपये की आय होती है। ट्रस्ट ने एक अन्य ट्रस्ट, एबीसी एजुकेशनल ट्रस्ट को 200 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है, जो धारा 12कख के तहत पंजीकृत है।
- I. (क) एक्सवाईजेड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भुगतान की गई कितनी राशि को धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु आय के उपयोग के रूप में माना जाएगा, यदि ऐसा योगदान -
- (i) इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि इसका उपयोग सामान्य धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु किया जाएगा न कि निधि के रूप में।
- (ii) इस विशिष्ट निर्देश के साथ दिया जाता है कि यह राशि उसके कॉर्पस का हिस्सा बनेगी।
- (ख) यदि ऐसी राशि एक्सवाईजेड ट्रस्ट के संचय से भुगतान की जाती है, तो क्या उपरोक्त प्रश्नों के प्रति आपका उत्तर बदल जाएगा। यदि हाँ, तो इसके लिए अन्य कर निहितार्थ क्या होंगे?

- II. साथ ही, उन शर्तों की भी जांच करें जिन्हें एबीसी एजुकेशनल ट्रस्ट को एक्सवाईजेड चैरिटेबल ट्रस्ट से प्राप्त राशि को अपनी कुल आय में शामिल न करने हेतु पूरा करना होगा, जिसमें विशिष्ट निर्देश शामिल हैं कि इसे कॉर्पस के रूप में हिस्सा बनाया जाए। अगर ऐसी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो एबीसी एजुकेशनल ट्रस्ट पर अन्य कर निहितार्थ क्या होंगे।
17. भारतीय निवासी श्री अमित ने क्रिप्टोकॉरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) में निवेश किया।  
15 अप्रैल, 2024 को उन्होंने 60 लाख रुपये में 1 बिटकॉइन (बीटीसी) खरीदा। उनके दोस्त सुशील ने 16.8.2024 को उनके जन्मदिन पर 5 लाख रुपये के एफएमवी वाले एनएफटी (इन टोकन के हस्तांतरण से अंतर्निहित मूल्य परिसंपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता) उपहार में दिए। सुशील ने ये एनएफटी 4.5 लाख रुपये में खरीदे हैं। अमित ने भी 16.11.2024 को 10 लाख रुपये के एनएफटी खरीदे।  
कुछ वित्तीय जरूरतों के कारण, 1.12.2024 को, उन्होंने 0.5 बीटीसी को ₹ 28 लाख में बेचा और दोस्त से प्राप्त एनएफटी को ₹ 6.50 लाख में बेचा। बीटीसी और एनएफटी के हस्तांतरण पर उन्हें 0.1% का खर्च उठाना पड़ा।  
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उनकी अन्य आय 6,50,000 रुपये है।  
श्री अमित द्वारा निर्धारण वर्ष 2025-26 हेतु देय कर की गणना करें, यह मानते हुए कि उन्होंने धारा 115खकग से हटने का विकल्प चुना है।
18. पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान, अनिवासी भारतीय श्री विवेक, एक साझेदारी फर्म मेसर्स पाल एंड कंपनी का भारत में भागीदार बने और पूंजी हेतु 50 लाख रुपये का योगदान दिया। साझेदारी विलेख की शर्तों के अनुसार, उन्हें पूंजी पर ब्याज के रूप में 10% की दर से ब्याज और फर्म द्वारा हर साल उनके लाभ का हिस्सा दिया गया। वि.व. 2024-25 में, उनका लाभ हिस्सा 4 लाख रुपये था। वि.व. 2024-25 के दौरान, फर्म ने भारत में एक परियोजना हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी सेवाओं (एफटीएस) के शुल्क के लिए श्री विवेक के मित्र श्री विकास (एक अनिवासी) को 5 लाख रुपये का भुगतान किया। श्री विवेक और श्री विकास दोनों देश एक्स के निवासी हैं।
- (i) मेसर्स पाल एंड कंपनी, भारत के कर सलाहकार के रूप में, आपको श्री विवेक को किए गए भुगतानों (अर्थात्, पूंजी पर ब्याज व लाभ का हिस्सा) पर स्रोत पर कर कटौती और श्री विवेक को एफटीएस भुगतान के बारे में फर्म को सलाह देनी है, यह देखते हुए कि भारत का देश 'एक्स' के साथ कोई डीटीएए नहीं है। यदि स्रोत पर कर कटौती योग्य नहीं है, तो क्या फर्म द्वारा अनुपालन की जाने वाली कोई अन्य संबंधित आवश्यकता है?

(ii) यदि भारत का देश 'एक्स' के साथ डीटीए है, जो एफटीएस के संबंध में 10% की दर से कर कटौती का प्रावधान करता है, तो यदि मेसर्स पाल एंड कंपनी, भारत ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अपेक्षित दर पर कर कटौती की है, तो क्या उपाय उपलब्ध है?

19. श्री भुवन अपने व्यवसाय हेतु श्री श्रीनिवास से कुछ कच्चा माल खरीदना चाहते हैं। उत्पादों की कमी को देखते हुए, श्रीनिवास खरीद हेतु नकद भुगतान करने पर जोर देते हैं, जिस पर भुवन सहमत हो जाते हैं। 27-3-2025 को, ₹3,20,000 के नकद चालान के माध्यम से खरीद हो जाती है।

उपरोक्त लेन-देन के संबंध में, क्या आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत भुवन और श्रीनिवास पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? संक्षेप में समझाएँ।

यदि क्रेता भुवन द्वारा दो अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग कच्चे माल की नकद खरीद क्रमशः ₹1,80,000 तथा ₹1,40,000 में की जाए, तो क्या आपका उत्तर भिन्न होगा?

20. 61 वर्षीय श्रीमती सुधा शर्मा विवाहित हैं और कलकत्ता में बस गई हैं। वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और संगीतकार हैं जो भारत तथा देश एम में संगीत कार्यक्रम करती हैं। वह हर साल अक्टूबर में संगीत सत्र के दौरान देश एम में आयोजित संगीत समारोह में भाग लेने हेतु आती हैं। शेष वर्ष के लिए, वह भारत में संगीत कार्यक्रम करती हैं।

आयोजित संगीत समारोहों से आय -

भारत में - ₹10 लाख

देश एम में - सीएनडी 12,245

अक्टूबर, 2024 में देश एम में उसके द्वारा अर्जित आय के संबंध में काटा गया कर 2500 सीएनडी था।

वह देश एम में अपनी म्यूज़िक कंपोजिशन के कॉपीराइट के संबंध में रॉयल्टी के रूप में सीएनडी 10000 की आय अर्जित करती हैं। रॉयल्टी का भुगतान उन्हें हर साल 25 मार्च को 10% कर की कटौती के बाद किया जाता है।

भारत में, उसके नाम पर बैंक सावधि जमा से 4 लाख रुपये और बचत बैंक खाते से 25,000 रुपये की ब्याज आय है। वह अपने स्वास्थ्य हेतु 27,000 रुपये का चिकित्सा बीमा प्रीमियम अदा करती हैं तथा अपने 64 वर्षीय पति के स्वास्थ्य

हेतु 30,000 रुपये का प्रीमियम अदा करती हैं। उन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.50 लाख रुपए और अपने बेटे श्री साहिल के नाम पर पांच साल की सावधि जमा में 3 लाख रुपए जमा करवाए हैं।

रूपांतरण दरें इस प्रकार हैं -

टीटी क्रय दर	30.9.2024	31.10.2024	28.2.2025	31.3.2025
देश एम डॉलर (सीएमडी)	₹ 80	₹ 84	₹ 78	₹ 80
देश एन डॉलर (सीएनडी)	₹ 80	₹ 82	₹ 78	₹ 79

भारत का देश एम के साथ कोई दोहरा कराधान परिहार समझौता नहीं है, लेकिन देश एन के साथ इसका डीटीए है।

### “भारत - देश एन” के बीच डीटीए के प्रासंगिक अंश

#### अनुच्छेद 12

#### तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली सम्मिलित सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान किए जाते हैं, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

#### अनुच्छेद 23

#### दोहरे कराधान का उन्मूलन

3. देश एन के कानूनों के तहत और समझौते के प्रावधानों के अनुसार, भारत के निवासी द्वारा देश एन के भीतर स्रोतों से आय के संबंध में, जो भारत और देश एन दोनों में कर के अधीन है, सीधे या कटौती के माध्यम से भुगतान किए गए कर की राशि को ऐसी आय के संबंध में देय भारतीय कर के विरुद्ध क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह राशि भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी जो ऐसी आय भारतीय कर हेतु प्रभार्य संपूर्ण आय का है।

यदि श्रीमती सुधा शर्मा ने डिफॉल्ट कर व्यवस्था से हटने का विकल्प चुना है, तो निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए उनकी कुल आय और शुद्ध कर देयता (विदेशी कर क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए) की गणना करें।

21. मनन जो देश एक्स में रहे, 1 फरवरी 2024 को स्थायी रूप से भारत लौट आए। उनके पास देश एक्स में एक घर यानी परिसंपत्ति है, जिससे उन्होंने 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः देश एक्स \$30,000 और देश एक्स \$34,000 की किराया आय अर्जित की और प्राप्त की,

जो देश एक्स में खोले गए बैंक खाते में जमा है। देश एक्स में खोले गए बैंक खाते में क्रमशः 18,200 डॉलर की मूल छूट सीमा हेतु पात्र है और शेष आय पर, उन्होंने देश एक्स में दोनों वर्षों के लिए 20% की दर से आयकर का भुगतान किया। देश एक्स में अर्जित आय पर किराए पर दी गई परिसंपत्ति के लिए कर का भुगतान क्रमशः 5 अप्रैल 2024 और 10 अप्रैल 2025 को भारत में उसके बैंक खाते से किया गया। 31-03-2025 को समाप्त वर्ष हेतु भारत में स्थित व्यवसाय से उनकी आय 12,50,000 रुपये है।

उन्होंने 23.12.2024 को इंदौर स्थित भूमि श्री सार्थक को ₹80,00,000 में हस्तांतरित की, जिसे उन्होंने 18.5.2022 को ₹30 लाख में अधिग्रहित किया था।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक - वित्तीय वर्ष 2022-23: 331; वित्तीय वर्ष 2024-25: 363  
विभिन्न तिथियों पर देश एक्स के 1 डॉलर की विनिमय दर नीचे दी गई है:

31 मार्च 2024 = ₹80; 05 अप्रैल 2024 = ₹80.50; 31 दिसंबर 2024 = ₹81;

31 मार्च 2025 = ₹82; 10 अप्रैल 2025 = ₹81.50 और 31 दिसंबर 2025 = ₹83

डिफॉल्ट कर व्यवस्था के तहत निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए भारत में मनन की कर देयता की गणना करें।

22. त्रिवेणी सीमेंट लिमिटेड (टीसीएल) एक भारतीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, इसने कुछ संस्थाओं और इन कंपनियों के साथ किए गए लेन-देन की निम्नलिखित जानकारी दी है:

- ट्रिफ्ट इंक. जापान में टीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी है। यह वर्तमान में टीसीएल को तकनीकी जानकारी की आपूर्ति हेतु प्रति वर्ष 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रॉयल्टी का भुगतान कर रही है। जापान में पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी एलीट एलएलसी को तकनीकी जानकारी की इसी तरह की आपूर्ति के लिए टीसीएल को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक रॉयल्टी मिलती है। (1 अमेरिकी डॉलर = 82 रुपये)
- टीसीएल ने 1.4.2024 को स्विफ्ट इंक., दुबई से 220 करोड़ रुपये के बराबर की राशि ऋण ली है। इस तिथि पर, टीसीएल की परिसंपत्ति की स्थिति निम्नानुसार थी:

परिसंपत्तियों का प्रकार	(₹ करोड़ में)	
	बाजार मूल्य	बुक वैल्यू
मूर्त अचल परिसंपत्तियां	350	270
अमूर्त परिसंपत्तियां	30	25
अन्य परिसंपत्तियां	40	35

स्विफ्ट इंक. ने 8% की दर से ब्याज लिया है और टीसीएल ने 31.3.2025 को समाप्त वर्ष हेतु 17.6 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाया है। हालाँकि स्विफ्ट इंक. की सामान्य ऋण दर अन्य पक्षों के लिए 7% प्रति वर्ष थी, लेकिन धन की तत्काल आवश्यकता और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, टीसीएल ने उस समय यह राशि ऋण लेने का फैसला किया।

- टीसीएल सिंगापुर में टू वर्ड्स लिमिटेड (टीडब्ल्यूएल) को माल की आपूर्ति करता है। विदेशी मुद्रा के समतुल्य टीडब्ल्यूएल की चुकता पूंजी 92 करोड़ रुपये है। टीसीएल के पास टीडब्ल्यूएल में 22 करोड़ रुपये के शेयर हैं। कंपनी में वोटिंग पावर सीधे तौर पर रखे गए शेयरों की संख्या के समानुपातिक है।

आपको टीसीएल द्वारा किए गए विभिन्न लेन-देन की जांच करनी है और प्रत्येक लेन-देन के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधानों की प्रयोज्यता निर्धारित करनी है। इस मामले में, यदि लागू हो, तो धारा 94ख के प्रावधानों को अनदेखा करें।



### सुझाए गए उत्तर

एमसीक्यू सं.	सबसे उपयुक्त उत्तर	एमसीक्यू सं.	सबसे उपयुक्त उत्तर
1.	(घ)	8.	(क)
2.	(क)	9.	(घ)
3.	(घ)	10.	(ख)
4.	(घ)	11.	(ख)
5.	(ख)	12.	(क)
6.	(ग)	13.	(ग)
7.	(ग)		

14. वर्ष 2025-26 के लिए धारा 115खकक के अनुसार तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड की कुल आय एवं कर देयता की गणना

	विवरण	राशि (₹)	
I	घर परिसंपत्ति से आय [कमर्शियल परिसंपत्ति से किराये की आय] सकल वार्षिक मूल्य <sup>1</sup> /शुद्ध वार्षिक मूल्य घटाएँ: धारा 24(क) के तहत कटौती शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%	5,30,000	3,71,000
		1,59,000	
II	व्यवसाय और प्रोफेस से होने वाले लाभ एवं प्राप्त लाभ व हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ जोड़ें: डेबिट की गई मदें लेकिन अलग से विचार की जानी चाहिए या अस्वीकृत की जानी चाहिए	1,07,00,000	
	ख(ii) स्वच्छ भारत कोष को दिया गया दान [पूरी तरह से और विशेष रूप से विनिर्माण व्यवसाय हेतु किया गया व्यय नहीं। इसलिए, धारा 37 के तहत स्वीकार्य नहीं है]	85,000	
	ख(iii) कर्मचारियों की पेंशन योजना में अंशदान [धारा 80गघ में उल्लिखित पेंशन योजना हेतु कर्मचारियों को अंशदान केवल वित्तीय वर्ष में कर्मचारी के वेतन के 14% की सीमा तक की अनुमति है, अर्थात् 1,40,000 रुपये, जो 10,00,000 रुपये का 14% है। इसलिए, 50,000 रुपये [अर्थात् 1,90,000 रुपये - 1,40,000 रुपये] का अतिरिक्त अंशदान धारा 36(1)(ivक) के तहत अस्वीकृत है।	50,000	
	ख(iv) ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान [धारा 194ग(6) के अनुसार, स्रोत पर कोई कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है]	-	

<sup>1</sup> नगरपालिका मूल्य, उचित किराया और मानक किराया से संबंधित जानकारी के अभाव में प्राप्त किराया को सकल वार्षिक मूल्य (जीएवी) के रूप में माना गया है।

<p>क्योंकि भुगतान एक ट्रांसपोर्ट कंट्रैक्टर को किया जाता है जिसके पास पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 10 से अधिक माल गाड़ियां नहीं थीं और उसने अपने पैन के साथ इस आशय की घोषणा भी की है। इसलिए, स्रोत पर कर की कटौती न करने हेतु धारा 40(क)(ढक) के तहत अस्वीकृति लागू नहीं होती है। साथ ही, चूंकि भुगतान अकाउंट पेयी चेक द्वारा किया जाता है, इसलिए धारा 40क(3) के तहत कोई अस्वीकृति लागू नहीं होती है]</p>	4,48,000		
<p><b>ख(v) कर्मचारियों को बोनस</b> [चूंकि भुगतान आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि के बाद किया जाता है, इसलिए धारा 43ख के तहत अस्वीकृति लागू होती है]</p>	4,20,000		
<p><b>ख(vi) आयकर के लिए प्रावधान (इस पर 70,000 रुपये के ब्याज सहित)</b> [कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। धारा 40(क)(ii) के तहत अस्वीकृति लागू होती है]</p>	1,00,000		
<p><b>ख(vii) धारा 35(1)(ii) के तहत अनुमोदित और अधिसूचित विश्वविद्यालय में योगदान धारा 35(1)(ii) के तहत अनुमोदित और अधिसूचित विश्वविद्यालय में योगदान के संबंध में धारा 115खकक के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं है।</b></p>	1,50,000	12,53,000	
<p><b>ख(viii) एबीसी इंक के शेयरों में निवेश करने के लिए ऋण लिए गए ऋण पर ब्याज</b> [लाभांश अर्जित करने पर ब्याज व्यय की अनुमति या अन्यथा को “अन्य स्रोतों से आय” मद के तहत अलग से विचार किया जाना चाहिए]</p>			1,19,53,000
<p><b>जोड़ें: कच्चे माल की खरीद हेतु किए गए नकद भुगतान को आय माना जाएगा</b> कड(4) [चूंकि कच्चे माल की खरीद के</p>		45,000	

<p>लिए बकाया बिल के प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कटौती के रूप में अनुमति दी गई है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऐसे बिल के विरुद्ध 10,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान धारा 40क(3क) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय माना जाएगा।]</p> <p><b>घटाएँ: अनुमत व्यय</b></p> <p>ख(i) और कढ(1) मूल्यहास</p> <p>[आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार 16.75 लाख रुपये के सामान्य मूल्यहास <b>[नीचे टिप्पणी देखें]</b> और 11.86 लाख रुपये के लाभ और हानि विवरण पर लगाए गए मूल्यहास के बीच अंतर]</p> <p><b>टिप्पणी</b> - <sup>2</sup>प्रिंटर एवं स्कैनर कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं और इनका उपयोग कंप्यूटर के बिना नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, वे कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा हैं, वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटरों पर लागू 40% की उच्च दर पर मूल्यहास के लिए पात्र होंगे। हालाँकि, ईपीएबीएक्स एक कंप्यूटर नहीं है और इसलिए, यह 40% की दर से उच्च मूल्यहास नहीं लगाया जाएगा। तदनुसार, पीएबीएक्स पर 25% (40% - 15%) की दर से गणना की गई 1,25,000 रुपये की मूल्यहास राशि को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार दिए गए 18 लाख रुपये के मूल्यहास से घटाया जाना है। इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कटौती के रूप में दी गई मूल्यहास राशि 16.75 लाख रुपये होगी।</p> <p><b>कढ(2) नए संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास</b></p>	4,89,000	1,19,98,000	
	शून्य		

<sup>2</sup> सीआईटी बनाम बीएसईएस यमुना पॉवर्स लिमिटेड (2013) 358 आईटीआर 47 (दिल्ली)

<sup>3</sup> फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम एसीआईटी (2011) 332 आईटीआर 319 (केरल)

[धारा 115खकक के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं]			
<b>कढ़(3) वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित लेखा परीक्षा शुल्क</b>	30,000	<u>5,19,000</u>	
[वित्त वर्ष 2023-24 की लेखाबही में दिए गए 1,00,000 रुपये के लेखा परीक्षा शुल्क का 30% होने के नाते 30,000 रुपये की राशि स्रोत पर कर की कटौती न किए जाने के कारण अस्वीकृत कर दी गई होगी। चूंकि कर अक्टूबर, 2024 में काटा गया है और 12.12.2024 को भुगतान किया गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की व्यावसायिक आय की गणना करते समय 30,000 रुपये की राशि कटौती योग्य है।]		1,14,79,000	
<b>घटाएँ: लाभ व हानि के विवरण में जमा की गई मर्दे, लेकिन व्यावसायिक आय में शामिल नहीं की गई</b>	5,30,000		
क(i) खाली जमीन से प्राप्त किराया [मद "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत कर योग्य]	48,000		
क(ii) कंपनी के स्वामित्व वाली वाणिज्यिक परिसंपत्ति से प्राप्त किराया [मद "घर की परिसंपत्ति से आय" के अंतर्गत कर योग्य]	8,00,000		
क(iii) आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज [मद "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत कर योग्य]	6,00,000	<u>22,33,000</u>	
क(iv) प्लॉट की बिक्री पर लाभ [मद "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत कर योग्य]		92,46,000	
क(v) एबीसी इंक. कंपनी से लाभांश [विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश मद "अन्य स्रोतों से आय" के अंतर्गत कर योग्य है]			<b>92,46,000</b>
<b>विनिर्माण व्यवसाय से लाभ एवं मुनाफा</b>			

III	<b>पूंजीगत लाभ</b> <b>प्लॉट की बिक्री पर पूंजीगत लाभ</b> बिक्री प्रतिफल घटाएँ: अधिग्रहण की लागत [चूँकि भूमि 23.7.2024 को या उसके बाद हस्तांतरित की जाती है, इसलिए भारत में निवासी किसी व्यक्ति या एचयूएफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सूचीकरण लाभ नहीं मिलेगा]	58,00,000 <u>50,00,000</u>	
	<b>दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ</b>		8,00,000
IV	<b>अन्य स्रोतों से आय</b> खाली जमीन से प्राप्त किराया आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज शेयरों के उचित बाजार मूल्य से शेयरों के निर्गम मूल्य की अधिकता पर वित्तीय वर्ष 2025-26 से कर नहीं लगेगा विदेशी कंपनी एबीसी इंक से लाभांश घटाएँ: 1,50,000 रुपये का ब्याज व्यय, लाभांश के 20% तक कटौती की अनुमति	2,55,000 48,000 - 6,00,000 1,20,000 4,80,000	
	<b>सकल कुल आय</b> घटाएँ: खंड VI-क के अंतर्गत कटौती		<u>7,83,000</u> <b>1,12,00,000</b>
	<b>धारा 80छ के अंतर्गत कटौती</b> धारा 115खकक के अंतर्गत अनुमेय नहीं <b>धारा 80छ के अंतर्गत कटौती</b> अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में 5,20,000 रुपये की सीमा तक कटौती, जो धारा 139(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत तिथि से एक महीने पहले उसके द्वारा वितरित लाभांश है या सकल कुल आय में शामिल किए जाने योग्य सीमा तक प्राप्त 4,80,000 रुपये का लाभांश, जो भी कम हो	- 4,80,000	
	<b>कुल आय</b>		<u>4,80,000</u> <b>1,07,20,000</b>
	<b>कर देयता की गणना</b> दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर 12.5% की दर से कर अन्य आय पर 99,20,000 रुपये पर 22% की दर से कर		1,00,000 <u>21,82,400</u> <b>22,82,400</b>

जोड़ें: 10% पर अधिभार	2,28,240
	<u>25,10,640</u>
जोड़ें: 4% पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कर देयता (पूर्णांकित)	<u>1,00,426</u>
कर देयता	<u>26,11,066</u>
	26,11,070

15. 15. आयकर अधिनियम, 1961 के नियमित प्रावधानों को लागू करते हुए निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए फर्म, वीएसके एंड कंपनी की कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
लाभ व हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		4,50,000
जोड़ें: लाभ व हानि खाते में डेबिट किया गया व्यय लेकिन कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है या अलग से विचार नहीं किया जाना चाहिए		
- खाताबही के अनुसार मूल्यहास	1,10,000	
- कार्यरत भागीदारों को अलग से भुगतान किया गया वेतन [₹82,000 x 3 भागीदार x 10 महीने]	24,60,000	
- साझेदारों को दी गई पूंजी पर 12% से अधिक ब्याज की अनुमति नहीं है। तदनुसार, ₹1,20,000 [₹3,60,000 - ₹2,40,000 (₹3,60,000 x 12/18)], की अनुमति नहीं है।	1,20,000	
- पंजीकृत राजनीतिक दल को दान [किसी राजनीतिक दल को दिया गया दान धार 37 के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय नहीं है क्योंकि यह पूर्णतः या विशेष रूप से व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए नहीं है]	1,50,000	
- किसी साझेदार को दिया गया अतिरिक्त किराया धारा 40क(2) के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाएगा, क्योंकि साझेदार फर्म का संबंधित व्यक्ति है [(₹36,000 - ₹15,000) x 6]	1,26,000	
[स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए कोई अस्वीकृति नहीं दी जाएगी,		

क्योंकि किराये की राशि 2,40,000 रुपये से अधिक नहीं है]		
- ग्राहकों को दिए गए सोने के सिक्कों पर व्यय [धारा 37 के तहत व्यय के रूप में स्वीकृत। धारा 194आर के तहत टीडीएस नहीं काटा जाता है क्योंकि प्रत्येक ग्राहक को दिए गए सोने के सिक्के का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक नहीं है, इसलिए स्रोत पर कर की कटौती न करने हेतु कोई अस्वीकृति नहीं दी जाएगी,]	शून्य	<u>29,66,000</u>
		34,16,000
घटाएँ: आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार मूल्यहास		
- मूर्त परिसंपत्ति	2,43,000	
- अमूर्त परिसंपत्ति-पंजीकृत ट्रेडमार्क [₹3,00,000 x 12.5%] [25% का 50%, कटौती के रूप में स्वीकार्य मूल्यहास है, क्योंकि परिसंपत्ति अधिग्रहण के वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम समय के लिए उपयोग में लाई गई है]	<u>37,500</u>	<u>2,80,500</u>
		31,35,500
<b>बही लाभ</b>		
घटाएँ: कार्यरत साझेदारों को वेतन:		
(i) निर्धारित सीमा के अनुसार पहले ₹ 6,00,000 पर 90% या ₹3,00,000, जो भी अधिक हो	5,40,000	
शेष ₹ 25,35,500 पर 60%	<u>15,21,300</u>	
	20,61,300	
(ii) वास्तव में भुगतान किया गया वेतन	24,60,000	
कटौती की अनुमति (i) या (ii) जो भी कम हो		<u>20,61,300</u>
<b>व्यवसाय या पेशे से लाभ व प्राप्य</b>		<u>10,74,200</u>

सकल कुल आय		10,74,200
<b>घटाएँ: खंड VI-क के अंतर्गत कटौती</b>		
धारा 80छछग के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया गया दान	शून्य	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• नकद भुगतान स्वीकार्य नहीं है</li> <li>• इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा भुगतान किए गए 70,000 रुपये की राशि पर कटौती की अनुमति होगी, क्योंकि भुगतान नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाता है।</li> </ul>	70,000	70,000
<b>कुल आय</b>		<b>10,04,200</b>

16. (I) (क) (i) धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 4(iii) के अनुसार, एबीसी एजुकेशनल ट्रस्ट को भुगतान की गई राशि (कॉर्पस के अलावा) का केवल 85% ही आय के रूप में माना जाता है। तदनुसार, 170 लाख रुपये को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय के रूप में माना जाएगा।

(ii) धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, एक ट्रस्ट द्वारा किसी अन्य ट्रस्ट या संस्था को किया गया कोई भी योगदान (भले ही वह धारा 12कख या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत पंजीकृत हो) इस निर्देश के साथ कि ऐसी राशि कॉर्पस का हिस्सा बनेगी, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय के उपयोग के रूप में नहीं माना जाता है।

इसलिए, कोष के लिए दिए गए 200 लाख रुपये को एक्सवाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ख) जहां धारा 12कख के तहत स्वीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत पंजीकृत किसी अन्य ट्रस्ट को दिए गए योगदान की कोई राशि संचय से बाहर है, तो ऐसी राशि आवेदन के लिए योग्य नहीं होगी और दोनों मामलों में धारा 11(3) के आधार पर आय मानी जाएगी। इसके अलावा, ऐसी राशि धारा 115BBI के तहत निर्दिष्ट आय की परिभाषा के अंतर्गत आएगी और 30% की दर से कर योग्य होगी।

(II) धारा 11(1)(घ) के अनुसार, किसी फंड/ट्रस्ट/संस्था आदि द्वारा प्राप्त राशि कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, यदि ऐसी राशि इस विशिष्ट निर्देश के साथ प्राप्त की जाती है कि यह कॉर्पस का हिस्सा बनेगी और उक्त कॉर्पस अंशदान को धारा 11(5) के तहत निर्दिष्ट किसी भी तरीके से निवेश किया जाता है।

हालाँकि, यदि इसे धारा 11(5) के तहत निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य तरीके से निवेश किया जाता है, तो धारा 115खखझ के आधार पर इसे निर्दिष्ट आय माना जाएगा और 30% की दर से कर योग्य होगा।

17. श्री अमित द्वारा निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए देय कर

विवरण	राशि ₹ में	राशि ₹ में
<b>बिटकॉइन की बिक्री पर</b>		
बिक्री प्रतिफल	28,00,000	
घटाएँ: अधिग्रहण की लागत [₹60 लाख/2]	<u>30,00,000</u>	
[वीडीए के हस्तांतरण पर व्यय कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है]		
वीडीए के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं है	(2,00,000)	
<b>एनएफटी की बिक्री पर</b>		
बिक्री प्रतिफल	6,50,000	
घटाएँ: अधिग्रहण की लागत [16.8.2024 को एनएफटी का एफएमवी, जो उपहार प्राप्त करने की तिथि है]	<u>5,00,000</u>	
[वीडीए के हस्तांतरण पर व्यय कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है]		1,50,000
<b>श्री सुशील से प्राप्त उपहार</b>		
कर योग्य [चूँकि 16.8.2024 को एनएफटी का एफएमवी ₹50,000 से अधिक है]	5,00,000	
अन्य आय	<u>6,50,000</u>	11,50,000
<b>कुल आय</b>		<b>13,00,000</b>
₹11,50,000 की अन्य आय पर कर [₹1,12,500 प्लस ₹45,000 @ ₹1,50,000 का 30%]		1,57,500

वीडीए आय के हस्तांतरण से प्राप्त आय पर 1,50,000 रुपये @30% कर		<u>45,000</u>
स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @4%		<u>2,02,500</u>
		<u>8,100</u>
		<u>2,10,600</u>
घटाएँ: धारा 194क के तहत टीडीएस [₹28 लाख x 1% + ₹6.50 लाख x 1%]		<u>34,500</u>
<b>देय शुद्ध कर</b>		1,76,100

18. (i) धारा 194क के तहत, किसी निवासी को जमा या भुगतान की गई प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज के रूप में किसी भी आय पर स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता होती है, जो किसी फर्म द्वारा अपने साझेदार को जमा या भुगतान की गई आय को इसके दायरे से बाहर है। हालांकि, धारा 195, जो गैर-निवासियों को भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती को आवश्यक करती है, फर्म द्वारा अपने गैर-निवासी साझेदार को ब्याज के भुगतान के संबंध में किसी भी बहिष्करण का प्रावधान नहीं करती है। इसके अलावा, चूंकि एफटीएस को भारत में किसी परियोजना के लिए सेवाओं के उपयोग के कारण भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है और श्री विकास पर कर योग्य है, इसलिए एफटीएस भुगतान पर टीडीएस भी काटा जाना आवश्यक है। तदनुसार, धारा 195 के तहत 30% की दर से कर काटा जाना चाहिए और एचईसी @4% पूंजी और एफटीएस पर ब्याज है (यह मानते हुए कि यह केंद्र सरकार के समझौते के अनुसरण में नहीं है) पर लागू दर।

धारा 10(2क) के अनुसार, फर्म की कुल आय में से साझेदार द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा कर से मुक्त है। इसलिए, अनिवासी भारतीय को भुगतान किया गया लाभ का हिस्सा स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है।

हालांकि, धारा 195(6) में यह प्रावधान है कि किसी गैर-कॉर्पोरेट अनिवासी या किसी विदेशी कंपनी को कोई राशि, चाहे वह कर योग्य हो या न हो, का भुगतान करने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति को नियम 37खख के तहत निर्धारित प्रपत्र और तरीके से ऐसी राशि के भुगतान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

- (ii) धारा 239क के अनुसार, जहां डीटीए के तहत, धारा 195 के तहत ब्याज के अलावा किसी भी आय पर कटौती योग्य कर उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय देय है, और ऐसा व्यक्ति केंद्र सरकार

के खाते में ऐसे कर का भुगतान करने के बाद दावा करता है कि ऐसी आय पर कोई कर काटने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा व्यक्ति ऐसे कर के भुगतान की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे कर के रिफंड के लिए मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है।

इस मामले में, पाल एंड कंपनी को ऐसे कर के भुगतान की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर रिफंड के लिए मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करना होगा।

सीबीडीटी ने 27.9.2011 के परिपत्र संख्या 11/2007 के माध्यम से 23.10.2007 के परिपत्र संख्या 7/2007 को संशोधित किया है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के तहत स्रोत पर कर कटौती के रिफंड की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जो किसी अनिवासी को किए गए भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। उक्त परिपत्र ने धारा 195 के तहत भुगतान करने वाले व्यक्ति को *अन्य बातों के साथ-साथ*, तब भी पैसे की रिफंड की अनुमति दी, जब आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उच्च दर पर कर का भुगतान होता है, जबकि भारत द्वारा की गई प्रासंगिक दोहरे कराधान परिहार संधि में कम दर निर्धारित की गई है।

इसलिए, मेसर्स पाल एंड कंपनी, भारत धारा 195 के तहत स्रोत पर काटे गए अतिरिक्त कर की टैक्स रिफंड का दावा कर सकता है, जहां आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 30% की दर से स्रोत पर कर काटा गया है, जबकि देश 'एक्स' के साथ डीटीएए के तहत कम दर यानी 10% निर्धारित है, केवल तभी जब पाल एंड कंपनी ने कर वहन किया हो। अन्यथा, अनिवासी, श्री विकास द्वारा रिफंड का दावा किया जा सकता है।

19. (1) **जहां खरीद 3,20,000 रुपये के नकद चालान के माध्यम से की जाती है**

(i) **श्री भुवन पर**

चूँकि श्री भुवन अपने व्यवसाय हेतु श्री श्रीनिवास से कच्चा माल खरीदने के लिए 3,20,000 रुपये का नकद भुगतान कर रहे हैं, इसलिए धारा 40क(3) के तहत अस्वीकृति लागू होगी, क्योंकि अकाउंट पेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से ईसीएस के उपयोग या किसी अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक तरीके से

किसी व्यक्ति को एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता है। तदनुसार, उनकी व्यावसायिक आय की गणना करते समय 3,20,000 रुपये की कटौती स्वीकार्य नहीं होगी।

(ii) श्री श्रीनिवास पर

धारा 269धन, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी व्यक्ति से एक दिन में कुल मिलाकर 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त करने पर रोक लगाती है, सिवाय अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से ईसीएस के उपयोग या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति धारा 269धन के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई राशि प्राप्त करता है, तो उसे धारा 271घक के तहत ऐसी प्राप्ति की राशि के बराबर राशि का जुर्माना देना होगा।

इस मामले में, चूंकि श्रीनिवास ने 27.3.2025 को श्री भुवन से नकद के रूप में ₹3,20,000 प्राप्त किए हैं, इसलिए उन्होंने धारा 269धन के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, और इसलिए, धारा 271घक के तहत ₹3,20,000 का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

(2) जहां दो अलग-अलग तारीखों पर विभिन्न कच्चे माल के संबंध में ₹1,80,000 और ₹1,40,000 की नकद खरीद की जाती है

(i) श्री भुवन पर

भले ही श्री भुवन द्वारा अलग-अलग कच्चे माल हेतु दो अलग-अलग तारीखों पर 1,80,000 रुपये और 1,40,000 रुपये का नकद भुगतान किया गया हो, धारा 40क(3) के तहत अस्वीकृति लागू होगी, क्योंकि श्री श्रीनिवास को एक दिन में नकद भुगतान 10,000 रुपये से अधिक है।

(ii) श्री श्रीनिवास पर

अलग-अलग कच्चे माल की खरीद हेतु दो अलग-अलग तारीखों पर 1,80,000 रुपये और 1,40,000 रुपये की नकदी मिलती है, तो धारा 269धन का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि एक दिन की प्राप्ति 2 लाख रुपये से कम है और ये रसीदें एक ही लेन-देन के संबंध में नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग कच्चे माल की खरीद हेतु हैं। इसलिए, धारा 271घक का प्रावधान लागू नहीं होगा।

20. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए श्रीमती सुधा शर्मा की शुद्ध कर देयता की गणना

विवरण	₹	₹
<b>व्यवसाय या प्रोफेशन से लाभ और प्राप्य</b>		
भारत में आयोजित संगीत कार्यक्रमों से	10,00,000	
देश एन से प्राप्त रॉयल्टी से [सीएनडी 10000 x 79 (31.3.2025 तक रूपांतरण दर - नियम 115)]	7,90,000	
देश एम में आयोजित संगीत कार्यक्रमों से [सीएनडी 12,245 x 80 (31.3.2025 तक रूपांतरण दर - नियम 115)]	<u>9,79,600</u>	27,69,600
<b>अन्य स्रोतों से आय</b>		
उसके नाम पर बैंक सावधि जमा से आय	4,00,000	
बचत बैंक खाते से आय	<u>25,000</u>	<u>4,25,000</u>
<b>सकल कुल आय</b>		<b>31,94,600</b>
<b>घटाएँ: धारा 80ग के तहत कटौती</b>		
- पीपीएफ में जमा राशि	1,50,000	
- अपने बेटे के नाम पर पांच साल की सावधि जमा राशि (धारा 80ग के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है)	-	
<b>धारा 80घ के तहत</b>	50,000	
- अपने और अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम ('57,000, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम स्वीकार्य राशि '50,000 तक सीमित है)		

<b>धारा 80ननख के तहत</b>		
- बैंक एफडी और बचत बैंक खाते पर ब्याज सीमित	<u>50,000</u>	<u>2,50,000</u>
<b>कुल आय</b>		<b>29,44,600</b>
कुल आय पर कर		
आयकर [₹1,10,000 (₹10,00,000 तक) प्लस ₹5,83,380 @ ₹19,44,600 का 30%]		6,93,380
जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4%		<u>27,735</u>
		<b>7,21,115</b>
भारत में कर की औसत दर (अर्थात्, ₹7,21,115/₹29,44,600 × 100)	24.489%	
<b>विदेशी टैक्स क्रेडिट</b>		
पेशे से आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत देय कर और ऐसी आय पर देय विदेशी कर में से कम		
<b>भारत-देश एन डीटीए के तहत कवर किया गया कर:</b>	78,000	
[₹1,93,463 (अर्थात्, 24.489% × ₹7,90,000) और ₹78,000 (₹78, नियम 128 x सीएनडी 1000 के अनुसार 28.2.2025 को रूपांतरण दर है) में से कम]		
<b>देश एम में भुगतान किया गया कर:</b>		
देश एम [₹2,39,894 (यानी, 24.489% × ₹9,79,600) और ₹2,00,000 (₹80, नियम 128 x सीएमडी 2500 के अनुसार 30.9.2024 को रूपांतरण दर) में से कम]	2,00,000	
		<u>2,78,000</u>
<b>शुद्ध कर देयता (₹7,21,115 - ₹2,78,000)</b>		<u>4,43,115</u>
<b>शुद्ध कर देयता (पूर्णांकित)</b>		<b>4,43,120</b>

**टिप्पणी** - नियम 115 के अनुसार, श्रीमती सुधा शर्मा की पेशे से आय की गणना करने के लिए, 31.3.2025 तक टीटी क्रय दर पर विचार किया जाना चाहिए। देश एन से रॉयल्टी आय और देश एम में संगीत कार्यक्रमों से आय उनके पेशे से होने वाली आय है, क्योंकि वह एक गायिका और संगीतकार हैं।

नियम 128 के अनुसार, विदेशी कर क्रेडिट की गणना के लिए, उस देश में कर कटौती या भुगतान किए गए महीने से ठीक पहले के महीने के अंतिम दिन की टीटी क्रय दर पर विचार किया जाना चाहिए। विदेशी कर क्रेडिट की गणना तदनुसार की गई है।

अनुच्छेद 12(1) के अनुसार, किसी संविदाकारी राज्य (इस मामले में देश एन) में उत्पन्न होने वाली तथा किसी अन्य संविदाकारी राज्य के निवासी (इस मामले में भारत की निवासी श्रीमती सुधा शर्मा) को भुगतान की गई रॉयल्टी आय पर उस अन्य राज्य (इस मामले में भारत) में कर लगाया जा सकता है। इस मामले में श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा स्रोत राज्य, अर्थात् देश एन में भुगतान किए गए ऐसे कर के लिए क्रेडिट भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगा जो ऐसी आय भारतीय कर के लिए प्रभार्य संपूर्ण आय में वहन करती है।

21. मन्नन वर्ष 2024-25 के लिए निवासी तो है, लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं है। वह निवासी है, क्योंकि वह पूरे वर्ष भारत में रहा है और इसलिए, वह वर्ष 2024-25 के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहने की शर्त को पूरा करता है। हालाँकि, वह सामान्य रूप से निवासी नहीं है, क्योंकि वह वर्ष 2024-25 से पहले केवल 60 दिनों की अवधि तक भारत में रहा है।

इसलिए, वह वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में "सामान्यतः निवासी नहीं" माने जाने के लिए धारा 6(6) के तहत निर्धारित वित्तीय वर्ष 2024-25 से ठीक पूर्व के सात वर्षों में 729 दिन या उससे कम अवधि तक भारत में रहने की शर्त को पूरा करता है।

इसके अलावा, वह वित्तीय वर्ष 2024-25 से ठीक पहले के सभी दस वर्षों में गैर-निवासी रहा है। इसलिए, वह वित्तीय वर्ष 2024-25 से ठीक पहले के 10 में से 9 वर्षों में गैर-निवासी होने की धारा 6(6) की शर्त को भी पूरा करता है। इस मामले में, उसने दोनों शर्तों को पूरा किया है, भले ही किसी एक शर्त की संतुष्टि "सामान्यतः निवासी नहीं" के रूप में माने जाने के लिए पर्याप्त होगी।

निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी न होने की स्थिति में, भारत में प्राप्त होने वाली या प्राप्त मानी जाने वाली आय या भारत में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली या उपार्जित या उत्पन्न मानी जाने वाली आय भारत में कर योग्य होगी। हालाँकि, भारत के बाहर उपार्जित या उत्पन्न होने वाली आय को कुल आय में तभी शामिल किया जाएगा, जब वह भारत में स्थापित व्यवसाय या प्रोफेशन से हुई हो।

तदनुसार, श्री मनन की कुल आय और कर देयता, निवासी होते हुए भी सामान्यतः निवासी न होते हुए, निम्नलिखित तरीके से गणना की जाएगी:

विवरण	₹
देश एक्स में अर्जित और प्राप्त परिसंपत्ति से आय भारत में उसपर कर योग्य नहीं होगी।	-
<b>व्यवसाय से आय</b> [भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है और इसलिए भारत में कर योग्य है]	12,50,000
<b>पूंजीगत लाभ</b>	
बिक्री प्रतिफल	80,00,000
घटाएँ: अधिग्रहण की लागत [चूँकि भूमि 23.7.2024 को या उसके बाद हस्तांतरित की जाती है, इसलिए धारा 112 के तहत कर देयता निर्धारित करते समय सूचीकरण लाभ पर विचार किया जाएगा]	<u>30,00,000</u>
<b>दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ</b>	<u>50,00,000</u>
<b>कुल आय</b>	<b>62,50,000</b>
<b>कर देयता की गणना</b>	
<b>दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर</b>	6,25,000
निम्नतम -	
- इंडेक्सेशन लाभ के बिना 12.5% की दर से कर [₹50,00,000 x 12.5%]	6,25,000
- 47,09,970 रुपये के एलटीसीजी पर इंडेक्सेशन के साथ 20% की दर से कर [80,00,000 – 32,90,030 (₹30 लाख x 363/331)]	9,41,994
<b>धारा 115खकग के तहत एलटीसीजी के अलावा 12.5 लाख रुपये की कुल आय पर कर</b>	

₹3,00,000 तक	शून्य	
₹3,00,001 – ₹7,00,000 [यानी., ₹4,00,000 x 5%]	20,000	
₹7,00,001 – ₹10,00,000 [यानी, ₹3,00,000 x 10%]	30,000	
₹10,00,001 – ₹12,00,000 [यानी, ₹2,00,000 x 15%]	30,000	
₹12,00,001 – ₹12,50,000 [यानी, ₹50,000 x 20%]	<u>10,000</u>	
		90,000
		7,15,000
जोड़ें: कुल आय ₹50 लाख से अधिक होने पर 10% अधिभार		<u>71,500</u>
		<b>7,86,500</b>
जोड़ें: एचईसी@4%		<u>31,460</u>
<b>कर देयता</b>		<b><u>8,17,960</u></b>

22. दो या अधिक "संबद्ध उद्यमों" के बीच किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय की गणना अधिनियम के खंड X के प्रावधानों के अनुसार आर्म्स लेंथ मूल्य को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। धारा 92क में "संबद्ध उद्यम" को परिभाषित किया गया है और इस खंड की उप-धारा (2) में उन स्थितियों को बताया गया है जब दो उद्यमों को संबद्ध उद्यम माना जाएगा।

#### ड्रिफ्ट इंक के साथ लेनदेन

ड्रिफ्ट इंक. टीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और विदेशी कंपनी है। इसलिए, यह एक संबद्ध उद्यम है। रॉयल्टी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में आती है, क्योंकि यह एक अमूर्त परिसंपत्ति होने के नाते ज्ञान हेतु किया गया भुगतान है। ड्रिफ्ट इंक. वर्तमान में ज्ञान की आपूर्ति हेतु टीसीएल को प्रति वर्ष 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की रॉयल्टी का भुगतान कर रही है। जापान में पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी एलीट एलएलसी को ज्ञान की समान आपूर्ति के लिए, टीसीएल को 4 मिलियन अमरीकी डॉलर की वार्षिक रॉयल्टी मिलती है।

सीयूपी पद्धति के तहत, एएलपी को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर माना जाना चाहिए। रॉयल्टी की न्यूनोक्ति 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर x ₹82 = ₹820 लाख

#### स्विफ्ट इंक के साथ लेनदेन

धारा 92क(2) के अनुसार, यदि कोई उद्यम दूसरे उद्यम को उसकी कुल परिसंपत्तियों के बही मूल्य के 51% या उससे अधिक राशि का ऋण देता है, तो दोनों उद्यमों को संबद्ध उद्यम माना जाएगा।

ऋण लेने की तिथि पर, अग्रिम राशि 330 करोड़ रुपये में से 220 करोड़ रुपये है, जो 66.67 % है। इसलिए, स्विफ्ट इंक. को टीसीएल का संबद्ध उद्यम माना जाएगा। ब्याज भुगतान भी "अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन" के अंतर्गत आते हैं।

स्विफ्ट इंक. ने 8% की दर से ब्याज लिया है और टीसीएल ने 31.3.2025 को समाप्त वर्ष हेतु 17.6 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाया है। अन्य पक्षों से ली जाने वाली ब्याज दर 7% है। इसे एएलपी दर के रूप में माना जाना चाहिए।

इसके अनुसार ब्याज भुगतान  $17.6 \times 7/8$  यानी 15.4 करोड़ रुपये होना चाहिए था। एएलपी से 2.2 करोड़ रुपये अधिक भुगतान हुआ है।

#### टी.डब्लू.एल. के साथ लेनदेन

टी.डब्लू.एल. में टीसीएल के पास 22/92 यानी 23.91% वोटिंग पावर है। चूंकि टीसीएल के पास 26% से कम वोटिंग पावर है, इसलिए टी.डब्लू.एल. एक संबद्ध उद्यम नहीं है। इसलिए, टीसीएल द्वारा टी.डब्लू.एल. को की गई बिक्री पर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रावधान लागू नहीं होंगे।



## प्रश्न-पत्र - 5 : अप्रत्यक्ष कर कानून

- (1) सभी प्रश्नों के उत्तर (i) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित जीएसटी कानून, जिसमें 31 अक्टूबर, 2024 तक महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र और अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, और (ii) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क कानून, जिसमें 31 अक्टूबर, 2024 तक महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र और अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, की स्थिति के आधार पर दिए गए हैं।
- (2) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, जीएसटी से संबंधित प्रश्नों और उत्तरों में उल्लिखित धारा संख्याएं और नियम क्रमशः केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 से संबंधित हैं।
- (3) विभिन्न प्रश्नों में उल्लिखित वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जीएसटी दरें काल्पनिक हैं और जरूरी नहीं कि वे उन वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू वास्तविक दरें हों। सीमा शुल्क की दरें भी काल्पनिक हैं और जरूरी नहीं कि वे वास्तविक दरें हों। इसके अलावा, सभी प्रश्नों में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, जहां भी लागू हो।



### प्रश्न

#### केस परिदृश्य - I

वर्धमान लिमिटेड [जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा], दिल्ली में पंजीकृत है, तथा भारत के कई राज्यों में इसका संचालन होता है। कंपनी ने उन सभी राज्यों में अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण कराया है, जहां यह काम करती है। जनवरी महीने के दौरान, कर टीम ने प्रबंधन को अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

1. कंपनी ने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर स्थित अपने गोदाम से 5 करोड़ रुपये मूल्य का माल अहमदाबाद स्थित एक खरीदार को माल में स्वामित्व के हस्तांतरण के माध्यम से बेचा। माल के क्लियरेंस की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। कंपनी ने वियतनाम से माल आयात किया था और तब से घरेलू खपत हेतु इसे मंजूरी नहीं दी गई थी।
2. कंपनी को राजस्थान के अग्रिम निर्णय प्राधिकरण से एक विशेष मुद्दे पर अनुकूल अग्रिम निर्णय आदेश मिला। कंपनी ने यह आवेदन राजस्थान में अपने पंजीकृत व्यवसाय स्थान के माध्यम से दायर किया था।
3. कंपनी को महाराष्ट्र में न्यायाधिकरण से एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा 1 करोड़ रुपये के कर और 10 लाख रुपये के जुर्माने तथा 25 लाख रुपये के ब्याज की मांग की पुष्टि की गई। इस मामले में विवाद उस मुद्दे के समान था जिसके लिए कंपनी को राजस्थान राज्य में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण से अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ था, जिसकी ऊपर पैरा 2 में चर्चा की गई है। कंपनी को लगता है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इस मामले में उसका मामला मजबूत है।
4. कंपनी ने कुछ आपूर्तियों के संबंध में कर चालान जारी किया है, जिसमें प्राप्तकर्ताओं से एकत्रित कुल कर राशि 3 करोड़ रुपये है। इसके बाद, यह पाया गया कि आपूर्ति जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं थी और कंपनी द्वारा आपूर्ति के प्राप्तकर्ताओं से गलत तरीके से राशि एकत्र की गई थी।
5. मध्य प्रदेश राज्य के कर प्राधिकारियों द्वारा नामित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में कंपनी के विरुद्ध विशेष लेखापरीक्षा शुरू की गई।

उपरोक्त मामले के तथ्यों के आधार पर, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हेतु सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

1. गुजरात के कांडला स्थित अपने गोदाम से बेचे गए माल के संबंध में, कंपनी \_\_\_\_\_:
  - (क) लागू होने पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।
  - (ख) केवल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।
  - (ग) केवल आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।
  - (घ) किसी भी कर या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

2. राजस्थान में कंपनी द्वारा प्राप्त अग्रिम न्यायिक निर्णय आदेश के संबंध में,
  - (क) यह आदेश न केवल राजस्थान में कंपनी पर बाध्यकारी है, बल्कि भारत में कंपनी के सभी पंजीकरणों के क्षेत्राधिकार अधिकारियों पर भी बाध्यकारी है।
  - (ख) यह आदेश भारत के सभी राज्यों में कंपनी के लिए बाध्यकारी है।
  - (ग) यह आदेश कंपनी और राजस्थान में क्षेत्राधिकार अधिकारी पर बाध्यकारी है।
  - (घ) यह आदेश कंपनी और भारत में कंपनी के सभी पंजीकरणों के क्षेत्राधिकार अधिकारियों पर बाध्यकारी है।
3. यदि कंपनी महाराष्ट्र में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करती है, तो कंपनी द्वारा की जाने वाली पूर्व-जमा राशि \_\_\_\_\_ है।
  - (क) ₹ 11 लाख
  - (ख) ₹ 13.5 लाख
  - (ग) ₹ 10 लाख
  - (घ) शून्य
4. ऐसे मामले में जहां कंपनी द्वारा प्राप्तकर्ताओं से कर गलत तरीके से वसूला गया हो,
  - (क) कंपनी ऐसी राशि सरकार को अदा करेगी।
  - (ख) कंपनी प्राप्तकर्ताओं को राशि वापस लौटाएगी।
  - (ग) कंपनी ऐसी राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करेगी।
  - (घ) कंपनी ऐसी राशि अपने पास रख सकती है।
5. मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित की जा रही विशेष लेखापरीक्षा के मामले में,
  - (क) चार्टर्ड अकाउंटेंट का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार देय है।
  - (ख) चार्टर्ड अकाउंटेंट का पारिश्रमिक राज्य कर आयुक्त के निर्देशानुसार कंपनी द्वारा देय है।
  - (ग) चार्टर्ड अकाउंटेंट का पारिश्रमिक आयुक्त द्वारा देय है, लेकिन परीक्षा और लेखा परीक्षा का खर्च अभिलेखों की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जाएगी।

(घ) अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा का व्यय, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का पारिश्रमिक भी शामिल है, आयुक्त द्वारा भुगतान किया जाएगा।

**केस परिदृश्य II**

विद्युत निगम लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है जो पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में है। उक्त कंपनी में भारत सरकार की 75% इक्विटी है और शेष इक्विटी संस्थागत एवं घरेलू निवेशकों के पास है। कंपनी ने ऐसे प्रत्येक राज्य में जीएसटी के तहत अलग-अलग पंजीकरण कराया है जहाँ इसका व्यवसाय संचालन होता है। कंपनी का मुख्यालय (एचओ) दिल्ली में है और इसके बिजली संयंत्र बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित हैं।

फरवरी माह के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित लेनदेन किए गए:

विवरण	दिल्ली मुख्यालय (₹)	बिहार संयंत्र (₹)	ओडिशा संयंत्र (₹)	छत्तीसगढ़ संयंत्र (₹)
डिस्कॉम को विद्युत ऊर्जा की बिक्री	---	2,50,00,000	3,50,00,000	4,50,00,000
बचत बैंक खाते और सावधि जमा पर प्राप्त बैंक ब्याज	18,00,000	3,00,000	5,00,000	8,00,000
कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए आवासीय आवास हेतु उनसे वसूला गया मकान का किराया	55,000	30,000	25,000	40,000
बैंक, एटीएम, डाकघर और कार्यालय परिसर में स्थित दुकानों से लिया जाने वाला किराया	48,000	15,000	12,000	16,000
जीएसटी के अंतर्गत अपंजीकृत बिड़ला स्क्रैपर्स को धातु स्क्रैप (खंड 72 के अंतर्गत) (आयकर	-	85,000	65,000	45,000

अधिनियम, 1961 के अनुसार 1% टीसीएस को छोड़कर) की बिक्री				
अन्य आय	2,50,000	-	-	45,000

उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त, फरवरी माह के दौरान निम्नलिखित लेनदेन भी किए गए:

- (1) दिल्ली मुख्यालय द्वारा मेसर्स स्टेशनरी मार्ट, नई दिल्ली को ₹3,36,000 (जीएसटी @ 12% सहित) का स्टेशनरी वस्तुओं की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया।  
विक्रेता ने 44,800 रुपये (जीएसटी @ 12% सहित) मूल्य की स्टेशनरी वस्तुएं आपूर्ति की और फरवरी में कर चालान जारी किया। दिल्ली मुख्यालय ने फरवरी में उक्त बिल का भुगतान विक्रेता के खाते में उसी तिथि को अपनी खाताबही में जमा करके किया था। शेष राशि का भुगतान अप्रैल में शेष वस्तुओं की आपूर्ति पर किया गया।
- (2) ओडिशा स्थित संयंत्र ने फरवरी के दौरान एक अपंजीकृत डीलर से 2,80,000 रुपये का ऑफिस फर्नीचर खरीदा। उक्त फर्नीचर पर जीएसटी की दर 18% है।
- (3) परियोजना के विस्तार हेतु सावधि ऋण जुटाने हेतु फरवरी में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। दिल्ली मुख्यालय ने बैठक में भाग लेने वाले 4 स्वतंत्र निदेशकों (सभी जीएसटी के तहत पंजीकृत) को बैठक की फीस के रूप में प्रत्येक को 20,000 रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा, इसने इन निदेशकों में से एक को 80,000 रुपये का भुगतान किया, जिसने दिल्ली मुख्यालय को कार्यालय भवन किराए पर दिया था।
- (4) अपने मुख्यालय और बिजली संयंत्रों की सुरक्षा हेतु कंपनी ने पर्सनल सिक्योरिटी के साथ-साथ सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) की सेवाएं भी लीं। उक्त सेवाओं के लिए फरवरी में निम्नलिखित भुगतान किए गए:

विवरण	दिल्ली मुख्यालय (₹)	बिहार संयंत्र (₹)	ओडिशा संयंत्र (₹)	छत्तीसगढ़ संयंत्र (₹)
सीआईएसएफ	---	10,00,000 (7 फरवरी को भुगतान किया गया)	8,00,000 (15 फरवरी को भुगतान किया गया)	14,00,000 (5 फरवरी को भुगतान किया गया)
एबीएस सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	5,00,000 (11 फरवरी को भुगतान किया गया)	-	-	-

- (5) बिहार संयंत्र ने फरवरी में मेसर्स साहू एंटरप्राइजेज, पटना (जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं) से ₹86,000 में एक मशीनरी खरीदी। फरवरी में पूरा भुगतान किया गया। उक्त मशीनरी पर जीएसटी की दर 18% है।

ऊपर उल्लिखित सभी राशियाँ, जहाँ भी लागू हो, जीएसटी को छोड़कर हैं (जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो)।

उपरोक्त मामले के तथ्यों के आधार पर, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 6 से 11 तक हेतु सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

6. फरवरी माह हेतु कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, जिस पर दिल्ली मुख्यालय द्वारा अग्रिम प्रभार के तहत जी.एस.टी. देय है, \_\_\_\_\_ है।

(क) ₹ 18,00,000

(ख) ₹ 2,98,000

(ग) ₹ 21,53,000

(घ) ₹ 48,000

7. कर योग्य आवक आपूर्ति का मूल्य जिस पर बिहार विद्युत संयंत्र द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी देय होगा, \_\_\_\_\_ है।

(क) ₹ 11,80,000

(ख) ₹ 10,00,000

(ग) ₹ 10,86,000

(घ) ₹ 10,30,000

8. आपूर्ति का वह मूल्य जिस पर फरवरी में मेसर्स स्टेशनरी मार्ट को भुगतान करते समय दिल्ली मुख्यालय द्वारा धारा 51 के अंतर्गत टीडीएस काटा जाएगा, \_\_\_\_\_ है।

(क) ₹ 40,000

(ख) ₹ 44,800

(ग) ₹ 3,00,000

- (घ) चूंकि फरवरी में किया गया भुगतान 2,50,000 रुपये से कम है, इसलिए टीडीएस कटौती योग्य नहीं है।

9. कर योग्य आवक आपूर्ति का मूल्य जिस पर दिल्ली मुख्यालय और ओडिशा संयंत्र द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी देय होगा, क्रमशः \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ है।
- (क) ₹1,60,000 और ₹10,80,000  
 (ख) ₹80,000 और ₹8,00,000  
 (ग) ₹6,80,000 और ₹2,80,000  
 (घ) ₹5,80,000 और ₹2,80,000
10. छत्तीसगढ़ संयंत्र द्वारा धातु स्क्रेप की बिक्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है?
- (क) बिड़ला स्क्रेपर्स द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत 45,000 रुपये के धातु स्क्रेप की आपूर्ति के मूल्य पर जीएसटी देय है।  
 (ख) छत्तीसगढ़ संयंत्र द्वारा फॉरवर्ड चार्ज के तहत 45,000 रुपये के धातु स्क्रेप की आपूर्ति के मूल्य पर जीएसटी देय है।  
 (ग) छत्तीसगढ़ संयंत्र द्वारा फॉरवर्ड चार्ज के तहत 45,450 रुपये की धातु स्क्रेप की आपूर्ति के मूल्य पर जीएसटी देय है।  
 (घ) धातु स्क्रेप की बिक्री, जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत टीसीएस एकत्र किया जा रहा है, जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त आपूर्ति है।
11. निम्नलिखित में से कौन सी आपूर्ति रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर योग्य नहीं है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।
- (i) कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए आवासीय आवास के लिए उनसे वसूला गया मकान का किराया।  
 (ii) बैंक, एटीएम, डाकघर और कार्यालय परिसर में स्थित दुकानों से वसूला गया किराया।  
 (iii) बिड़ला स्क्रेपर्स को धातु स्क्रेप (खंड 72 के अंतर्गत) की बिक्री।
- (क) (i) और (ii)  
 (ख) (i), (ii) और (iii)  
 (ग) (i) और (iii)  
 (घ) (ii) और (iii)

12. लांबा इंडस्ट्री, भारत ने अपने मुख्य उत्पाद की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने हेतु विकासशील देश मलेशिया से बड़ी मात्रा में 'वस्तु गामा' का आयात किया है। उक्त उत्पाद के बढ़ते आयात से चिंतित केंद्र सरकार कुछ सुरक्षा उपाय लागू करने पर विचार कर रही है, क्योंकि जांच करने के बाद, उसे ऐसा लगता है कि ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा है। मलेशिया से 'वस्तु गामा' के आयात का हिस्सा भारत में उस वस्तु के कुल आयात का 4% है।

दिए गए मामले में सुरक्षा उपाय लागू करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें।

- (i) केन्द्र सरकार को सुरक्षा उपाय लागू होने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू करने का अधिकार है।
- (ii) सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि मलेशिया से 'वस्तु गामा' के आयात का हिस्सा भारत में उस वस्तु के कुल आयात का 3% से अधिक है।
- (iii) केन्द्र सरकार को सुरक्षा उपाय लागू करने की तिथि से अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें लागू करने का अधिकार है, तथा इसके बाद इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
- (iv) सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि मलेशिया से 'वस्तु गामा' के आयात का हिस्सा भारत में उस वस्तु के कुल आयात का 3% से अधिक है।

(क) (i) और (ii)

(ख) (iii)

(ग) (iv)

(घ) (ii) और (iii)

13. महाराष्ट्र राज्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत कंपनी पूर्वा इंपेक्स लिमिटेड, विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति करती है। यह कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न नहीं है। पूर्वा इंपेक्स लिमिटेड, भारत पूर्वा इंक की एक सहायक कंपनी है, जो यूएसए में निगमित है, जो भारत में ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ प्रदान करती है। इसने अप्रैल महीने हेतु निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹)
	<b>जावक आपूर्ति:</b>	
(i)	पूर्वा इंक हेतु भारत में प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के प्रमोशन एवं मार्केटिंग का कार्य।	20,00,000
(ii)	महाराष्ट्र में पंजीकृत सुभाषिनी एंटरप्राइजेज को मुद्रित लेटर कार्ड की आपूर्ति की गई। प्रत्येक लेटर कार्ड पर फर्म के विजन को दर्शाने वाला लोगो अंकित किया जाना था और उक्त लोगो फर्म द्वारा प्रदान किया गया था। सामग्री की लागत ₹8,00,000 थी और मुद्रण लागत ₹72,000 थी।	8,72,000
(iii)	महाराष्ट्र में पंजीकृत ध्रुवतारा ट्रेडर्स को कच्चा कपास उपलब्ध कराया गया। कच्चा कपास पिछले महीने स्थानीय किसानों से खरीदा गया था।	5,00,000
(iv)	ग्रेटर मुंबई नगर निगम को रखरखाव सेवाएँ प्रदान कीं, जिसने ग्रेटर मुंबई नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का अनुबंध दिया है। रखरखाव कार्य में खराब लाइटों और अन्य पुर्जों को बदलना शामिल था। [आपूर्ति के कुल मूल्य 1,20,000 रुपये में से खराब लाइटों और बदले गए अन्य पुर्जों का मूल्य 32,000 रुपये है।]	1,20,000
(v)	गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) को 10 कारों (ड्राइवर सहित 5 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता) किराये पर दी गई।	3,00,000
	<b>आवक आपूर्ति:</b>	
(i)	गुजरात राज्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत बाँबी एंड कंपनी से प्रोसेसिंग मशीनें खरीदी गईं। कर योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु गुजरात में मशीनें "जैसी हैं, वैसी ही स्थिति में" खरीदी गईं।	5,00,000

(ii)	महाराष्ट्र के मनसुख ट्रेडर्स, जो एक अपंजीकृत व्यक्ति है, से विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग हेतु धातु स्क्रैप (खंड 72 के अंतर्गत) खरीदा गया।	2,00,000
(iii)	जर्मनी स्थित कंपनी थॉमस इंक से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपने व्यवसाय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्राप्त कीं	1,50,000
(iv)	विनिर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी को मरम्मत कार्य के लिए जॉर्ज इंक., यू.एस.ए. को भेजा गया था। इस मरम्मत कार्य के लिए जॉर्ज इंक. को प्रतिफल का भुगतान किया गया। मशीन मरम्मत के बाद मई महीने में प्राप्त हुई।	5,00,000

कंपनी ने निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की:

- (i) पूर्वा इंक., यूएसए ने पूर्वा इम्पेक्स लिमिटेड की ओर से मणिमणि बैंक, महाराष्ट्र को 1.5 करोड़ रुपये की निःशुल्क कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की।
- (ii) सेवाओं की आवक और जावक आपूर्ति दोनों के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की दरें क्रमशः 9%, 9% और 18% हैं और वस्तुओं की आवक और जावक आपूर्ति दोनों के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की दरें क्रमशः 6%, 6% और 12% हैं, कच्चे कपास की आपूर्ति के मामले को छोड़कर जहां सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की लागू दरें 2.5%, 2.5% और 5% हैं और धातु स्क्रैप की आपूर्ति के मामले में जहां सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की लागू दरें 9%, 9% और 18% हैं।
- (iii) ऊपर दी गई सभी राशियों में, जहां भी लागू हो, कर शामिल नहीं हैं।
- (iv) प्रासंगिक अवधि के लिए किसी भी आईटीसी का कोई प्रारंभिक शेष नहीं था।
- (v) पूर्वा इम्पेक्स लिमिटेड द्वारा किए गए सभी निर्यात, आईजीएसटी के भुगतान के बिना एल्यूटी प्रस्तुत करने के माध्यम से होते हैं।

उपरोक्त दी गई जानकारी से, आपको पूर्वा इम्पेक्स लिमिटेड, महाराष्ट्र के लिए अप्रैल महीने हेतु नकद में देय न्यूनतम शुद्ध जीएसटी देयता (सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, जैसा भी मामला हो) की गणना करनी है।

14. प्रतीक लिमिटेड द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील में, इस सवाल पर कि क्या प्रतीक लिमिटेड द्वारा की गई गतिविधि आपूर्ति के समतुल्य है, अपील का निर्णय प्रतीक लिमिटेड के पक्ष में आया। इसमें कर, ब्याज और जुर्माने की राशि 1.2 करोड़ रुपये की आईजीएसटी, 60 लाख रुपये का ब्याज और 50 लाख रुपये का जुर्माना शामिल था।

हालांकि, विभाग उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत नहीं है और तर्क दिया कि उक्त गतिविधि जीएसटी के तहत आपूर्ति के समतुल्य है। विभाग कर, ब्याज और जुर्माने की मांग से संबंधित विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करना चाहता है। आपको यह जांचना है कि क्या दिए गए मामले में विभाग द्वारा अपील दायर की जा सकती है। यदि मामला सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है, न कि यह निर्धारित करने से कि उक्त गतिविधि आपूर्ति के समतुल्य है या नहीं, तो क्या आपका उत्तर बदल जाएगा?

15. यूएसए स्थित कंपनी स्मिथ इंक. अपने ऑनलाइन मनी गेमिंग पोर्टल पर भारत में अपने अपंजीकृत ग्राहकों से सब्सक्रिप्शन शुल्क लेती है। विभाग का तर्क है कि स्मिथ इंक. को भारतीय ग्राहकों से मिलने वाले सब्सक्रिप्शन शुल्क पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए।

स्मिथ इंक. ने उपरोक्त का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग अमूर्त वस्तुएं हैं और इस मामले में भौतिक रूप से सीमा शुल्क सीमाओं को पार नहीं करती हैं, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं:

- (i) इस मामले में आपूर्ति का स्थान क्या होगा?
  - (ii) क्या स्मिथ इंक द्वारा अपंजीकृत ग्राहकों से ली जाने वाले सब्सक्रिप्शन शुल्क पर जीएसटी देय है? यदि हाँ, तो जीएसटी का भुगतान किसे करना होगा?
16. श्री दिवास, आगरा, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यक्ति हैं, उन्होंने 15 अक्टूबर को 12,50,000 रुपये में एक कार खरीदी। 31 अक्टूबर को कार की दुर्घटना हुई और दुर्घटना के कारण मामूली क्षति हुई।
- समय की कमी के कारण, उन्होंने अपनी कार की मरम्मत अपनी सामान्य बीमा कंपनी, अर्थात् सुरक्षा बीमा कंपनी, जिसके माध्यम से उनकी कार का बीमा हुआ था, द्वारा अधिकृत गैराज के बजाय, पास के बाजार के स्थानीय गैराज में करवाई।

मरम्मत की कुल लागत 54,000 रुपये (18% जीएसटी को छोड़कर) थी। श्री दिवास के कहने पर, गैरेज द्वारा सुरक्षा बीमा कंपनी के नाम पर पूरी राशि का चालान बनाया गया। बीमा कंपनी ने सर्वे के बाद केवल 40,000 रुपये की दावा राशि को मंजूरी दी और श्री दिवास को 18% जीएसटी के साथ राशि की प्रतिपूर्ति कर दी।

उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं:

- (i) क्या सुरक्षा बीमा कंपनी गैराज द्वारा जारी किए गए चालान के आधार पर आईटीसी का लाभ उठाने हेतु पात्र है? यदि हाँ, तो पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि क्या होगी?
  - (ii) क्या आपका उत्तर अलग होता, यदि गैराज ने दो अलग-अलग चालान जारी किए होते, एक सुरक्षा बीमा कंपनी को ₹40,000 + जीएसटी @ 18% और दूसरा श्री दिवास को ₹14000 + जीएसटी @18%?
  - (iii) यदि गैराज ने श्री दिवास के नाम पर चालान जारी किया है, तो क्या सुरक्षा बीमा कंपनी आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्र होगी?
17. उन परिदृश्यों की सूची बनाएं जहां माल या वाहन सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 130 के अंतर्गत जब्त किए जा सकते हैं।
18. श्री मनमीत ने अमेरिका में रहने वाले अपने बेटे श्री हरभजन से कुछ सामान आयात किया और ट्रांजेक्शन वैल्यू को अस्वीकार कर दिया गया है। सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 के नियम 4 और 5 लागू नहीं पाए गए क्योंकि भारत में कोई समान/समरूप सामान आयात नहीं किया जाता है।

श्री मनमीत आयातों के लागत-संबंधी आंकड़े पेश किया तथा सीमा शुल्क अधिकारियों से नियम 8 के अनुसार तदनुसार मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है। प्रासंगिक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	श्री हरभजन द्वारा वहन की गई सामग्री की लागत	\$ 2000
2.	श्री हरभजन द्वारा वहन किए गए निर्माण शुल्क	\$ 1000
3.	श्री हरभजन द्वारा वहन किए गए अन्य प्रभार्य व्यय	\$ 400
4.	श्री हरभजन द्वारा वहन किए गए अन्य अप्रत्यक्ष खर्च	\$ 250

5.	श्री हरभजन की फैक्ट्री से अमेरिकी बंदरगाह तक माल ढुलाई	\$ 250
6.	अमेरिकी बंदरगाह पर लोडिंग शुल्क	\$ 100
7.	श्री हरभजन का सामान्य शुद्ध लाभ मार्जिन	एफओबी का 20%
8.	अमेरिकी बंदरगाह से भारतीय बंदरगाह तक हवाई माल ढुलाई	\$ 1,500
9.	अमेरिकी बंदरगाह से भारतीय बंदरगाह तक बीमा	\$ 50
10.	विनिमय दर	रु, 85 प्रति \$

सीमा शुल्क प्राधिकारियों की राय है कि चूंकि नियम 7 के अनुसार मूल्य 5,00,000 रुपये निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए नियम 8 को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्या श्री मनमीत का अनुरोध कानूनी रूप से स्वीकार्य हो सकता है? यदि हाँ, तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना करें।

19. ग्रीन पेपर्स कंपनी ने 15 जुलाई को उचित अधिकारी के समक्ष पेश किए गए बिल ऑफ एंट्री के माध्यम से 20,00,000 रुपये मूल्य का माल आयात किया, जिस तिथि को सीमा शुल्क की दर 10% थी। ग्रीन पेपर्स कंपनी ने सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किए और पूरी जानकारी दी। हालांकि, उचित अधिकारी ने आगे की जांच करना आवश्यक समझा और इसलिए, इसे 20,00,000 रुपये के मूल्य पर अनंतिम रूप से मूल्यांकित किया गया और ग्रीन पेपर्स कंपनी ने उसी तिथि पर 2,00,000 रुपये का अनंतिम शुल्क चुकाया।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अंतर्गत देय ब्याज की राशि, यदि कोई हो, निर्धारित करें, बशर्ते कि:

- ग्रीन पेपर्स कंपनी 20 अगस्त को स्वेच्छा से 50,000 रुपये का शुल्क अदा करती है।
- अंतिम शुल्क 31 अगस्त को ₹3,00,000 निर्धारित किया गया है।
- ग्रीन पेपर्स कंपनी अंतिम शुल्क के मूल्यांकन की तिथि पर शेष शुल्क का भुगतान करती है।

20. निर्यात हेतु गोदाम में रखे माल के क्लियरेंस से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा करें।



सुझाए गए उत्तर

प्रश्न. सं.	उत्तर
1.	(घ) किसी भी कर या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2.	(ग) यह आदेश कंपनी और राजस्थान में क्षेत्राधिकार अधिकारी पर बाध्यकारी है।
3.	(ग) ₹10 लाख
4.	(क) कंपनी ऐसी राशि सरकार को अदा करेगी।
5.	(घ) अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा का व्यय, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का पारिश्रमिक भी शामिल है, आयुक्त द्वारा भुगतान किया जाएगा।
6.	(ख) ₹ 2,98,000
7.	(ख) ₹ 10,00,000
8.	(क) ₹ 40,000
9.	(ख) ₹80,000 और ₹8,00,000
10.	(ख) छत्तीसगढ़ संयंत्र द्वारा फॉरवर्ड चार्ज के तहत 45,000 रुपये के धातु स्क्रेप की आपूर्ति के मूल्य पर जीएसटी देय है।
11.	(ख) (i), (ii) और (iii)
12.	(क) (i) और (ii)

13. अप्रैल माह के लिए नकद में देय न्यूनतम शुद्ध जीएसटी की गणना

विवरण	राशि (₹)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)	आईजीएसटी (₹)
<b>अग्रिम प्रभार (फॉरवर्ड चार्ज) के अंतर्गत देय जीएसटी</b>				
पूर्वा इंक को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रमोशन एवं मार्केटिंग।	20,00,000	-	-	-

[चूंकि प्रमोशन एवं मार्केटिंग सेवाओं की आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता - पूर्वा इंक. का स्थान है, अर्थात् भारत के बाहर, वे पूर्वा इंपेक्स लिमिटेड द्वारा पूर्वा इंक. को सेवाओं का निर्यात है, क्योंकि आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(6) की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है। <sup>1</sup> इसके अलावा, पूर्वा इंपेक्स लिमिटेड द्वारा किए गए सभी निर्यात आईजीएसटी के भुगतान के बिना एल्यूटी प्रस्तुत करने के माध्यम से हैं।]				
मुद्रित लेटर कार्ड की आपूर्ति [चूंकि लेटर कार्ड प्रिंटर द्वारा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए लोगो को प्रिंट करने हेतु अपने स्वयं के भौतिक इनपुट का उपयोग करके आपूर्ति किए गए हैं, इसलिए यह समग्र आपूर्ति है जिसमें प्रमुख आपूर्ति माल की आपूर्ति है। यह एक अंतर-राज्य आपूर्ति है क्योंकि आपूर्ति का स्थान महाराष्ट्र है, जो धारा 10(1)(क) के अनुसार माल की आवाजाही पूरा होने का स्थान है।]	8,72,000	52,320 [8,72,000 X 6%]	52,320 [8,72,000 X 6%]	
कच्चे कपास की अंतर-राज्य आपूर्ति [अधिसूचना संख्या 4/2017 सीटी (आर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार अग्रिम	5,00,000	12,500 [5,00,000 × 2.5%]	12,500 [5,00,000 × 2.5%]	

<sup>1</sup> होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी को परिपत्र संख्या 161/17/2021 जीएसटी दिनांक 20.09.2021 के अनुसार सेवा के निर्यात की शर्तों के अनुपालन के उद्देश्य से "केवल एक अलग व्यक्ति की स्थापना" नहीं माना जाता है।

प्रभार (फॉरवर्ड चार्ज) के अंतर्गत कर योग्य। रिवर्स चार्ज तंत्र लागू नहीं है, क्योंकि यहां कच्चे कपास को कृषक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेचा जा रहा है।]				
ग्रेटर मुंबई नगर निगम को प्रदान की गई रखरखाव सेवाएँ [कर योग्य, क्योंकि माल की आपूर्ति का मूल्य स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र आपूर्ति के मूल्य का 25% से अधिक है [अधिसूचना संख्या 12/2017 सीटी (आर) दिनांक 28.06.2017]। इसके अलावा, मुख्य आपूर्ति रखरखाव सेवाओं की आपूर्ति है। यह एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति है क्योंकि आपूर्ति का स्थान महाराष्ट्र है जो प्राप्तकर्ता का स्थान है, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12(2) के अनुसार।]	1,20,000	10,800 [1,20,000 × 9%]	10,800 [1,20,000 × 9%]	
मोटर वाहन किराए पर देने की अंतर-राज्यीय सेवा [राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू) को किराए पर देने के माध्यम से सेवाएं, मोटर वाहन को केवल तभी छूट दिया जाता है जब ऐसा मोटर वाहन 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने हेतु हो। इस प्रकार, दिए गए मामले में, किराए पर कार देने की सेवा छूट प्राप्त नहीं है [अधिसूचना संख्या 9/2017 आईटी	3,00,000			54,000 [3,00,000 × 18%]

(आर) दिनांक 28.06.2017]। इसके अलावा, यह एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति है क्योंकि आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान गुजरात है, जो कि आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 (2) के अनुसार है।]				
<b>कुल आउटपुट कर</b>		<b>75,620</b>	<b>75,620</b>	<b>54,000</b>
घटाएँ: सेट ऑफ के लिए उपलब्ध आईटीसी [कार्य टिप्पण देखें] [आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी देयता के भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी क्रमशः सीजीएसटी और एसजीएसटी देयता के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है।]		(18,000)	(18,000)	(54,000)
<b>शुद्ध जीएसटी</b>		<b>57,620</b>	<b>57,620</b>	<b>शून्य</b>
<b>रिवर्स चार्ज के तहत देय जीएसटी</b>				
खरीदे गए धातु स्क्रेप [पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति से खरीदे गए धातु स्क्रेप पर कर अधिसूचना संख्या 4/2017 सीटी (आर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार रिवर्स चार्ज के तहत देय है।]	2,00,000	18,000 [2,00,000 × 9%]	18,000 [2,00,000 × 9%]	
इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से थॉमस इंक से प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ [आयातित सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं पर कर अधिसूचना संख्या 10/2017 आईटी (आर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार रिवर्स चार्ज के तहत देय है।]	1,50,000			27,000 [1,50,000 × 18%]

पूर्वा इंक द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट गारंटी [जहां कॉर्पोरेट गारंटी भारत में स्थित संबंधित कंपनी हेतु विदेशी/विदेशी कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, वहां सेवा प्राप्तकर्ता, यानी भारत में स्थित संबंधित इकाई द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी देय होगा।]	1,50,000			27,000 [1,50,000 × 18%]
<b>नकद में देय कुल शुद्ध जीएसटी</b>		<b>75,620</b>	<b>75,620</b>	<b>54,000</b>

**कार्य टिप्पण - सेट ऑफ के लिए उपलब्ध पात्र आईटीसी की गणना**

विवरण	राशि (₹)	सीजीएसटी (₹)	एसजीएसटी (₹)	आईजीएसटी (₹)
खरीदी गई मशीनें [यह अंतर-राज्यीय आपूर्ति है क्योंकि माल की आवाजाही से संबंधित न होने वाले माल के मामले में आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समय माल का स्थान है, अर्थात् गुजरात, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(1)(ग) के अनुसार। हालाँकि, इसका आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि उक्त अंतर-	शून्य	-	-	-

राज्यीय आपूर्ति का प्राप्तकर्ता आपूर्ति के स्थान से भिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है <sup>2</sup> ।				
खरीदा गया धातु स्क्रेप [यह अंतर-राज्यीय आपूर्ति है क्योंकि आपूर्ति का स्थान महाराष्ट्र है, जो उस समय माल का स्थान है जिस समय प्राप्तकर्ता को डिलीवरी हेतु माल की आवाजाही पूरी होती है, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(1)(क) के अनुसार। आईटीसी उपलब्ध है क्योंकि उक्त माल का उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।]	2,00,000	18,000 [2,00,000 × 9%]	18,000 [2,00,000 × 9%]	
थॉमस इंक से प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ। [आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13(2) के अनुसार, आपूर्ति का स्थान महाराष्ट्र है, जो प्राप्तकर्ता का स्थान है। ऐसी किसी भी सेवा की आपूर्ति, जहाँ आपूर्तिकर्ता भारत से बाहर है और प्राप्तकर्ता व आपूर्ति का स्थान भारत में है, सेवाओं के आयात के रूप में योग्य है। इसके अलावा, सेवा के आयात के मामले में, अधिसूचना संख्या	1,50,000			27,000 [1,50,000 × 18%]

<sup>2</sup> परिपत्र संख्या 170/02/2022 जीएसटी दिनांक 06.07.2022

<p>10/2017 आईटी (आर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार ऐसी सेवा का आयात करने वाले व्यक्ति द्वारा कर देय है। आईटीसी उपलब्ध है क्योंकि उक्त सेवाओं का उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।]</p>				
<p>जॉर्ज इंक को मरम्मत कार्य करने हेतु भेजी गई मशीनरी। [चूंकि मरम्मत सेवाओं की आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर है, जो कि वह स्थान है जहां आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13(3) के अनुसार सेवाएं वास्तव में प्रदान की जाती हैं, इसलिए उक्त सेवाएं कर योग्य नहीं हैं।]</p>	<p>शून्य</p>			
<p>पूर्वा इंक द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट गारंटी [यदि कोई आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित किसी संबंधित पक्ष की ओर से बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी देता है, तो सेवा का मूल्य प्रति वर्ष दी जाने वाली गारंटी की राशि का 1% या वास्तविक प्रतिफल, जो भी अधिक हो, यानी 1.5 करोड़ रुपये का 1% है। इसके अलावा, आईटीसी उपलब्ध है क्योंकि उक्त सेवाओं</p>	<p>1,50,000</p>			<p>27,000 [1,50,000 × 18%]</p>

का उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने हेतु किया जा रहा है।				
<b>सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध पात्र आईटीसी</b> [शून्य-रेटेड आपूर्तियों (पूर्वा इंक को प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रचार और विपणन) सहित कर योग्य बाहरी आपूर्ति करने हेतु जारी किए गए माल व सेवाओं पर आईटीसी धारा 17 के अनुसार सेट-ऑफ के लिए पूरी तरह से पात्र है।]		18,000	18,000	54,000

14. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 120 में यह प्रावधान है कि बोर्ड, परिषद की सिफारिशों पर, समय-समय पर, इस खंड के प्रावधानों के तहत केंद्रीय कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन दाखिल करने को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी मौद्रिक सीमाएँ तय करने हेतु आदेश या निर्देश या निर्देश जारी कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। सीबीआईटी ने परिपत्र संख्या 207/1/2024 जीएसटी दिनांक 26.06.2024 के तहत विभाग द्वारा जीएसटीएटी, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील/आवेदन/विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित मौद्रिक सीमाएं निर्धारित की हैं, जिसपर कुछ निर्दिष्ट अपवाद भी हैं:

अपीलीय मंच	मौद्रिक सीमा (इसमें शामिल राशि ₹)
जीएसटीएटी	20 लाख
उच्च न्यायालय	1 करोड़
सुप्रीम कोर्ट	2 करोड़

इसके अलावा, जहां विवाद कर की मांग (जुर्माना और/या ब्याज सहित या उसके बिना) से संबंधित है, तो अपील दायर करने हेतु इस मौद्रिक सीमा का पालन करते समय विवाद में कर की कुल राशि (सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर सहित) पर ही विचार किया जाएगा,

अर्थात् दिए गए मामले में 1.2 करोड़ रुपये (केवल कर की राशि) पर। इस प्रकार, दिए गए मामले में विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती क्योंकि परिपत्र के अनुसार शामिल राशि 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा से अधिक नहीं है।

हालांकि, परिपत्र में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि जीएसटीएटी या उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा अपील या आवेदन दायर करने और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका या अपील दायर करने हेतु ऊपर निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाएं निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होंगी, जहां अपील दायर करने का निर्णय उक्त मौद्रिक सीमाओं पर ध्यान दिए बिना मेरिट के आधार पर लिया जाएगा:

- i. जहां सीजीएसटी अधिनियम या एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम या जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम का कोई प्रावधान भारत के संविधान के विरुद्ध माना गया हो; या
- ii. जहां सीजीएसटी अधिनियम या एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम या जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम या विनियमन को मूल अधिनियम के विपरीत माना गया हो; या
- iii. जहां सरकार या बोर्ड द्वारा जारी कोई आदेश, अधिसूचना, अनुदेश या परिपत्र सीजीएसटी अधिनियम या एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम या जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के विरुद्ध माना गया हो; या
- iv. जहां मामला निम्न से संबंधित है -
  - क. माल या सेवाओं का मूल्यांकन; या
  - ख. माल या सेवाओं का वर्गीकरण; या
  - ग. रिफंड; या
  - घ. आपूर्ति का स्थान; या
  - ङ. कोई अन्य मुद्दा,

जो आवर्ती प्रकृति का हो और/या उसमें जीएसटी कानून/नियम/ अधिसूचना/परिपत्र /आदेश/ निर्देश आदि के प्रावधानों की व्याख्या शामिल हो;

- v. जहां सरकार/विभाग या उनके अधिकारियों के विरुद्ध आलोचना/प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हों और/या जुर्माना लगाया गया हो; या
- vi. कोई अन्य मामला या मामलों का वर्ग, जहां बोर्ड की राय में न्याय या राजस्व के हित में विरोध करना आवश्यक है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, यदि मामला सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है, तो विभाग द्वारा मौद्रिक सीमाओं पर ध्यान दिए बिना मेरिट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

15. (i) आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 11 के अनुसार, भारत में आयातित माल की आपूर्ति का स्थान आयातक का स्थान है। ऑनलाइन मनी गेमिंग निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावा होने के कारण, धारा 2(52) के साथ धारा 2(102क) के अनुसार माल में शामिल है। तदनुसार, दिए गए मामले में, आपूर्ति का स्थान ऑनलाइन मनी गेमिंग के निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे के प्राप्तकर्ता का स्थान होगा, अर्थात् भारत।
- (ii) आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(1) के प्रावधान के अनुसार, भारत में आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्य पर उस समय लगाया और एकत्र किया जाता है जब सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के तहत उक्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है।

हालांकि, अमूर्त वस्तुओं के मामले में, उक्त तरीके से आयात पर आईजीएसटी लगाना और संग्रह करना संभव नहीं है, क्योंकि ये वस्तुएं भौतिक रूप से सीमा शुल्क सीमाओं को पार नहीं करती हैं। परिणामस्वरूप, सरकार ने कुछ वस्तुओं को अधिसूचित किया है जिनके लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(1) के प्रावधान आईजीएसटी के संग्रह और संग्रह के लिए लागू नहीं होंगे; ऐसे मामलों में, आईजीएसटी केवल धारा 5(1) में निर्दिष्ट तरीके से लगाया और एकत्र किया जाएगा। उक्त उद्देश्य के लिए ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति को अधिसूचित किया गया है।

इसलिए, ऑनलाइन मनी गेमिंग के निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे के आयात पर माल के आयात के समान आईजीएसटी के तहत कर लगाया जाएगा।

तदनुसार, इस मामले में विभाग का तर्क सही है और स्मिथ इंक भारत के अपंजीकृत ग्राहकों से प्राप्त सब्सक्रिप्शन शुल्क पर आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 14क के अनुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंग का आपूर्तिकर्ता, जो कर योग्य क्षेत्र में स्थित नहीं है, कर योग्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को उसके द्वारा ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति के संबंध में, ऐसी आपूर्ति पर आईजीएसटी का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। धारा 24 (xi)क भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुल टर्नओवर की मात्रा पर ध्यान दिए बिना पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है। ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत एकल पंजीकरण लेना आवश्यक है।

तथापि, यदि आपूर्तिकर्ता का किसी प्रयोजन के लिए भारत में कोई प्रतिनिधि है, तो ऐसे व्यक्ति (भारत में प्रतिनिधि) को पंजीकृत होना होगा तथा आपूर्तिकर्ता की ओर से आईजीएसटी का भुगतान करना होगा।

यदि विदेशी आपूर्तिकर्ता की भारत में न तो कोई भौतिक उपस्थिति है और न ही किसी उद्देश्य के लिए उसका कोई प्रतिनिधि है, तो वह आईजीएसटी का भुगतान करने के उद्देश्य से भारत में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति ऐसे कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

तदनुसार, दिए गए मामले में, चूंकि स्मिथ इंक को भारतीय ग्राहकों से लिए जाने वाले सब्सक्रिप्शन शुल्क पर आईजीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है, इसलिए उसे ऊपर निर्दिष्ट तरीके से आईजीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है।

16. (ii) धारा 17(5) में प्रावधान है कि मोटर वाहनों की मरम्मत की सेवाओं के संबंध में आईटीसी तब उपलब्ध होगा जब वह अपने द्वारा बीमाकृत मोटर वाहनों के संबंध में सामान्य बीमा सेवाओं की आपूर्ति में लगे कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा, धारा 2(93) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो प्रतिफल का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, जहां ऐसा प्रतिफल माल या सेवाओं या दोनों की उक्त आपूर्ति के लिए देय है। धारा 2(31) के अनुसार, प्रतिफल में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किया गया या किया जाने वाला कोई भी भुगतान शामिल है, चाहे वह प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

सीबीआईसी ने परिपत्र संख्या 217/11/2024 जीएसटी दिनांक 26.06.2024 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि दावा निपटान के प्रतिपूर्ति मोड में, बीमा कंपनी द्वारा बीमाधारक को प्रतिपूर्ति के माध्यम से मरम्मत सेवाओं की अनुमोदित लागत का भुगतान किया जाता है।

इसके अलावा, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि गैराज को मरम्मत सेवाओं का भुगतान पहले बीमाधारक द्वारा किया जाता है, जिसे बाद में बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित दावा लागत की सीमा तक बीमाधारक को प्रतिपूर्ति की जाती है, अनुमोदित दावा लागत हेतु मरम्मत सेवा के भुगतान का दायित्व बीमा कंपनी का होता है, और इस प्रकार, बीमा कंपनी, गैराज द्वारा प्रदान की गई वाहन मरम्मत की सेवाओं की उक्त आपूर्ति के संबंध में, धारा 2(93) के अनुसार, अनुमोदित मरम्मत दायित्व की सीमा तक प्राप्तकर्ता की परिभाषा में शामिल है।

इसके अलावा, ऐसे मोटर वाहनों के लिए बीमा सेवाओं की बाहरी आपूर्ति के लिए बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त मोटर वाहन मरम्मत सेवाओं पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स के संबंध में क्रेडिट का लाभ धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध नहीं है।

तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि दावा निपटान के प्रतिपूर्ति मोड के मामले में बीमा कंपनियों को उनके द्वारा किए गए मोटर वाहन मरम्मत व्यय के संबंध में आईटीसी उपलब्ध है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मरम्मत सेवाओं के लिए पूरी राशि का चालान बीमा कंपनी को जारी किया जाता है, जबकि बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को केवल स्वीकृत दावा लागत के लिए प्रतिपूर्ति करती है, तो बीमा कंपनी को आईटीसी केवल बीमित व्यक्ति को स्वीकृत दावा लागत की प्रतिपूर्ति की सीमा तक ही उपलब्ध हो सकती है, न कि पूरे चालान मूल्य पर।

दिए गए मामले में, हालांकि मरम्मत सेवाओं की पूरी राशि (₹54,000 + जीएसटी) का चालान सुरक्षा बीमा कंपनी के नाम पर बनाया गया है, लेकिन यह स्वीकृत दावा लागत (₹40,000 + जीएसटी) की सीमा तक मरम्मत सेवा का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार, यह धारा 2(93) के तहत 'प्राप्तकर्ता' की परिभाषा में, स्वीकृत दावा लागत की सीमा तक शामिल है।

इसलिए, यह 40,000 रुपये (स्वीकृत दावा लागत) की राशि पर भुगतान किए गए जीएसटी की सीमा तक आईटीसी का लाभ उठाने हेतु पात्र है। इस प्रकार, सुरक्षा बीमा कंपनी को 7,200 रुपये ( $40,000 \times 18\%$ ) का आईटीसी उपलब्ध है।

- (ii) परिपत्र में आगे स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां गौराज मरम्मत सेवाओं के संबंध में दो अलग-अलग चालान जारी करता है, पहला बीमा कंपनी को अनुमोदित दावा लागत के संबंध में और दूसरा ग्राहक को अनुमोदित दावा लागत से अधिक मरम्मत सेवा की राशि हेतु, तो बीमा कंपनी को जारी किए गए उक्त चालान पर बीमा कंपनी को आईटीसी उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते कि बीमा कंपनी द्वारा ग्राहक को उक्त राशि की प्रतिपूर्ति की जाए।

इस प्रकार, दिए गए मामले में, यदि गैरेज ने दो अलग-अलग चालान जारी किए हैं, तो उत्तर वही रहेगा क्योंकि सुरक्षा बीमा कंपनी द्वारा श्री दिवास को प्रतिपूर्ति की गई सेवा लागत का स्वीकृत दावा केवल ₹40,000 था। इस प्रकार, सुरक्षा बीमा कंपनी को ₹7,200 ( $₹40,000 \times 18\%$ ) का आईटीसी उपलब्ध है।

- (iii) परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां वाहन की मरम्मत हेतु चालान बीमा कंपनी के नाम पर नहीं है, वहां धारा 16(2) के खंड (क) और (कक) की शर्तें पूरी नहीं होती हैं और तदनुसार, ऐसे चालान के संबंध में बीमा कंपनी को आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी। इस प्रकार, दिए गए मामले में, यदि चालान श्री दिवास के नाम पर जारी किया गया है, तो सुरक्षा बीमा कंपनी आईटीसी का लाभ उठाने हेतु पात्र नहीं होगी।

17. धारा 130 के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति —

- (i) टैक्स के भुगतान से बचने के इरादे से जीएसटी कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करके किसी भी सामान की आपूर्ति या प्राप्त करता है;
- (ii) किसी भी ऐसे माल का लेखा-जोखा नहीं रखता जिस पर वह जीएसटी कानून के तहत कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है; या
- (iii) पंजीकरण हेतु आवेदन किए बिना जीएसटी कानून के तहत कर योग्य किसी भी सामान की आपूर्ति करता है; या
- (iv) टैक्स के भुगतान से बचने के इरादे से जीएसटी कानून या उसके तहत बनाए

गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है; या

- (v) जीएसटी कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल की ढुलाई हेतु परिवहन के साधन के रूप में किसी भी वाहन का उपयोग करता है, जब तक कि वाहन का मालिक यह साबित नहीं कर देता कि इसका उपयोग मालिक, उसके एजेंट, यदि कोई हो, और वाहन के प्रभारी व्यक्ति के ज्ञान या मिलीभगत के बिना किया गया था,

तो ऐसे सभी माल या वाहन जब्त किए जा सकेंगे और व्यक्ति धारा 122 के तहत दंड का भागी होगा।

18. सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 (जिसे इसके बाद आयात मूल्यांकन नियम कहा जाएगा) के नियम 2(2) में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान है कि व्यक्तियों को "संबंधित" माना जाएगा यदि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस प्रकार, चूंकि श्री मनमीत और उनके बेटे संबंधित हैं, इसलिए लेनदेन मूल्य को खारिज [नियम 3] कर दिया गया है। नियम 4 और 5 अनुपयुक्त पाए गए हैं क्योंकि भारत में कोई समान/समरूप सामान आयात नहीं किया जाता है। नियम 6 में प्रावधान है कि यदि आयातित वस्तुओं का मूल्य नियम 3, 4 और 5 के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो मूल्य नियम 7 के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाएगा या जब मूल्य उस नियम के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो नियम 8 के तहत निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, आयातित वस्तुओं का मूल्य नियम 8 के तहत निर्धारित किया जाता है यदि इसे पहले के नियमों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, नियम 7 और 8 के आवेदन के क्रम को आयातक के अनुरोध पर और उचित अधिकारी के अनुमोदन से बदला जा सकता है।

इस प्रकार, नियम 8 के तहत मूल्य निर्धारण हेतु श्री मनमीत का अनुरोध कानूनी रूप से स्वीकार्य है, यदि इसे उचित अधिकारी द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है।

यह मानते हुए कि श्री मनमीत के अनुरोध को उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, नियम 8 के तहत आयातित माल का मूल्यांकन योग्य मूल्य निम्नलिखित राशि होगी-

- (क) सामग्री और निर्माण या अन्य प्रसंस्करण की लागत  
 (ख) लाभ और सामान्य व्यय के लिए राशि  
 (ग) उक्त नियमों के नियम 10(2) के अधीन सभी अन्य व्ययों की लागत या मूल्य।

## मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना

विवरण	राशि (\$)
सामग्री की लागत	2,000
जोड़ें: फैब्रिकेशन शुल्क	1,000
अन्य प्रभार्य व्यय	400
अन्य अप्रत्यक्ष लागतें	250
श्री हरभजन की फैक्ट्री में माल की लागत	3,650
जोड़ें: एफओबी का 20% यानी कुल लागत का 25% शुद्ध लाभ मार्जिन यूएस पोर्ट तक कुल लागत = कारखाने में माल की लागत + कारखाने से यूएस पोर्ट तक माल ढुलाई और यूएस पोर्ट पर लोडिंग शुल्क = \$ 4,000 [ $\$ 3,650 + \$ 250 + \$ 100$ ] एफओबी मूल्य = बंदरगाह तक कुल लागत + लाभ = \$ 5,000 ( $\$ 4,000 + \$ 1,000$ )	1,000
जोड़ें: माल ढुलाई और लोडिंग/अनलोडिंग शुल्क /हवाई मार्ग से आयात के मामले में, आयातित वस्तुओं को आयात के स्थान पर पहुंचाने से जुड़े परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग शुल्क की लागत एफओबी मूल्य के 20% तक सीमित है।	1,000
बीमा शुल्क	50
मूल्यांकन योग्य मूल्य	5,700
<b>विवरण</b>	<b>राशि (₹)</b>
भारतीय रुपए में मूल्यांकन योग्य मूल्य (विनिमय दर - ₹ 85 प्रति डॉलर)	4,84,500

19. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 में आगे यह प्रावधान है कि आयातक को अंतिम मूल्यांकन आदेश के परिणामस्वरूप देय किसी भी राशि पर, उस माह के पहले दिन से, जिसमें शुल्क का अंतिम मूल्यांकन किया गया है, भुगतान की तिथि तक 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

तदनुसार, देय ब्याज की राशि होगी:

$$= [₹ 50,000 \times 15\% \times 51/365] + [₹ 50,000 \times 15\% \times 62/365]$$

$$= ₹ 1,048 + ₹ 1,274 = ₹ 2,322$$

20. धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार आयात शुल्क का भुगतान किए बिना गोदाम में रखे गए माल का निर्यात किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, जहाज से लाए गए सामान, जो केवल निर्यात हेतु हैं; पुनः निर्यात के लिए रखे गए सामान और शुल्क मुक्त दुकानों को आपूर्ति किए गए सामान आदि। धारा 69 में प्रावधान है कि किसी भी गोदाम में रखे गए माल को आयात शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर किसी स्थान पर निर्यात किया जा सकता है, यदि:

- (क) ऐसे माल के संबंध में शिपिंग बिल या निर्यात बिल या धारा 84 के तहत निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है;
- (ख) ऐसे माल के संबंध में देय निर्यात शुल्क, जुर्माना और दंड का भुगतान कर दिया गया है; तथा
- (ग) निर्यात हेतु ऐसे माल की निकासी के लिए उचित अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है। निर्यात के लिए गोदाम में रखे माल की निकासी के लिए आदेश उचित चयन मानदंडों के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दिया जा सकता है।

यदि भारत सरकार की यह राय है कि किसी निर्दिष्ट विवरण का माल भारत में तस्करी करके वापस लाया जा सकता है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसा माल:

- (i) शुल्क या अन्य भुगतान के बिना भारत से बाहर किसी भी स्थान पर निर्यात नहीं किया जाएगा।
- (ii) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए निर्यात की अनुमति दी जाएगी।



## प्रश्न-पत्र – 6: एकीकृत व्यावसायिक समाधान



### प्रश्न

#### केस स्टडी 1

#### सिक्वोर एगोकेमिकल लिमिटेड (एसएएल)

सिक्वोर एगोकेमिकल लिमिटेड (एसएएल) उर्वरकों में इस्तेमाल होने वाले एगोकेमिकल रसायनों का उत्पादन करती है। फसल पोषण व्यवसाय (कॉर्प न्यूट्रिशन बिजनेस - सीएनबी) के रूप में जानी जाने वाली इस कंपनी के पास 20 उत्पादों का पोर्टफोलियो है जिससे किसानों की विभिन्न ज़रूरतों के लिए विभिन्न ग्रेड के उर्वरक मिलते हैं। फसल पोषण किसी भी कृषि कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसका फसल की उत्पादकता और स्थिरता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फसल की उपज को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्वों का ठीक से प्रबंधन आवश्यक है। बढ़ती आबादी की खाद्य ज़रूरतों के कारण फसल की उपज को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती बन गई है। इसलिए, एसएएल जैसी कंपनियों को यह सुनिश्चित करने हेतु अच्छे ग्रेड के उर्वरक प्रदान करने की आवश्यकता है कि किसान अपनी खेती संबंधी गतिविधि से फसल की उपज को बढ़ा सकें।

#### सरकारी अनुदान

एसएएल सरकार की वित्तीय सहायता से कई परियोजनाओं को करती है। इसे जारी शोध और विकास पहलों के लिए अप्रैल 2024 में 5 करोड़ रुपये के दो अनुदान प्राप्त हुए। पहला बिना शर्त अनुदान "उर्वरकों के दुरुपयोग के कारण मिट्टी के क्षरण" पर शोध से संबंधित है, जो पंजाब में एक तय कृषि क्षेत्र में मिट्टी के अम्लीकरण, सख्त होने तथा प्रदूषण जैसे अत्यधिक उर्वरक उपयोग के दीर्घकालिक प्रभावों पर केंद्रित है। हालाँकि, 31 मार्च, 2025 तक, इस शोध को शुरू करने हेतु कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। दूसरा अनुदान फसल-विशिष्ट पोषण समाधानों के व्यावसायिक विकास का समर्थन करता है, जो उपज बढ़ाने और देश की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने हेतु फसल की विविधता और विकास चरण के आधार पर अनुरूप पोषक तत्व प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एसएएल को इस शोध की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता पर पूरा भरोसा है और

उम्मीद है कि यह उत्पाद अप्रैल 2026 तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा, सितंबर 2024 में, भूकंप के कारण एसएएल की एक फैक्ट्री में उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे दो महीने तक बंद रहना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रभावित विनिर्माण संस्थाओं के लिए एक मुआवजा पैकेज शुरू किया, जिसके तहत एसएएल को पिछले तीन महीनों की औसत बिक्री के आधार पर मुआवजे का दावा करने का अधिकार मिला। इस राहत का लाभ उठाने के लिए, एसएएल को 30 मई, 2025 तक आवश्यक आंकड़ों के साथ आवेदन पेश करना था। हालाँकि, 31 मई, 2025 को जब एसएएल के वित्तीय विवरण अपनाए गए, तब तक दावा फॉर्म जमा नहीं किया गया था।

### कुछ विशिष्ट फसलों के लिए अनुकूलित सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण उर्वरकों का विकास

काफी शोध के बाद, एसएएल ने अनुकूलित सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण उर्वरक विकसित किए हैं जो कुछ मिट्टी के प्रकार और फसल की किस्म की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने हेतु डिज़ाइन किए गए हैं। ये विशेष उर्वरक हैं जो फसल या मिट्टी की विशिष्ट पोषक तत्वों की ज़रूरतों के साथ उर्वरकों को समृद्ध करके और मिश्रित करके बनाए जाते हैं। वे अच्छी फसलों के विकास को बढ़ावा देते हैं और मिट्टी के पोषण को बढ़ाते हैं। हाल के वर्षों में, फसल की पैदावार और मिट्टी की उत्पादकता में सुधार करने के लिए, ऐसे विशेष उर्वरकों पर बहुत सारे शोध और विकास किए गए हैं। वे किसी भी सरकारी सब्सिडी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। निर्माता अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय कर सकता है और आवश्यकतानुसार छूट भी दे सकता है।

हाल ही में, एसएएल ने बाजार में ऐसे उर्वरकों के 3 नए ग्रेड पेश किए हैं। तीनों ग्रेड का उपयोग मुख्य रूप से सब्ज़ियाँ उगाने हेतु किया जा सकता है। एसएएल ने इन उत्पादों को सीमित पैमाने पर लॉन्च करके बाजार में इनकी मांग को जानने का फैसला किया है।

अप्रैल 2025 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, बिक्री प्रबंधक श्री रे ने सेल्स वैल्यूम रिपोर्ट देखी। एसएएल ने वर्ष के दौरान सभी 3 ग्रेड की 11,000 यूनिट्स बेची थीं, यह उस अवधि हेतु 10,000 यूनिट्स के बजट से अधिक थी। श्री रे ने वर्ष के लिए अच्छा बोनस पाने के लिए अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में इसका उल्लेख करने का सोचा। उन्होंने बिक्री प्रदर्शन का विश्लेषण करने में मदद हेतु कंपनी के प्रबंधन खाते श्री बोस से संपर्क किया है।

वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रेड 1 की 2,000 किलोग्राम, ग्रेड 2 की 3,000 किलोग्राम और ग्रेड 3 की 5,000 किलोग्राम की बिक्री का अनुमान लगाया गया है, जो कुल मिलाकर 10,000 किलोग्राम है। मूल्य ग्रेड 1 की प्रति किलोग्राम औसत बिक्री 500 रुपये, ग्रेड 2 की 300 रुपये और ग्रेड 3 की 200 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रति किलोग्राम प्रत्यक्ष सामग्री लागत क्रमशः ग्रेड 1, 2 और 3 के लिए ₹150, ₹100, और

₹75 पर बजट की गई थी, जबकि प्रत्यक्ष श्रम लागत तीन ग्रेड के लिए ₹100, ₹60, और ₹75 प्रति किलोग्राम पर अनुमानित थी। ग्रेड 1 की परिवर्तनीय ओवरहेड लागत ₹50 प्रति किलोग्राम, ग्रेड 2 की ₹40 प्रति किलोग्राम और ग्रेड 3 की ₹10 प्रति किलोग्राम होने की उम्मीद थी।

इसके विपरीत, वर्ष हेतु वास्तविक बिक्री ग्रेड 1 की 2,500 किलोग्राम, ग्रेड 2 की 3,100 किलोग्राम और ग्रेड 3 की 5,400 किलोग्राम रही, जिससे कुल बिक्री 11,000 किलोग्राम हो गई। ग्रेड 1 की प्रति किलोग्राम औसत बिक्री मूल्य 450 रुपये, ग्रेड 2 की 280 रुपये और ग्रेड 3 की 180 रुपये था। ग्रेड 1 की प्रति किलोग्राम प्रत्यक्ष सामग्री लागत 170 रुपये, ग्रेड 2 की 120 रुपये और ग्रेड 3 की 95 रुपये तक बढ़ गई। इस बीच, प्रत्यक्ष श्रम लागत ग्रेड 1, 2 और 3 हेतु क्रमशः 100 रुपये, 60 रुपये और 75 रुपये प्रति किलोग्राम पर बजट के अनुरूप बनी रही। इसी तरह, परिवर्तनीय ओवरहेड लागत संबंधित ग्रेड हेतु 50 रुपये, 40 रुपये और 10 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही।

श्री रे की बिक्री संबंधी मुख्य जिम्मेदारी उर्वरकों के इन ग्रेड तक ही सीमित है। इन उत्पादों के नया होने के कारण, एसएएल के प्रबंधन ने उत्पादों को इन्वेंट्री के रूप में स्टॉक न करने का फैसला किया क्योंकि वे पहले मांग और बाजार की स्थितियां जानने चाहते थे। बल्कि केवल इन उत्पादों के लिए, एसएएल ने खरीद और उत्पादन हेतु जस्ट इन टाइम सिस्टम का पालन किया और कोई इन्वेंट्री नहीं रखी है। श्री रे विभिन्न क्षेत्रों और एसएएल के उत्पादन विभाग में थोक विक्रेताओं के साथ एक मध्यस्थ के रूप में समन्वय करते हैं। श्री रे विनिर्माण प्रक्रिया के किसी अन्य कार्य या संचालन के प्रभारी नहीं हैं।

#### विशिष्ट फसलों के लिए अनुकूलित सूक्ष्मपोषक मिश्रण उर्वरकों का बिक्री अभियान

उपरोक्त ग्रेड ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 विभिन्न प्रकार के उर्वरक हैं जो किसान की ज़रूरतों के आधार पर एक दूसरे का विकल्प बन सकते हैं। एसएएल ने सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्स एवं मार्केटिंग अभियान शुरू किया जिससे उन्हें पूरे देश में किसानों तक सीधे पहुंचने में मदद मिली। इस अभियान का नेतृत्व श्री रे ने किया था। ऐसा समझने हेतु किया गया था कि उत्पाद मूल्य निर्धारण इन ग्रेडों में से प्रत्येक की बिक्री को कैसे प्रभावित कर सकता है। चूंकि उत्पाद समान हैं, इसलिए एसएएल को उम्मीद है कि उत्पाद का मूल्य बिक्री में प्राथमिक भूमिका निभाएगा। जानने हेतु, कंपनी किसी उत्पाद को मूल्य संवेदनशील तभी मानती है जब मूल्य में परिवर्तन के कारण बिक्री की मात्रा पर 5% का प्रभाव पड़ता है।

अभियान के दौरान, एसएएल ने एक निश्चित सीमा से अधिक थोक खरीद पर थोड़ी अधिक छूट की पेशकश की। इससे बिक्री की मात्रा को बढ़ाने में मदद मिली। अतिरिक्त छूट नीति को बजट में शामिल नहीं किया गया था। अभियान ने एसएएल को अच्छे सेल्स कर्मियों की समस्या से निपटने में भी मदद की, जिन्हें हाल के दिनों में ढूँढना मुश्किल हो गया था। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी विशेष किस्म के उर्वरक की मांग

में अचानक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उस मौसम में उस फसल को उगाने और बेचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं।

बिक्री की मात्रा को बढ़ाने वाले सफल सेल्स एवं मार्केटिंग अभियान के साथ, खरीद विभाग को मौजूदा कीमतों पर खुले बाजार से कच्चा माल खरीदना पड़ा। आम तौर पर, मौजूदा प्रचलित बाजार कीमतें जेआईटी आपूर्तिकर्ता भागीदारों के साथ सहमत कीमतों से अधिक होती हैं।

### उर्वरकों के प्रभावी उपयोग हेतु शैक्षिक और प्रचार अभियान

फसल की पैदावार तभी बढ़ सकती है जब किसान उर्वरकों का ठीक से उपयोग करें। कस्टमाइज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर्स के बारे में बहुत अधिक जागरूकता नहीं है। कस्टमाइज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर्स के उपर्युक्त ग्रेड में किसानों की कृषि उत्पादकता में सुधार करने की क्षमता है। एसएएल के प्रबंधन को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे कस्टमाइज्ड मिक्सचर फर्टिलाइजर्स की मांग बढ़ेगी। इसलिए ऐसे संभावित उत्पादों को बढ़ावा देना, किसानों और कृषिविदों के बीच उनके बारे में शिक्षित करना और जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण था।

उपरोक्त जैसे सेल्स अभियान इन उत्पादों में शुरुआत में रुचि उत्पन्न करने में सहायक रहे हैं। वे प्रकृति में अधिक अस्थायी व मौसमी हैं। इन उर्वरकों की अनुप्रयोग तकनीकों के बारे में उचित जागरूकता से नियमित बिक्री बढ़ेगी। इसके लिए एसएएल को किसानों को शिक्षित करके और उन्हें इन उत्पादों के बारे में जागरूक करके उनके साथ बेहतर ढंग से जुड़ना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने कृषि भूमि का एक हिस्सा खरीदा, जिसका उपयोग विशेष रूप से किसानों के लिए उर्वरक अनुप्रयोग तकनीकों को प्रदर्शित करने हेतु किया गया था। एसएएल के विशेषज्ञों से सीधे समझने से, किसान इन उर्वरकों के संभावित लाभों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये प्रचार कार्यक्रम लगभग पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं, जहाँ मौसम के आधार पर, उर्वरकों को उस फसल के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद, ऐसे आयोजनों में भाग लेने वाले कई किसान अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ऐसे आयोजनों में स्टॉल से ऐसे अनुकूलित उर्वरक खरीदते हैं। इस भूमि पर वास्तव में कोई कृषि उत्पादन नहीं होता है।

### वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2025 तक, एसएएल के पास 5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी; 4 करोड़ रुपये का रिजर्व व अधिशेष; 16 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण; 0.2 करोड़ रुपये का व्यापार देय है। एसएएल ने 9 करोड़ रुपये का ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) हासिल करके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है; वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान किया गया

ब्याज 1.12 करोड़ रुपये है। कॉर्पोरेट कर की दर 30% है; इक्विटी की लागत 12.50% और ऋण की लागत 4.9% है।

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का ठीक से मूल्यांकन करने और सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए, एसएएल पूंजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी) को एक प्रमुख मीट्रिक के रूप में उपयोग करता है। हर समय, प्रबंधन पूंजी के सभी स्रोतों (ऋण व इक्विटी) में कंपनी के संचालन के वित्तपोषण की औसत लागत को 10% से कम रखना चाहता है।

#### विनियामक जांच: अनुलग्नक 1 देखें

अपने पोर्टफोलियो में 20 उत्पादों में से, एसएएल 3 ऐसे उत्पाद बेचता है जिनमें लाल लेबल है और 2 ऐसे उत्पाद हैं जिनमें पीला लेबल है। ऐसे उत्पाद उच्च मार्जिन उत्पन्न करते हैं और अब तक उन्होंने एसएएल के वार्षिक राजस्व में लगभग 25% का योगदान दिया है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) ने हाल के वर्षों में समय-समय पर इन उत्पादों के बारे में पूछताछ और जांच की है। इन हानिकारक उत्पादों की बढ़ती जांच के कारण, एसएएल के प्रबंधन ने उन्हें धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो से बाहर करने का फैसला किया है। उनके उत्पादन को रोकने पर, अल्पावधि में राजस्व में न्यूनतम 25% की कमी आने की संभावना है। इस बीच, एसएएल पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सुरक्षित उत्पाद बनाने हेतु आरएंडडी में निवेश करने की योजना बना रहा है। पीएएल जो उसी उद्योग में एसएएल का प्रतिस्पर्धी है, उसकी भी वार्षिक राजस्व का लगभग 30% हिस्सा लाल एवं पीले लेबल वाले उत्पादों की बिक्री से होता है। सीआईबी ने हाल ही में पीएएल द्वारा निर्मित इन अत्यधिक विषैले उत्पादों की जांच शुरू की है। फिर भी, पीएएल, उनके उच्च मार्जिन वाले उत्पाद होने के कारण, निकट भविष्य में प्रतिबंध लगाए जाने की नियामक चिंताओं के बावजूद इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है। पीएएल को उम्मीद है कि आगामी वर्ष में राजस्व में न्यूनतम 10% की वृद्धि होगी।

#### अनलिमिटेड यूरिया लिमिटेड (यूयूएल) के साथ विलय: अनुलग्नक 2 देखें

एसएएल (हस्तांतरित कंपनी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 235 के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से यूयूएल (हस्तांतरक कंपनी) के शेयरों का अधिग्रहण करके उसका अधिग्रहण करने का फैसला किया। एसएएल ने एक योजना तैयार की जिसके तहत यूयूएल के शेयरधारकों को एक ऑफर दिया गया। यह ऑफर 1 अगस्त 2024 को दिया गया। यह ऑफर 4 महीने तक खुला रहा और इसे 92% शेयरों के मूल्य वाले शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके बाद, एसएएल ने शेष असहमत शेयरधारकों को नोटिस दिया कि वह उनके शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है। ऐसा नोटिस 5 जनवरी 2025 को दिया गया था। कुछ असहमत शेयरधारकों ने न्यायाधिकरण में आवेदन दिया कि उनके शेयरों के अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने आवेदन को खारिज कर दिया। इसलिए, एसएएल ने असहमत शेयरधारकों के 5% शेयर (शेष 8% में से) हासिल कर लिए। शेष 3% शेयरधारकों की हिस्सेदारी असहमत शेयरधारकों के पास ही बनी रही।

### अनुलग्नक 1:



## स्टेट टाइम्स

### कृषि रसायनों के छिपे खतरे



जयपुर, 21 फरवरी 2025 – दुनिया की बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने हेतु किफ़ायती दामों पर भरपूर फ़सल इस समय बहुत जरूरी है। कृषि रसायनों, विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करें, जिससे फ़सल से अधिक उपज सुनिश्चित हुआ है। रासायनिक सूत्र सटीक और विशेषज्ञता से बनाए जाते हैं, जो इच्छित उपयोग पर निर्भर करते हैं, और वे अपेक्षाकृत लागत प्रभावी होते हैं। इससे दुनिया भर के किसानों को अपनी फ़सल उत्पादन पर नियंत्रण पाने में मदद

मिली है। अल्पावधि में किसान अधिक और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें पैदा कर सकते हैं। हालांकि, इन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग लंबे समय में मिट्टी के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। वे भूजल और अन्य जल स्रोतों में रिस सकते हैं जिससे संदूषण हो सकता है, जो लंबे समय में विषाक्त हो सकता है। नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों का जलवायु परिवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इससे जैव विविधता को भारी नुकसान हुआ है।

मानव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आती हैं क्योंकि उर्वरकों के उपयोग के कारण फसलें उतनी पोषिक नहीं होतीं जितनी होनी चाहिए। इससे वयस्कों और बच्चों में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इनके उपयोग से तंत्रिका, अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित होती है, खासकर कीटनाशकों के उपयोग से। पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा समुदाय द्वारा कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।

हाल के महीनों में भारत में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग पर बहुत अधिक जन आक्रोश और बहस देखी गई है। कंपनियों को उनके उत्पादों को उनकी विषाक्तता के आधार पर लेबल करने हेतु मजबूर करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। कृषि रसायनों (उर्वरकों सहित) के मानव स्वास्थ्य और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले गहरे, कभी-कभी प्रतिकूल प्रभाव के कारण, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) ने लेबलिंग प्रणाली के आधार पर कृषि रसायन विषाक्तता के स्तरों को - लाल, पीले, नीले और हरे रंग के लेबल का उपयोग करते हुए वर्गीकृत किया है - जहाँ लाल सबसे अधिक जहरीला है जबकि हरा सबसे कम जहरीला है। इसके अलावा, नकली उत्पादों को रोकने के लिए कंपनियाँ अपने उत्पाद पैकेजिंग की पहचान करने हेतु बारकोड या पहचान के अन्य तकनीकें इस्तेमाल कर रही हैं।

हाल के वर्षों में लाल लेबल वाले उत्पादों पर बहुत ज्यादा जांच की गई है, क्योंकि उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों में काफी नाराज़गी है। विनियामक प्राधिकरण इन उत्पादों के उपयोग को काफी हद तक कम कर रहे हैं और धीरे-धीरे पीले लेबल वाले उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसकी संभावना अधिक है कि ईएसजी दिशा-निर्देशों के अनुसार निकट भविष्य में इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सभी पैकेजों पर लेबल लगे होते हैं, ताकि उपयोगकर्ता उनके विषाक्तता स्तर की पहचान कर सकें। इसके बावजूद कुछ कंपनियाँ ऐसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफी लाभदायक हैं।

## अनुलग्नक 2:



### क्रॉनिकल

**1,000 करोड़ रुपये में अनलिमिटेड यूरिया लिमिटेड का अधिग्रहण करेगा सिक्योर एग्नोकेमिकल्स लिमिटेड**



जयपुर, 2 सितंबर 2024 - अनलिमिटेड यूरिया लिमिटेड (यूयूएल) अपनी कंपनी को सिक्योर एग्नोकेमिकल्स लिमिटेड (एसएएल) को बेचने जा रही है। राजस्थान के कोटा जिले के गड़ेपान में स्थित अनलिमिटेड यूरिया लिमिटेड (यूयूएल) का स्वामित्व बदलने जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपने पूरे टर्नओवर को सिक्योर एग्नोकेमिकल लिमिटेड (एसएएल) को 1,000 करोड़ रुपये में बेचने की बात कही है।

कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अनिवार्यताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई और एनएसई को अनिवार्य प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में जानकारी का प्रकटीकरण किया। प्रकटीकरण में कहा गया है कि निदेशक मंडल ने अपनी हालिया बैठक में एसएएल को अपने व्यवसाय की बिक्री को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सहमत प्रतिफल मूल्य 1,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। नोटिस में कहा गया है कि बिक्री शेरधारकों, अन्य विनियामक और वैधानिक अनुमोदन और वित्तीय परिश्रम से अनुमोदन के अधीन है।

यह अधिग्रहण महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई निवेश नीति (एनआईपी) की घोषणा की थी। एसएएल उर्वरक उद्योग में एक सुस्थापित कंपनी है, इसके पोर्टफोलियो में रासायनिक और जैविक उर्वरक और फसल पोषण समाधान दोनों हैं। यूयूएल के यूरिया व्यवसाय का अधिग्रहण इसके व्यवसाय के भीतर वैल्यू अनलॉक करने को बढ़ावा देगा। हाल के भू-राजनीतिक तनावों ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा किया है और यूरिया सहित कच्चे माल की कीमत आसमान छू रही है। कैपिटल स्वामित्व वाली यूरिया विनिर्माण इकाई होने से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मूल्य में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

## बहु विकल्पीय प्रश्न

1.1 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

- (i) वास्तविक सामग्री खरीद बजट से अधिक होने का एक कारण यह है कि एसएएल को जेआईटी खरीद के बाद एसएएल द्वारा सफल मार्केटिंग अभियान के कारण प्रत्याशित मांग से अधिक की पूर्ति करनी पड़ी।
- (ii) श्री रे प्रत्येक ग्रेड के उर्वरक की बिक्री से प्राप्त योगदान के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं।
- (iii) जेआईटी उत्पादन प्रणाली हमेशा उपयुक्त नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ उत्पादों की मौसमी मांग में अचानक वृद्धि के उदाहरण हैं जो फसलों की बढ़ती मौसमी स्थितियों पर निर्भर करते हैं। उत्पादन विभाग अपने वार्षिक नियोजन बही में इसका हिसाब नहीं रख सकता है।
- (iv) कच्चे माल की जेआईटी खरीद उपयुक्त है, क्योंकि उत्पादन भी समय पर किया जाता है।

## विकल्प:

- (क) (i) और (iii)
  - (ख) (i), (ii) और (iii)
  - (ग) (i), (iii) और (iv)
  - (घ) (ii), (iii) और (iv)
- 1.2 अत्यधिक विषैले लाल और पीले लेबल वाले उत्पादों की बिक्री के संदर्भ में, वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में एसएएल और पीएएल के लेखापरीक्षकों को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए?
- (i) एसएएल और पीएएल के लेखापरीक्षकों को कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तदनुसार बनाया जाना चाहिए।
  - (ii) एसएएल और पीएएल के लेखापरीक्षकों को कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन उत्पादों पर भारत में स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं है।

- (iii) पीएएल के लेखापरीक्षकों को एसए 250 को ध्यान में रखना होगा, जहां कानूनों और विनियमों का अनुपालन न करने पर जुर्माना और मुकदमेबाजी या अन्य परिणाम हो सकते हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
- (iv) एसएएल के लेखापरीक्षकों को इन उत्पादों के चरणबद्ध तरीके से बंद होने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे राजस्व पर 25% तक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, कंपनी इस निर्णय के बाद राजस्व में कमी के बावजूद पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित उत्पादों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने की योजना बना रही है।

**विकल्प:**

- (क) (i) और (iv)
- (ख) (ii) और (iv)
- (ग) (i) और (iii)
- (घ) (ii), (iii) और (iv)
- 1.3 बिक्री भिन्नता विश्लेषण के आधार पर, प्रबंधन को भविष्य में छूट हेतु किस उत्पाद को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि निरंतर लाभप्रदता सुनिश्चित करते हुए बिक्री की मात्रा को अधिकतम किया जा सके?
- (क) ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्योंकि इन दोनों ने बिक्री की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ सकारात्मक शुद्ध योगदान भी दिया है।
- (ख) ग्रेड 1 और ग्रेड 3, क्योंकि ये दोनों ही मूल्य के प्रति संवेदनशील हैं, तथा कंपनी द्वारा विश्लेषण के लिए 5% की सीमा निर्धारित की गई है।
- (ग) ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 क्योंकि दी गई छूट के कारण सभी मामलों में मात्रा में वृद्धि हुई।
- (घ) केवल ग्रेड 1, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो मूल्य के प्रति संवेदनशील है और साथ ही अधिक मार्जिन के कारण सकारात्मक योगदान देने की क्षमता रखता है।
- 1.4 एस.ए.एल. द्वारा यू.यू.एल. के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा?
- (क) एसएएल द्वारा यूयूएल का अधिग्रहण वैध है, क्योंकि न्यायाधिकरण ने असहमत शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है।

- (ख) एसएएल द्वारा यूयूएल का अधिग्रहण अवैध है, क्योंकि न्यायाधिकरण द्वारा असहमत शेयरधारकों द्वारा किए गए आवेदन को खारिज करने के बाद भी, यूयूएल ने कुल 8% असहमत शेयरधारकों में से केवल 5% के शेयर ही हासिल किए।
- (ग) एसएएल द्वारा यूयूएल का अधिग्रहण वैध है, क्योंकि 92% शेयरधारिता मूल्य वाले शेयरधारकों ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और यह एसएएल से प्रस्ताव प्राप्त होने के 4 महीने के भीतर किया गया था।
- (घ) एसएएल द्वारा यूयूएल का अधिग्रहण अवैध है, क्योंकि 8% शेयरधारिता मूल्य वाले शेयरधारकों ने अधिग्रहण पर असहमति जताई है और वे कानूनी रूप से अपना स्वामित्व एसएएल को सौंपने के लिए बाध्य नहीं हो सकते।
- 1.5 \* निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ऐसी रणनीतिक, मूल्य-वर्द्धक पहल का प्रतिनिधित्व करती है जो एस.ए.एल. को उसकी आपूर्ति श्रृंखला में दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती है?
- (क) मांग पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों के कारण ऑर्डर जल्दी आ जाते हैं या कच्चे माल की खरीद में देरी हो जाती है।
- (ख) डीलरों को भेजने से पहले तैयार माल को देश भर के गोदामों में भंडारित करना।
- (ग) विनियामक अनुपालन को पूरा करने के लिए तैयार माल का नियमित निरीक्षण।
- (घ) पोषक तत्व दक्षता में सुधार, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु बनाए गए उन्नत फॉर्मूलेशन के लिए पेटेंट दाखिल करने हेतु कानूनी शुल्क।
- 1.6 इन स्टालों पर ऐसे कस्टमाइज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर्स की बिक्री से एसएएल की आय को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए?
- (क) यह आय कृषि आय के रूप में योग्य है, क्योंकि एसएएल ने खेती में उर्वरक के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण किया था।
- (ख) यह आय कृषि आय के रूप में तभी योग्य मानी जाएगी जब एसएएल के उर्वरकों का उपयोग कृषि उत्पादन के लिए अधिग्रहीत भूमि पर किया गया हो।

- (ग) यह आय कृषि आय के रूप में योग्य नहीं है तथा कृषि भूमि अर्जित करने के बावजूद "व्यापार या पेशे से लाभ व प्राप्ति" के अंतर्गत व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य है।
- (घ) यदि एसएएल द्वारा बेचे गए उर्वरकों का उपयोग अधिग्रहित भूमि पर प्रशिक्षित किसानों द्वारा किया जाता है तो आय को आंशिक रूप से कृषि आय माना जा सकता है।

\* अतिरिक्त प्रश्न

#### वर्णनात्मक प्रश्न

- 1.7 31 मार्च 2025 तक एसएएल की लेखा बही में प्राप्त दो अनुदानों एवं भूकंप-संबंधी मुआवजे के लिए उचित लेखांकन प्रावधान, यदि कोई हो, की सलाह दें।
- 1.8 बजटीय एवं वास्तविक योगदानों का विस्तृत विचरण विश्लेषण करें। विचरण का कारण बनने वाले सभी तत्वों का व्यापक विवरण बताएं, जैसे कि मात्रा में अंतर, बिक्री मूल्यों में भिन्नता, लागत संरचनाओं में परिवर्तन एवं छूट रणनीतियों का प्रभाव।
- 1.9 दिए गए आँकड़ों के आधार पर एसएएल के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करें।

#### केस स्टडी 2

##### डायमंड लिमिटेड

डायमंड लिमिटेड, एक सूचीबद्ध कंपनी है जो भारत के ऑर्गनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल सेक्टर में एक अग्रणी कंपनी है, जो हीरे, कीमती पत्थरों, हीरे जड़े आभूषणों के साथ-साथ वस्तुओं के व्यापार, निर्माण और बिक्री के विविध व्यवसाय के लिए जानी जाती है। प्रमाणित हीरे के आभूषणों पर विशेष ध्यान देते हुए कंपनी कई तरह के आभूषण बनाती है। उनके प्रोडक्ट विभिन्न मार्केट सेगमेंट में जाते हैं, जिसमें शादी के आभूषण, पार्टी वियर और दैनिक पहनने वाले आभूषण शामिल हैं, जो विभिन्न अवसरों पर ग्राहकों के लिए चुनने के कई विकल्प देते हैं। प्रमाणित हीरों पर यह ध्यान कंपनी के मूल्य प्रस्ताव का केंद्र है, जो अपने ग्राहकों के लिए गुणवत्ता और विश्वास सुनिश्चित करता है।

##### व्यवसाय संरचना और रणनीति

होल्टिंग कंपनी के रूप में डायमंड लिमिटेड, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के विविध पोर्टफोलियो की देखरेख करती है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने हेतु इसे विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति मिलती है। कंपनी एक विकेन्द्रीकृत प्रबंधन संरचना का पालन करती है, तथा अपने डिवीजनों या शाखाओं के भीतर नामित कार्मिकों को दैनिक परिचालन और निर्णय लेने की जिम्मेदारियां सौंपती है। इस दृष्टिकोण से स्वायत्तता तथा

जवाबदेही बढ़ती है, और यह भी सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक डिवीजन के उद्देश्य कंपनी के व्यापक रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। जिम्मेदारी केंद्रों के रूप में काम करके, प्रबंधकों को उनके संबंधित डिवीजनों के प्रदर्शन, परिणामों और लाभप्रदता के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। यह संरचना डायमंड लिमिटेड को अपने व्यापक व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित रहते हुए अपने विविध संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करती है।

अपने रणनीतिक विस्तार तथा आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूल बनाने हेतु, डायमंड लिमिटेड ने कई अधिग्रहण किए हैं। कुछ साल पहले, कंपनी ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन रणनीति के ज़रिए रिटेल सेगमेंट में विशेषज्ञता वाली कंपनी जिरकोन लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण ने डायमंड लिमिटेड को जिरकोन लिमिटेड की विशेष रिटेल विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने की सुविधा दी, जिससे अंतिम उपभोक्ता बाजार में ब्रांड की उपस्थिति मजबूत हुई। जिरकोन की क्षमताओं को एकीकृत करके, डायमंड लिमिटेड ने अपने आभूषण उत्पादों को प्रभावी ढंग से बेचने की अपनी क्षमता को बढ़ाया, जिससे विनिर्माण से लेकर खुदरा तक निर्बाध फ्लो सुनिश्चित हुआ।

#### वैश्विक स्तर पर विस्तार और उत्पाद संरेखण

डायमंड लिमिटेड ने 2023 में इटली की एक प्रसिद्ध कंपनी रिटेल जेम्स स्पा का अधिग्रहण करके अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया। कंपनी वर्तमान में आकलन कर रही है कि क्या रिटेल जेम्स को डायमंड लिमिटेड के अहमदाबाद डिवीजन द्वारा निर्मित हीरे जड़ित आभूषण आइटम जेम-इंडो खरीदना चाहिए। अहमदाबाद डिवीजन की जेम-इंडो की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,20,000 यूनिट्स की है, जबकि रिटेल जेम्स, अपनी कम विनिर्माण क्षमता के साथ, एक समान आइटम जेम-मिलानो का उत्पादन कर सकता है, जो सालाना 50,000 यूनिट्स तक है। इतालवी बाजार में, जेम-मिलानो के समान आइटम हेतु स्थानीय खरीद मूल्य €1,600 (₹1,44,000 के बराबर) प्रति यूनिट है। हालाँकि, डायमंड लिमिटेड अपने आइटम (यानी, उत्पाद) को अहमदाबाद डिवीजन से रिटेल जेम्स में स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता का पता लगा रहा है, जो इतालवी सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। इस तरह के हस्तांतरण हेतु इटली डिवीजन की लागत €1,700 (₹1,53,000 के बराबर) प्रति यूनिट होगी। इस कीमत में सभी संबंधित लागतें शामिल हैं, जैसे कि शुल्क, कर और हैंडलिंग शुल्क। भारत में बाहरी बिक्री हेतु जेम-इंडो की कीमत 1,08,000 रुपये प्रति यूनिट है। जब इसे उचित रूप से मोडिफाइट वर्जन में रिटेल जेम्स को बेचा जाता है, तो लेनदेन €1,400 प्रति यूनिट की आर्म्स लेंथ कीमत पर किया जाता है। जेम-मिलानो की कुल 50,000 यूनिट रिटेल जेम्स को हस्तांतरित की जा रही हैं, जो अहमदाबाद डिवीजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अहमदाबाद डिवीजन की वर्तमान बिक्री मात्रा 1,00,000 यूनिट है। भारत में जेम-इंडो के लिए प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत बाह्य बिक्री हेतु 80,000 रुपये है। हालाँकि, जेम-इंडो को रिटेल जेम्स में स्थानांतरित करने के लिए, प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत 74,000 रुपये है, जो आंतरिक हस्तांतरण व्यवस्था से संभावित दक्षता या बचत को

दर्शाती है। इसके अलावा, इतालवी सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आइटम को संशोधित करने हेतु प्रति यूनिट 24,000 रुपये की एडॉप्शन कॉस्ट वहन की जाती है, जो मुख्य रूप से डिज़ाइन में मामूली परिवर्तनों के कारण होती है। दोनों संस्थाओं पर लागू कर की दरें अलग-अलग हैं और लेन-देन की लाभप्रदता को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। अहमदाबाद डिवीजन पर कर की दर 30% है, जबकि इटली में रिटेल जेम्स 40% की उच्च कर दर पर काम करता है। कर दर में यह अंतर दोनों संस्थाओं के वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से लाभप्रदता और कर देनदारियों के संबंध में। यह माना जाता है कि विनिमय दर निकट अवधि में स्थिर रहेगी।

#### सस्टैनबिलिटी और जीवन चक्र लागत निर्धारण

सस्टैनबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, डायमंड लिमिटेड ने अपने उत्पाद रणनीतियों में जीवन चक्र लागत को एकीकृत किया है। इस पद्धति में किसी वस्तु के जीवन चक्र में निवेश, संचालन, रखरखाव एवं निपटान सहित सभी लागतों को ध्यान में रखा जाता है। अपने प्रमुख आइटम "ऑरोरा" के लिए, कंपनी एक व्यापक जीवन चक्र लागत दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जो आइटम के जीवन चक्र में होने वाली सभी लागतों को कवर करती है। इन लागतों में सामग्री हेतु 460 लाख रुपये, अनुसंधान हेतु 100 लाख रुपये, वितरण हेतु 50 लाख रुपये, डेवलपमेंट हेतु 300 लाख रुपये, श्रम हेतु 380 लाख रुपये, ओवरहेड्स हेतु 500 लाख रुपये, निपटान हेतु 30 लाख रुपये, प्रशिक्षण हेतु 500 लाख रुपये, रखरखाव के लिए 170 लाख रुपये, वारंटी दावों के लिए 85 लाख रुपये, डिजाइन व परीक्षण के लिए 200 लाख रुपये और पर्यावरण स्वच्छता हेतु 70 लाख रुपये शामिल हैं। यह समग्र दृष्टिकोण स्थिरता, नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता के संदर्भ में कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

#### लेखापरीक्षा और वित्तीय निरीक्षण

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अमित एंड आमोद एलएलपी को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु डायमंड लिमिटेड का वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। अमित एंड आमोद एलएलपी का मानना है कि व्यावसायिक संचालन में आम तौर पर होने वाले संबंधित पक्ष लेन-देन, वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण या धोखाधड़ी के संभावित जोखिम पैदा करते हैं। इन जोखिमों को संबोधित करने के लिए, लेखापरीक्षक ने डायमंड लिमिटेड की सीएफओ सुश्री रत्ना मलिक को एक ईमेल भेजा, जिसमें संबंधित पक्षों की एक व्यापक सूची और कंपनी की संबंधित पक्ष नीति का अनुरोध किया गया।

ईमेल के माध्यम से उन्हें निम्नलिखित प्रतिक्रिया मिली:

**रत्ना मलिक / मुख्य वित्त अधिकारी / डायमंड लिमिटेड**

**प्रेषक:** "रत्ना मलिक" < ratna@dltd.com >  
**भेजा गया:** 15 अप्रैल 2025 10:00  
**प्राप्तकर्ता:** "भागीदार-1" < amit@aallp.in >  
**प्रतिलिपि:** "माणिक पॉल" <paul@dltd.com>  
**विषय:** संबंधित पक्ष प्रकटीकरण  
**अनुलग्नक:** समूह चार्ट – इंड एस 24. डीएफ; संबंधित पक्ष नीति.पीडीएफ  
**सीए अमित गुप्ता,**

उम्मीद है आप ठीक होंगे!

हमें आपकी कंपनी के संबंधित पक्षों और संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित ईमेल प्राप्त हुआ है।

डायमंड लिमिटेड, अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान, संबंधित पक्ष या पक्षों के साथ लेन-देन करता है। इन संबंधित पक्षों की पहचान लागू कानूनों/लेखा अनिवार्यताओं के अनुसार की गई है। कृपया भारतीय लेखा मानक 24 की अनिवार्यताओं के अनुसार समूह चार्ट हेतु अनुलग्नक देखें।

कंपनी ने संबंधित पक्ष लेन-देन पर एक नीति भी तैयार की है जो कंपनी तथा उसके संबंधित पक्षों के बीच सभी लेन-देन को नियंत्रित करती है। कंपनी की संबंधित पक्ष नीति के प्रासंगिक अंश संलग्न हैं।

हमें उम्मीद है कि उपरोक्त ईमेल से आपको आवश्यक जानकारी मिल गई होगी। यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्री माणिक पॉल से भी संपर्क कर सकते हैं।

धन्यवाद

रत्ना मलिक

अगले दिन, लेखापरीक्षक श्री माणिक पॉल से मिले और चालू व विगत वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए संबंधित पक्ष लेन-देन की एक सूची देने का अनुरोध किया। श्री पॉल ने तुरंत मांगे गए विवरण दे दिए, जो संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है। इसके बाद, लेखापरीक्षकों ने यह सत्यापित करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्रक्रियाओं को बनाया और निष्पादित किया कि संबंधित पक्ष संबंधों और लेन-देन को भारतीय लेखा मानक 24 की अनिवार्यताओं के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरणों में ठीक से चिन्हित, लेखांकित और प्रकट किया गया था। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, लेखा परीक्षकों ने श्री माणिक पॉल और सुश्री रत्ना मलिक को एक ईमेल भेजा।

सी.ए. अमित गुप्ता/भागीदार/अमित एंड आमोद एलएलपी

**प्रेषक:** "भागीदार -1" < amit@aallp.in >

**भेजा गया:** 20 अप्रैल 2025 10:00

**प्राप्तकर्ता:** "रत्ना मलिक" < ratna@dltd.com >

**प्रतिलिपि:** "माणिक पॉल" < paul@dltd.com>; "टीम 1" <audit\_1@aallp.in>

**विषय:** प्रारंभिक लेखापरीक्षा अवलोकन: संबंधित पक्ष

**दिनांक:** 20 अप्रैल 2025



सुश्री रत्ना मलिक और टीम,  
हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में आपकी टीम द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की सराहना करते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने निम्नलिखित बातें पाई हैं:

सैफायर लिमिटेड को संबंधित पक्ष के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है

साझा किए गए समूह चार्ट से, हम समझते हैं कि सैफायर लिमिटेड कोरल लिमिटेड की एक सहायक कंपनी (यानी संयुक्त उद्यम) है। भारतीय लेखा मानक 24 के तहत संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनी एक संबंधित पक्ष है। आपसे अनुरोध है कि कृपया भारतीय लेखा मानक 24 की अनिवार्यताओं - विशेष रूप से भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 12 पर विचार करें।



लेखापरीक्षा समिति की मंजूरी नहीं मिली है

उपरोक्त सादृश्य को जेड लिमिटेड पर लागू किया जाना चाहिए - जो एमराल्ड लिमिटेड (कंपनी की सहयोगी) की एक स्टेप-डाउन सहयोगी है। कंपनी अपने सहयोगी (एमराल्ड लिमिटेड) के माध्यम से स्टेप-डाउन सहयोगी - जेड लिमिटेड पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम होगी। वर्ष के दौरान, कंपनी ने जेड लिमिटेड से 595 लाख रुपये मूल्य के पत्थर के सामान खरीदे हैं। इन संबंधित पक्ष लेन-देन को सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 23 के तहत प्रदान की गई लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति के साथ दर्ज किया जाना चाहिए था। इस बात के बावजूद कि जेड लिमिटेड एमराल्ड लिमिटेड के लिए महत्वपूर्ण इकाई नहीं है, स्वीकृति की आवश्यकता होगी।



केएमपी को गैर-मौद्रिक लाभ

सुश्री रत्ना मलिक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, कंपनी के स्वामित्व वाली कार का उपयोग करती हैं और वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्ष लेनदेन के रूप में इसका प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैं:

- कार का क्रय मूल्य - ₹380 लाख
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुलाभ का मूल्य - ₹35 लाख
- वित्तीय विवरणों में चिन्हित मूल्यहास यानी ₹76 लाख

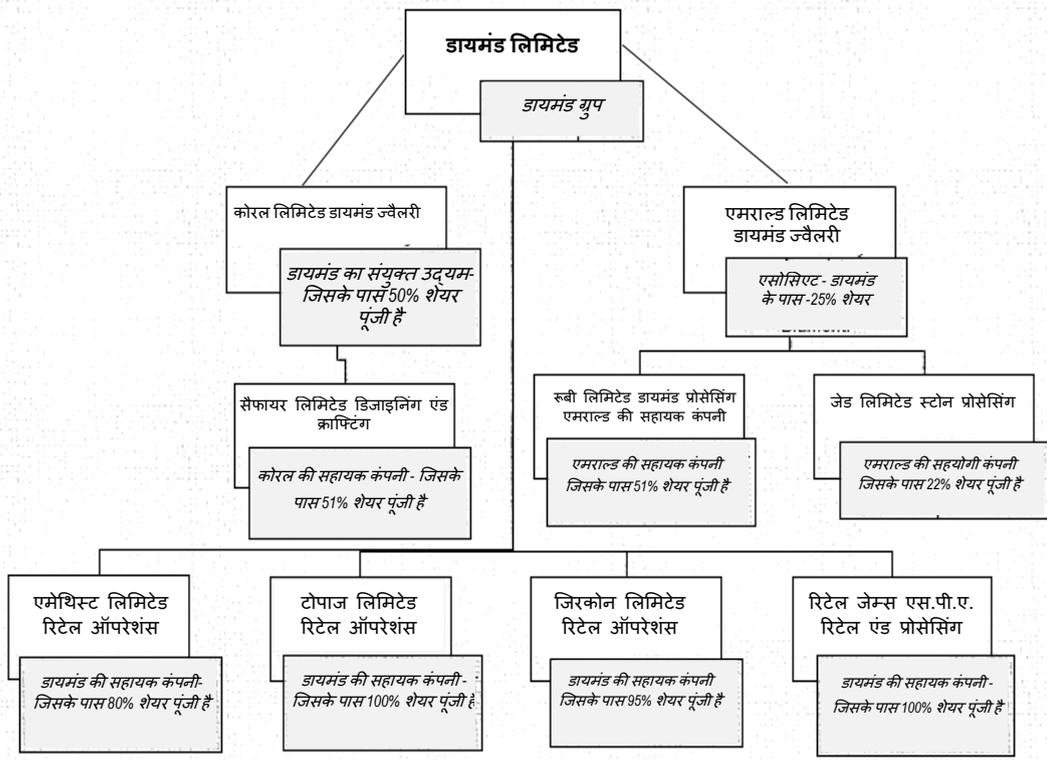


बिक्री बाजार  
दर पर नहीं है

वर्ष के दौरान कंपनी ने सहायक कंपनी जिरकोन लिमिटेड को 20 लाख रुपये मूल्य के हीरे जड़े आभूषण बेचे हैं। वर्ष के दौरान असंबंधित पक्ष को समान मात्रा में 25 लाख रुपये मूल्य के सामान बेचे गए। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन ऑर्म लेन्थ पर नहीं थी। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिरकोन लिमिटेड पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए पात्र नहीं है।

हम आपसे जल्द से जल्द उपरोक्त पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें।  
धन्यवाद,  
अमित गुप्ता

**समूह चार्ट – इंड एस 24. पीडीएफ**



चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारिता संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

संबंधित पक्ष नीति. पीडीएफ



संबंधित पक्षों और  
संबंधित पक्ष  
लेनदेन की  
पहचान

कंपनी तथा उसकी सहायक कंपनियों/सहयोगी/संयुक्त उद्यम के प्रत्येक प्रमोटर, निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को:

- नियुक्ति के समय;
- समय-समय पर - जैसा कि कंपनी या लागू कानून द्वारा अपेक्षित है
- जब भी पहले से प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो अपने रिश्तेदारों और सभी फर्मों, कंपनियों, निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्तियों के अन्य संघों के बारे में अपेक्षित जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिसमें ऐसे प्रमोटर, निदेशक या केएमपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम (जैसा भी मामला हो) में रुचि रखते हैं। प्रत्येक ऐसे प्रमोटर, निदेशक और केएमपी लेनदेन के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करेंगे, जिसे बोर्ड/लेखा परीक्षा समिति उचित रूप से अनुरोध कर सकती है।



संबंधित पक्ष  
लेनदेन की  
समीक्षा और  
अनुमोदन

सभी लेन-देन जिन्हें संबंधित पक्ष लेन-देन के रूप में चिन्हित किया जाता है और उसके बाद के संशोधनों को लागू कानूनों तथा विनियमों के तहत निर्दिष्ट तरीके से लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। लेखा परीक्षा समिति अनुमोदन के लिए संबंधित पक्ष लेन-देन पर विचार-विमर्श करते समय सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी। लेखा परीक्षा समिति का कोई भी सदस्य जो किसी भी संबंधित पक्ष लेन-देन में संभावित हित रखता है, वह खुद को इससे अलग कर लेगा और संबंधित पक्ष लेन-देन के अनुमोदन पर चर्चा और मतदान से दूर रहेगा। ऐसा संबंधित पक्ष लेन-देन जो (i) व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है, या (ii) आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं है, उसके लिए बोर्ड या शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

यदि कंपनी द्वारा किसी संबंधित पक्ष के लेन-देन को बोर्ड के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वह लेन-देन (i) व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है, या (ii) आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं है, तो बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेगा जैसे कि, लेन-देन की प्रकृति, भौतिक शर्तें, मूल्य निर्धारण का तरीका और ऐसे लेन-देन में प्रवेश करने का व्यावसायिक औचित्य और कोई अन्य जानकारी जिसे बोर्ड प्रस्तावित लेन-देन पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण/प्रासंगिक मान सकता है। ऐसे विचार-विमर्श के आधार पर, बोर्ड लेन-देन को मंजूरी दे सकता है या लेन-देन की शर्तों में ऐसे संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि वह परिस्थितियों के तहत उचित समझता है। बोर्ड का कोई भी सदस्य जो किसी संबंधित पक्ष के लेन-देन में कोई रुचि रखता है, वह खुद को इससे अलग कर लेगा और संबंधित पक्ष के लेन-देन के अनुमोदन पर चर्चा और मतदान से दूर रहेगा।

यदि कोई संबंधित पक्ष लेनदेन (i) लिस्टिंग विनियमों के अनुसार एक महत्वपूर्ण लेनदेन है, या (ii) व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है, या आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं है और कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित कुछ सीमाओं से अधिक है, तो ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन और उसके बाद के किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन के लिए शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ऐसे मामले में, कंपनी का कोई भी सदस्य जो संबंधित पक्ष है, चाहे वह उक्त लेनदेन से संबंधित हो या नहीं, ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देने हेतु पारित प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

**अनुलग्नक: श्री माणिक पॉल द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण**

	31 मार्च 2025 (₹ लाख)	31 मार्च 2024 (₹ लाख)
टोपाज लिमिटेड - सहायक कंपनी को हीरे जड़ित आभूषणों की बिक्री	17,076	14,340
जिरकोन लिमिटेड- सहायक कंपनी को हीरे जड़ित आभूषणों की बिक्री	20	25
एमेथिस्ट लिमिटेड - सहायक कंपनी को हीरे जड़ित आभूषणों की बिक्री	36	15
एमराल्ड लिमिटेड - सहायक कंपनी से हीरे जड़ित आभूषणों की खरीद	11,990 – 6,960 रुपये के उपकरण की खरीद सहित	शून्य
जेड लिमिटेड से पत्थर की वस्तुओं की खरीद - एमराल्ड लिमिटेड की सहयोगी जो कंपनी की सहयोगी है	595	शून्य
रूबी लिमिटेड से हीरे की वस्तुओं की खरीद - एमराल्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी जो कंपनी की सहयोगी है	80	75
कोरल लिमिटेड - संयुक्त उद्यम से हीरे जड़ित आभूषणों की खरीद	1,416	शून्य
संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनी (अर्थात कोरल लिमिटेड) - सैफायर लिमिटेड को हीरे जड़ित आभूषणों की बिक्री	186	230

## बहु विकल्पीय प्रश्न

- 2.1 क्या सैफायर लिमिटेड भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार डायमंड लिमिटेड की संबंधित पक्ष है?
- (क) हां, भारतीय लेखा मानक 24 के तहत, एक संयुक्त उद्यम (अर्थात् कोरल लिमिटेड) की सहायक कंपनी (अर्थात् सैफायर लिमिटेड) डायमंड लिमिटेड की एक संबद्ध पक्ष है।
- (ख) हां, भारतीय लेखा मानक 24 के अंतर्गत सभी स्टेप-डाउन (द्वितीय स्तर) इकाइयां संबंधित पक्ष हैं।
- (ग) हां, भारतीय लेखा मानक 24 के अंतर्गत सभी स्टेप-डाउन (द्वितीय स्तर) सहायक कंपनियां (अर्थात् सैफायर लिमिटेड) संबंधित पक्ष हैं।
- (घ) हां, भारतीय लेखा मानक 24 के तहत डायमंड लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम (अर्थात् कोरल लिमिटेड) की सहायक कंपनी (अर्थात् सैफायर लिमिटेड) को नियंत्रित करता है।
- 2.2 डायमंड लिमिटेड को अपने संबंधित पक्ष प्रकटीकरण में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदान किए गए गैर-मौद्रिक लाभ (अर्थात् कंपनी के स्वामित्व वाली कार) की कितनी राशि का प्रकटीकरण करना चाहिए?
- (क) कार की खरीद कीमत - ₹380 लाख
- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य - ₹35 लाख
- (ग) शून्य, क्योंकि कार का उपयोग मुख्य रूप से आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए किया जाता है
- (घ) वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त मूल्यहास अर्थात् ₹ 76 लाख
- 2.3 डायमंड लिमिटेड को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु जिरकोन लिमिटेड को इसकी बिक्री पर जीएसटी की गणना करने के लिए दिए गए आंकड़ों के आधार पर हीरे जड़े आभूषणों की आपूर्ति का मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है:
- i. चालान मूल्य - ₹20 लाख
- ii. समान प्रकार और गुणवत्ता के माल की आपूर्ति का मूल्य - ₹21 लाख
- iii. ओपन मार्केट वैल्यू - ₹25 लाख
- iv. जिरकोन लिमिटेड द्वारा अपने असंबद्ध ग्राहकों को समान प्रकार और गुणवत्ता के सामान की आपूर्ति के लिए लगाए गए मूल्य का 90% - 20.7 लाख रुपये
- v. आपूर्ति की लागत का 110% - ₹20.9 लाख
- हीरे जड़ित आभूषणों की आपूर्ति का मूल्य \_\_\_\_\_, आपूर्तिकर्ता - डायमंड लिमिटेड ऊपर निर्भर है।
- (क) i या ii
- (ख) ii या iii
- (ग) iii या iv
- (घ) iv या v

- 2.4 कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पूरे जीवन चक्र में कुछ लागत वहन करेगी। सही कथन चुनें?
- (क) डिजाइन चरण (₹600 लाख); विनिर्माण चरण (₹2,000 लाख), परिचालन चरण (₹100 लाख) और जीवन समाप्ति चरण (₹245 लाख)
- (ख) डिजाइन चरण (₹600 लाख); विनिर्माण चरण (₹2,010 लाख), परिचालन चरण (₹135 लाख) और जीवन समाप्ति चरण (₹100 लाख)
- (ग) डिजाइन चरण (₹580 लाख); विनिर्माण चरण (₹1,880 लाख), परिचालन चरण (₹15 लाख) और जीवन समाप्ति चरण (₹470 लाख)
- (घ) डिजाइन चरण (₹80 लाख); विनिर्माण चरण (₹110 लाख), परिचालन चरण (₹1,500 लाख) और जीवन समाप्ति चरण (₹1,255 लाख)
- 2.5 डायमंड लिमिटेड की प्रबंधन संरचना और रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है?
- (क) विभागीय लक्ष्यों को रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हुए शीर्ष प्रबंधन के परिचालन बोर्ड को कम करता है।
- (ख) विकेन्द्रीकृत प्रबंधन संरचना स्वायत्तता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है, जिससे प्रभागीय प्रबंधकों को अपने निर्णयों को कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है।
- (ग) उत्तरदायित्व केंद्र कंपनी के रणनीतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तथा प्रबंधक केवल अल्पकालिक लाभप्रदता लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- (घ) परिचालन जिम्मेदारियां सौंपकर, डायमंड लिमिटेड संभवतः क्षेत्रीय अनुकूलनशीलता और अपने व्यापक रणनीतिक लक्ष्यों के साथ प्रभागीय उद्देश्यों के संरेखण के बीच संतुलन हासिल कर लेता है।

**वर्णनात्मक प्रश्न**

- 2.6 भारतीय लेखा मानक 24 की अनिवार्यताओं के अनुपालन में संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण तैयार करें।
- 2.7 अज्ञात या अघोषित संबंधित पक्षों के जोखिम को कम करने हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का संक्षिप्त सारांश दें?
- 2.8 क्या जेड लिमिटेड के साथ लेनदेन हेतु लेखापरीक्षा समिति की मंजूरी की आवश्यकता है? विश्लेषण करें।
- 2.9 क्या डायमंड लिमिटेड को लाभ होगा यदि इटली शाखा भारत शाखा से खरीदारी करती है? टिप्पणी करें।



## सुझाए गए उत्तर

### बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

#### 1.1 (क) कथन (i) और (iii) सत्य हैं।

##### कारण:

कथन (i) एसएएल द्वारा सीधे ग्राहकों तक पहुँचने वाले सफल मार्केटिंग अभियान के परिणामस्वरूप प्रत्याशित बिक्री से अधिक बिक्री हुई। इससे खरीद और उत्पादन प्रणालियों पर इस मांग को तुरंत पूरा करने का दबाव पड़ा होगा। जेआईटी सिस्टम के कारण, वे अचानक मांग में वृद्धि से निपटने हेतु कोई स्टॉक नहीं रखते हैं। कथन (iii) जहाँ उत्पादन विभाग को मांग के पूर्वानुमान के आधार पर वार्षिक उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनानी होती है। इससे उन्हें सुचारू रूप से संचालन करने हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले खरीद आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय करने की सुविधा मिलेगी। किसी भी अप्रत्याशित अचानक मांग में वृद्धि का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, जिस स्थिति में जेआईटी उत्पादन प्रणाली उपयुक्त नहीं हो सकती है।

कथन (ii) गलत है क्योंकि श्री रे केवल उर्वरकों के 3 ग्रेड की बिक्री के प्रभारी हैं और विनिर्माण प्रक्रिया में किसी अन्य कार्य या संचालन के प्रभारी नहीं हैं। इसलिए, उन्हें कच्चे माल की कीमतों में अचानक वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जिसके कारण वास्तविक योगदान में कमी आई है।

कथन (iv) गलत है क्योंकि जेआईटी खरीद और उत्पादन प्रणाली एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। कच्चे माल का स्टॉक किया जा सकता है जबकि उत्पादन जेआईटी प्रणाली का पालन कर सकता है। इसी तरह, कच्चे माल की खरीद जेआईटी प्रणाली पर की जा सकती है जबकि उत्पादन को स्टॉक में रखा जा सकता है।

#### 1.2 (ग) (i) और (iii)

##### कारण:

कथन (i) और (iii) वे विचार हैं जिन पर एसएएल और पीएएल के लेखापरीक्षकों को अपने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु विचार करने की आवश्यकता है।

कथन (ii): गलत। स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित होने पर भी, अनुपालन पर विचार करने की जिम्मेदारी लेखा परीक्षक की बनी रहती है।

कथन (iv): गलत। हालांकि गैर-अनुपालन के निहितार्थों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विशिष्ट संदर्भ में यह लेखा परीक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं है।

- 1.3 (घ) केवल ग्रेड 1 क्योंकि यह एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो मूल्य के प्रति संवेदनशील है और साथ ही उच्च मार्जिन के कारण सकारात्मक योगदान देने की क्षमता रखता है।

**कारण:**

ग्रेड 1 केवल इसलिए क्योंकि कीमत पर दी गई 10% छूट के लिए मात्रा में वृद्धि 25% थी और इसने सकारात्मक योगदान दिया क्योंकि शुद्ध योगदान 130 रुपये है। उच्च मार्जिन वाले उत्पाद के रूप में, यह किसी भी अप्रत्याशित लागत वृद्धि को कम कर सकता है।

	ग्रेड 1	ग्रेड 2	ग्रेड 3
प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य में कमी	50	20	20
विक्रय मूल्य में कमी %	10%	7%	10%
बिक्री में वृद्धि (किलोग्राम में)	500	100	400
बिक्री में वृद्धि % में	25.00%	3.33%	8.00%
प्रति किलोग्राम शुद्ध अंशदान (वास्तविक)	130	60	-

हालांकि, ग्रेड 3 को 5% सीमा सीमा का उपयोग करके मूल्य संवेदनशील माना जा सकता है, लेकिन प्रति किलोग्राम वास्तविक शुद्ध योगदान शून्य था। इसलिए, ग्रेड 3 के लिए बहुत अधिक छूट देना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि यह कम मार्जिन वाला उत्पाद है। इसी तरह, ग्रेड 2 भी 5% सीमा सीमा का उपयोग करके कम मूल्य संवेदनशील है। यहाँ बिक्री मूल्य में 7% की छूट के परिणामस्वरूप बिक्री की मात्रा में केवल 3.33% की वृद्धि हुई। इसलिए, ग्रेड 2 की बिक्री केवल मूल्य छूट से बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी।

- 1.4 (ख) एसएएल द्वारा यूयूएल का अधिग्रहण अवैध है क्योंकि न्यायाधिकरण द्वारा असहमत शेयरधारकों द्वारा किए गए आवेदन को खारिज करने के बाद भी, यूयूएल ने कुल 8% असहमत शेयरधारकों में से केवल 5% के शेयरों का अधिग्रहण किया।

कारण:

दिए गए मामले में, चूंकि असहमत शेयरधारकों द्वारा किए गए आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है, इसलिए एसएएल असहमत शेयरधारकों के सभी शेयर यानी संपूर्ण 8% शेयरधारिता का अधिग्रहण करने के लिए बाध्य था। चूंकि एसएएल ने असहमत शेयरधारकों की केवल 5% शेयरधारिता का अधिग्रहण किया, इसलिए यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 235 का उल्लंघन है। इसलिए एसएएल द्वारा यूयूएल का अधिग्रहण अवैध है।

- 1.5 (घ) पोषक दक्षता में सुधार, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन किए गए उन्नत फॉर्मूलेशन के लिए पेटेंट दाखिल करने के लिए कानूनी शुल्क।

कारण:

विकल्प (घ) बौद्धिक संपदा संरक्षण और नवाचार में रणनीतिक निवेश को दर्शाता है। उन्नत फॉर्मूलेशन के लिए पेटेंट दाखिल करके, एसएएल उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए विशेष अधिकार सुरक्षित कर सकता है जो न केवल उत्पाद प्रदर्शन और स्थिरता में सुधार करते हैं बल्कि लंबी अवधि में इसकी बाजार स्थिति को भी मजबूत करते हैं। इसके विपरीत, अन्य विकल्प उन गतिविधियों का वर्णन करते हैं जो या तो अक्षमताओं को इंगित करते हैं या महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य प्रदान किए बिना केवल नियमित परिचालन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- 1.6 (ग) यह आय कृषि आय के रूप में योग्य नहीं है और कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बावजूद "व्यापार या पेशे के लाभ और प्राप्य" के अंतर्गत व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य है।

कारण:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1क) के तहत, भारत में कृषि आय में मुख्य रूप से खेती से संबंधित गतिविधियों से प्राप्त आय शामिल है। इसमें कृषि भूमि को किराये पर देने, फसल उगाने और बेचने, बाजार हेतु कृषि उपज का

प्रसंस्करण (जैसे सुखाना, साफ करना या साधारण प्रसंस्करण) तथा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक कृषि भवनों से अर्जित आय शामिल है।

केवल जागरूकता को बढ़ावा देने या प्रदर्शनी हेतु भूमि अधिग्रहण करने से उर्वरक की बिक्री से होने वाली आय कृषि आय में बदलाव नहीं होता है। एसएएल द्वारा अधिग्रहित भूमि का उपयोग जागरूकता बढ़ाने और कस्टमाइज्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर के इस्तेमाल संबंधी प्रदर्शनी हेतु किया जा रहा है। ऐसे प्रमोशन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले किसान ऐसे उर्वरक खरीदते हैं जो उस फसल हेतु अनुकूलित होते हैं जिसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। ऐसे उर्वरकों की बिक्री सीधे भूमि पर किसी भी कृषि गतिविधि से नहीं होती है। इसके अलावा, मामले में स्पष्ट बताया गया है कि इस भूमि पर कोई वास्तविक कृषि उत्पादन नहीं होता है। इसलिए, ऐसे उर्वरकों से एसएएल की बिक्री "व्यवसाय या प्रोफेशन के लाभ और फायदे" के तहत व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य है।

#### वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1.7 इंड एस 20, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण, के अनुसार लेखांकन प्रावधान:

1. ₹5 करोड़ का पहला अनुदान - "उर्वरकों के दुरुपयोग के कारण मिट्टी का क्षरण" पर शोध

पंजाब में मुख्यतः कृषि क्षेत्र से एक विशिष्ट क्षेत्र के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता (अम्लीकरण, कठोरता और प्रदूषण) पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के प्रभावों पर शोध से जुड़े "उर्वरकों के दुरुपयोग के कारण मिट्टी का क्षरण" के लिए पहला अनुदान। चूंकि, अनुदान बिना शर्त दिया गया है और इसके रिफंड के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। भले ही अनुसंधान शुरू नहीं हुआ है, न ही अनुसंधान शुरू करने हेतु एसएएल द्वारा प्रमुख कदम उठाए हैं, फिर भी अनुदान को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि में तुरंत दर्शाया जाएगा।

2. ₹5 करोड़ का दूसरा अनुदान - फसल-विशिष्ट पोषण समाधान के व्यावसायिक विकास से संबंधित है जिससे प्रत्येक फसल किस्म को विशिष्ट पोषक तत्व मिलेगा, जिसकी उसे बढ़ने हेतु आवश्यकता हो। केस स्टडी में दी गई जानकारी के अनुसार, ये समाधान अप्रैल 2026 तक बाजार में उपलब्ध होंगे। इसलिए, उस समय तक, अनुदान नए तकनीकी समाधान (जो एक परिसंपत्ति है) के विकास से संबंधित है और इसे शुरू में आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। आस्थगित आय को इस नई तकनीक के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

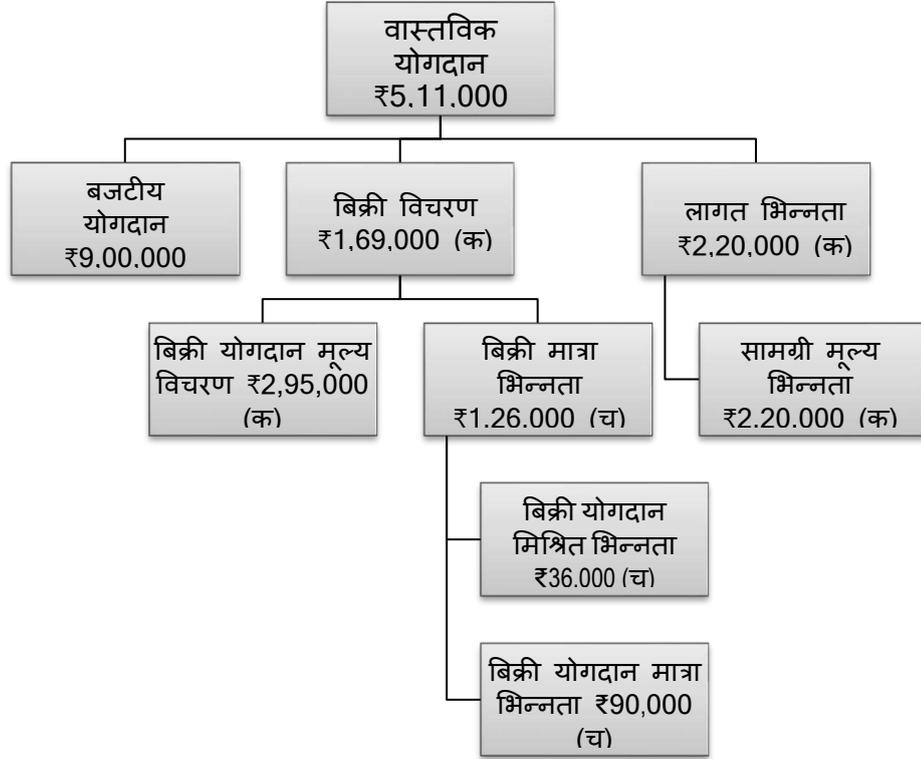
5 करोड़ रुपये के प्राप्त अनुदान के लिए, एसएएल को 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2026 तक तुलन पत्र में देयता को मान्यता देनी चाहिए। जब तकनीक का उपयोग फसल-विशिष्ट पोषण के कमर्शियल विकास में किया जाता है, तो मूल्यहास लागतों की भरपाई हेतु इस नई तकनीक के उपयोगी जीवन पर ₹5 करोड़ की आस्थगित अनुदान आय को मान्यता दी जानी चाहिए।

वैकल्पिक रूप से, भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार, एसएएल को 1 अप्रैल, 2026 तक इस प्रौद्योगिकी के विकास की लागत के विरुद्ध 5 करोड़ रुपये की आस्थगित आय की भरपाई करने की अनुमति दी जाएगी।

3. भूकंप संबंधी मुआवजा - एसएएल 31 मई, 2025 के बाद यानी वित्त वर्ष 2025-26 में ही आवेदन पत्र जमा कर सकेगा। हालांकि भूकंप सितंबर 2024 में वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित था, लेकिन एसएएल को सरकारी अनुदान से होने वाली आय को उस वर्ष मान्यता देनी चाहिए, जिस वर्ष आवेदन जमा किया गया था और मुआवजे के लिए सरकार द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी।

चूंकि वित्त वर्ष 2024-25 में भूकंप आने से पहले बिक्री के आंकड़ों के संबंध में वित्तीय अपनाने के कारण आवेदन पत्र जमा नहीं किया जा सका था, इसलिए एसएएल को अनुदान आय को मान्यता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह 31 मार्च, 2025 तक प्राप्य नहीं हुई है।

1.8 समाधान



**बजटीय बनाम वास्तविक योगदान**

कार्य टिप्पण का संदर्भ देते हुए, वर्ष 2024-25 हेतु कुल बजटीय योगदान ₹9,00,000 था, जबकि वास्तविक योगदान ₹5,11,000 था। इसलिए योगदान के संदर्भ में प्रतिकूल भिन्नता है = बजटीय योगदान - वास्तविक योगदान = ₹9,00,000 - ₹5,11,000 = ₹3,89,000 (प्रतिकूल)

उर्वरकों के तीनों ग्रेडों के लिए वास्तविक योगदान बजटीय योगदान से कम है। ऐसा 2 कारणों से है: छूट देने की नीति (ख) कच्चे माल की खरीद लागत। अब हम भिन्नताओं या विचरण का विस्तार से विश्लेषण करेंगे।

**बिक्री विचरण (योगदान के संदर्भ में)**

बिक्री विचरणों को बिक्री योगदान मूल्य भिन्नता और बिक्री योगदान मात्रा भिन्नता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

बिक्री योगदान मूल्य विचरण की गणना ₹2,95,000 (प्रतिकूल) के रूप में की जाती है

क्र.सं.	बिक्री योगदान मूल्य विचरण	ग्रेड 1	ग्रेड 2	ग्रेड 3	कुल
1	वास्तविक योगदान (प्रति किलोग्राम) * मानक लागत के आधार पर	150 [450-300*]	80 [280-200*]	20 [180-160*]	-
2	मानक योगदान (प्रति किलोग्राम)	200	100	40	-
3	वास्तविक मात्रा (किलोग्राम)	2,500	3,100	5,400	11,000
4	बिक्री योगदान मूल्य विचरण = (वास्तविक योगदान - मानक योगदान) × वास्तविक मात्रा [(1 - 2) × 3]	(1,25,000)	(62,000)	(1,08,000)	(2,95,000)

एसएएल के सेल्स एवं मार्केटिंग अभियान में एक निश्चित सीमा से परे थोक खरीद पर थोड़ी अधिक छूट दी गई। अतिरिक्त छूट के लिए इस नीति को मानक मूल्य (बजट) में शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक और बजटीय योगदान के बीच अंतर आया।

बिक्री योगदान मात्रा विचरण (अनुकूल) की गणना ₹1,26,000 के रूप में की जाती है।

क्र.सं.	बिक्री योगदान मात्रा विचरण	ग्रेड 1	ग्रेड 2	ग्रेड 3	कुल
1	वास्तविक मात्रा (किलोग्राम)	2,500	3,100	5,400	11,000
2	बजट मात्रा (किलोग्राम)	2,000	3,000	5,000	10,000
3	मानक योगदान (प्रति किलोग्राम)	200	100	40	-
4	बिक्री योगदान मात्रा विचरण = (वास्तविक मात्रा - बजट मात्रा) × मानक योगदान [(1 - 2) × 3]	1,00,000	10,000	16,000	1,26,000

बिक्री प्रदर्शन का आकलन करने का यह एक और बुनियादी मीट्रिक है। वास्तविक बिक्री की बजट बिक्री से तुलना करके, कंपनी (क) बाजार की स्थितियों को समझ सकती है जिसमें वह काम करती है (ख) किसी भी सेल्स एवं मार्केटिंग अभियान की सफलता या यहां तक कि (ग) कंपनी की पूर्वानुमान क्षमताओं की तर्कसंगतता को समझ सकती है।

एसएएल के मामले में, वर्ष 2024-25 के लिए 11,000 यूनिट्स की वास्तविक बिक्री की मात्रा 10,000 यूनिट्स की बजट बिक्री से अधिक रही है। इसका एक संभावित कारण तीन नए ग्रेड के लिए इसकी सफल सेल्स एवं मार्केटिंग अभियान के कारण मांग में तेजी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष हेतु ₹1,26,000 का अनुकूल विचरण हुआ।

**योगदान के संदर्भ में बिक्री भिन्नता = बिक्री योगदान मूल्य भिन्नता ₹2,95,000 (प्रतिकूल) + बिक्री योगदान मात्रा भिन्नता ₹1,26,000 (अनुकूल) = ₹1,69,000 (प्रतिकूल)**

यह ऊपर बताए गए समग्र परिणामों से मेल खाता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहां मात्रा से गिरावट हुई, वहीं एसएएल ने अधिक छूट दी होगी जिसने अंततः इसकी लाभप्रदता प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए, ग्रेड 3 उर्वरक, जहां वास्तविक योगदान शून्य है। हालांकि एसएएल ने ग्रेड 3 उर्वरक के बजट से 400 यूनिट्स अधिक बेचीं, लेकिन वास्तविक मुनाफे में योगदान शून्य था। यह सेल्स एवं मार्केटिंग अभियान के हिस्से के रूप में दी गई छूट के कारण (सामग्री की कीमत का प्रभाव बाद में चर्चा की गई है) भी है। एसएएल की सेल्स टीम को यह समझना चाहिए कि लंबे समय में ऐसी छूट देना संभव नहीं हो सकता है। प्रत्येक ग्रेड की बिक्री कीमत मांग को कैसे प्रभावित करती है, इसका मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसे एसएएल की टीम यह समझने हेतु अपना सकती है कि भविष्य में कितनी छूट देनी है।

#### बिक्री योगदान मात्रा भिन्नता का गहराई से विश्लेषण

बिक्री योगदान मात्रा भिन्नता का बेहतर विश्लेषण करने के लिए, इसे बिक्री योगदान मिश्रण भिन्नता और बिक्री योगदान मात्रा भिन्नता के रूप में आगे विभाजित किया जा सकता है।

**बिक्री योगदान मिश्रण विचरण ₹36,000 अनुकूल है।**

उत्पाद	वास्तविक मात्रा (एक्यू)	बजटीय अनुपात में वास्तविक बिक्री (आरएक्यू)	अंतर एक्यू-आरएक्यू	प्रति किलोग्राम मानक योगदान	मिश्रित विचरण अंतर × मानक योगदान
ग्रेड 1	2,500	2,200	300	200	60,000
ग्रेड 2	3,100	3,300	(200)	100	(20,000)
ग्रेड 3	5,400	5,500	(100)	40	(4,000)
<b>कुल</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>-</b>		<b>36,000</b>

बिक्री मिश्रण भिन्नता यह पहचानने में मदद करती है कि कौन सा उत्पाद या प्रोडक्ट लाइनें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बजट अनुपात के अनुसार बिक्री मात्रा संरचना ग्रेड 1: 20%, ग्रेड 2: 30% और ग्रेड 3: 50% थी। 11,000 यूनिट्स की वास्तविक मात्रा पर लागू होने पर, वितरण आरएक्यू - संशोधित वास्तविक मात्रा कॉलम में दिखाई देता है। बेची गई वास्तविक मात्रा और आरएक्यू के बीच का अंतर बजट अनुपात की तुलना में वास्तविक बिक्री के मिश्रण / अनुपात में भिन्नता को दर्शाता है।

तदनुसार, ग्रेड 1 की 300 यूनिट्स अधिक बेची गई हैं, जिसका मिश्रण में उच्च अनुपात है। इसमें अन्य 2 ग्रेड की तुलना में ₹200 प्रति किलोग्राम का उच्चतम योगदान भी है। यह भिन्नता को एक अनुकूल पक्ष में ले जाता है। इसके विपरीत, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का बिक्री मिश्रण में अनुपात कम है, जो बिक्री मिश्रण अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कुल मिलाकर, बिक्री मिश्रण सकारात्मक है क्योंकि एसएएल ने ग्रेड 1 उर्वरक की अधिक बिक्री की है जिसका अन्य 2 ग्रेड की तुलना में अधिक योगदान है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रेड 1 अन्य ग्रेड की तुलना में बेहतर है और व्यवसाय की लाभप्रदता में बेहतर योगदान देता है।

**बिक्री योगदान मात्रा विचरण ₹90,000 अनुकूल है।**

उत्पाद	बजट मात्रा (बीक्यू)	बजटीय अनुपात में वास्तविक मात्रा (आरएक्यू)	अंतर आरएक्यू - बीक्यू	प्रति किलोग्राम मानक योगदान	मात्रा विचरण अंतर x मानक योगदान
ग्रेड 1	2,000	2,200	200	200	40,000
ग्रेड 2	3,000	3,300	300	100	30,000
ग्रेड 3	5,000	5,500	500	40	20,000
<b>कुल</b>	<b>10,000</b>	<b>11,000</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>90,000</b>

अनुकूल बिक्री योगदान मात्रा भिन्नता यह दर्शाती है कि योगदान केवल पूर्व निर्धारित अनुपात (यानी बजटीय) में वास्तविक बिक्री के कारण कितना बढ़ा है, जो बजट के अनुसार अपेक्षाओं से अधिक है। इसमें बिक्री मूल्य में भिन्नता के कारण किसी प्रभाव पर विचार नहीं किया जाता है और इसलिए इसे मानक योगदान के संबंध में मापा जाता है।

वास्तविक बिक्री को संशोधित वास्तविक मात्रा (आरएक्यू) मिश्रण प्राप्त करने हेतु उनके बजट अनुमानों के अनुपात में पुनर्वितरित किया जाता है। इसलिए, यदि

बजट बिक्री 11,000 यूनिट्स होती, तो उर्वरकों के इन ग्रेडों में से प्रत्येक की बिक्री का अनुपात क्या होता? इसे आरएक्यू कॉलम में दिखाया गया है। 10,000 यूनिट्स के मूल बजट अनुमान के साथ तुलना करने पर, यह बेची गई यूनिट्स की मात्रा के अनुपात में परिवर्तन के कारण मानक योगदान पर प्रभाव दिखा सकता है।

प्रत्येक ग्रेड के उर्वरक के लिए मांग पक्ष में वृद्धि के परिणामस्वरूप कंपनी की लाभप्रदता में सकारात्मक योगदान हुआ।

**बिक्री योगदान मात्रा विचरण = बिक्री योगदान मिश्रण विचरण ₹36,000 अनुकूल + बिक्री योगदान मात्रा विचरण ₹90,000 अनुकूल = ₹1,26,000 (अनुकूल)**

मांग में तेजी के कारण उच्च बिक्री (₹90,000 के अनुकूल बिक्री योगदान मात्रा विचरण से संकेतित) और लाभदायक ग्रेड 1 उर्वरक (₹36,000 के अनुकूल बिक्री मिश्रण विचरण से संकेतित) से आने वाली इन बिक्री के उच्च अनुपात के साथ मिलकर, ₹1,26,000 का अनुकूल बिक्री योगदान मात्रा विचरण हुआ।

#### लागत विचरण

उच्च दरों पर अनियोजित सामग्री की खरीद के कारण लागत में वृद्धि ने भी प्रतिकूल योगदान दिया।

**सामग्री मूल्य विचरण ₹2,20,000 प्रतिकूल है।**

क्र.सं.	सामग्री मूल्य विचरण	ग्रेड 1	ग्रेड 2	ग्रेड 3	कुल
1	मानक मूल्य (प्रति किलोग्राम)	150	100	75	-
2	वास्तविक मूल्य (प्रति किलोग्राम)	170	120	95	-
3	वास्तविक मात्रा (किलोग्राम)	2,500	3,100	5,400	11,000
4	सामग्री मूल्य विचरण = (मानक मूल्य - वास्तविक मूल्य) × वास्तविक मात्रा [(1) - (2) × 3]	(50,000)	(62,000)	(1,08,000)	(2,20,000)

सभी ग्रेडों के लिए सामग्री खरीद लागत मानक से अधिक थी। कई बार ऐसा हुआ है कि उर्वरक की किसी विशेष श्रेणी की मांग में अचानक वृद्धि हुई है और साथ ही सफल सेल्स एवं मार्केटिंग अभियान ने बिक्री की मात्रा को बढ़ाया है। जेआईटी आपूर्तिकर्ता भागीदारों के साथ सहमत लागत से अधिक खुले बाजार से खरीद

लागत के परिणामस्वरूप वास्तविक योगदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कार्य टिप्पण

वर्ष 2024-25 के लिए बजट योगदान

क्र.सं.	विवरण	ग्रेड 1	ग्रेड 2	ग्रेड 3	कुल
1	बजट मात्रा (किग्रा)	2,000	3,000	5,000	10,000
2	औसत विक्रय मूल्य (प्रति किग्रा)	500	300	200	-
3	प्रत्यक्ष सामग्री लागत (प्रति किग्रा)	150	100	75	-
4	प्रत्यक्ष श्रम लागत (प्रति किग्रा)	100	60	75	-
5	परिवर्तनीय ओवरहेड लागत (प्रति किग्रा)	50	40	10	-
6	मानक योगदान (प्रति किग्रा) [2-(3+4+5)]	200	100	40	-
7	बजटीय योगदान [1 × 6]	4,00,000	3,00,000	2,00,000	9,00,000

वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक योगदान

क्र.सं.	विवरण	ग्रेड 1	ग्रेड 2	ग्रेड 3	कुल
1	वास्तविक मात्रा (किलोग्राम)	2,500	3,100	5,400	11,000
2	औसत विक्रय मूल्य (प्रति किलोग्राम)	450	280	180	-
3	प्रत्यक्ष सामग्री लागत (प्रति किलोग्राम)	170	120	95	-
4	प्रत्यक्ष श्रम लागत (प्रति किलोग्राम)	100	60	75	-
5	परिवर्तनशील ओवरहेड लागत (प्रति किलोग्राम)	50	40	10	-
6	वास्तविक योगदान (प्रति किलोग्राम) [2-(3+4+5)]	130	60	40	-
7	वास्तविक योगदान [1 × 6]	3,25,000	1,86,000	-	5,11,000

### 1.9 एसएएल के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन

एसएएल का प्रबंधन जिस बेंचमार्क डब्ल्यूएसीसी को बनाए रखना चाहता है, वह 10% से कम है। कंपनी का वास्तविक डब्ल्यूएसीसी 7.636% है। एसएएल मुख्यतः अपनी पूंजी संरचना की वजह से अपने डब्ल्यूएसीसी को आवश्यक बेंचमार्क से नीचे बनाए रखने में सफल रहा है। 16 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण, जो पूंजी जुटाने का सबसे सस्ता स्रोत है, 25 करोड़ रुपये की कुल नियोजित पूंजी का आधे से अधिक हिस्सा है।

एसएएल का वित्तीय प्रदर्शन एक मजबूत परिचालन आधार को दर्शाता है, हालांकि इसकी पूंजी संरचना में कुछ वित्तीय जोखिम भी हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है।

अपनी पूंजी का 64% हिस्सा ऋण से प्राप्त होने के कारण, एसएएल पर 1.12 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान का बड़ा वित्तीय दायित्व है। हालांकि, लेवरेज से रिटर्न बढ़ सकता है, लेकिन इससे वित्तीय जोखिम भी बढ़ता है, जिससे समय पर ऋण चुकौती सुनिश्चित करने और वित्तीय संकट के जोखिम को कम करने हेतु मजबूत नकदी प्रवाह का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है।

इस उच्च ऋण के बावजूद, एसएएल ने मजबूत परिचालन दक्षता का प्रदर्शन किया है, जिसने 9 करोड़ रुपये का पीबीआईटी हासिल किया है। यह वित्तीय दायित्वों से पहले पर्याप्त आय उत्पन्न करने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसका ₹4.391 करोड़ का ईवीए दर्शाता है कि एसएएल अपनी पूंजी की लागत से अधिक रिटर्न कमा रहा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह केवल वित्तपोषण लागतों को कवर करने के बजाय शेयरधारकों के लिए फायदेमंद रहा है।

इस सकारात्मक संचालन को बनाए रखने के लिए, एसएएल को नए निवेश अवसरों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बढ़ावा देने के लिए अपने बेंचमार्क 10% डब्ल्यूएसीसी से अधिक रिटर्न उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा, प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ - जैसे कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के खिलाफ बचाव, पूंजी आवंटन का अनुकूलन एवं वित्तीय बफर बनाए रखना - संभावित जोखिमों को कम करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा।

कुल मिलाकर, एसएएल का मजबूत परिचालन प्रदर्शन और सकारात्मक ईवीए मूल्य सृजन करने की इसकी क्षमता को उजागर करता है। हालांकि, ऋण पर इसकी उच्च निर्भरता सतर्क वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है। सतत विकास सुनिश्चित करने और शेयरधारकों के अधिकतम लाभ के लिए, एसएएल को विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, उच्च-रिटर्न परियोजनाओं में रणनीतिक निवेश और संभावित वित्तीय चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने हेतु मजबूत जोखिम शमन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कार्य टिप्पण

$$\begin{aligned}
 \text{ईवीए} &= \text{एनओपीएटी} - \text{डब्ल्यूएसीसी} \times \text{नियोजित पूंजी} \\
 &= ₹6.3 \text{ करोड़} - 7.636\% \times ₹25 \text{ करोड़} \\
 &= ₹4.391 \text{ करोड़} \\
 \text{नियोजित पूंजी} &= ₹5 \text{ करोड़} + ₹4 \text{ करोड़} + ₹16 \text{ करोड़} \\
 &= ₹25 \text{ करोड़} \\
 \text{डब्ल्यूएसीसी} &= (5 + 4)/25 \times 12.5\% + 16/25 \times 4.9\% \\
 &= 7.636\% \\
 \text{एनओपीएटी} &= [\text{पीबीआईटी} - \text{ब्याज - कर}] + \text{ब्याज (कर शुद्ध)}
 \end{aligned}$$

	₹करोड़ में
पीबीआईटी	9.000
घटाएँ ब्याज	(1.120)
पीबीटी	7.880
घटाएँ 30% कर	(2.364)
पीएटी	5.516
जोड़ें ब्याज (कर के बाद शुद्ध) $[1.12 \times (1 - 0.30)]$	0.784
एनओपीएटी	6.300

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

- 2.1 (क) हां, भारतीय लेखा मानक 24 के तहत, संयुक्त उद्यम (यानी, कोरल लिमिटेड) की सहायक कंपनी (यानी, सफायर लिमिटेड) एक संबंधित पक्ष है।

कारण:

भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 9(ख)(ii) के अनुसार, कोई कंपनी एक रिपोर्टिंग कंपनी से संबंधित है यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सहयोगी या संयुक्त उद्यम (या किसी ऐसे समूह के सदस्य की सहयोगी या संयुक्त उद्यम है जिसका दूसरी कंपनी सदस्य है) है।

इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 12 के अनुसार, संबंधित पक्ष की परिभाषा में, संयुक्त उद्यम में उसकी सहायक कंपनियां शामिल हैं। इसलिए, संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनी और ऐसे संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले निवेशक को भारतीय लेखा मानक 24 के तहत संबंधित पक्ष माना जाता है।

इसके अनुसार, सैफायर लिमिटेड (संयुक्त उद्यम - कोरल लिमिटेड की सहायक कंपनी होने के नाते) और डायमंड लिमिटेड (कोरल लिमिटेड में निवेशक के रूप में) भारतीय लेखा मानक 24 के तहत संबंधित पक्ष हैं।

## 2.2 (घ) वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त मूल्यहास यानी ₹76 लाख

**कारण:**

इंड एस 19 के पैरा 9 में निर्दिष्ट किया गया है कि कर्मचारी लाभों में गैर-मौद्रिक लाभ शामिल हैं। गैर-मौद्रिक लाभ (मुफ्त या सब्सिडी वाले सामान या सेवाओं सहित) प्रदान करने की लागत को नकद में देय लाभों के समान सिद्धांतों के अनुसार मान्यता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, इंड एस 24 के पैरा 9 में गैर-मौद्रिक लाभों सहित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को दिए गए मुआवजे का प्रकटीकरण करने की अनिवार्यता है। इस तरह के प्रकटीकरण में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को लाभ का अनुमान शामिल होना चाहिए। इसकी गणना, उदाहरण के लिए, मूल्यहास शुल्क के संदर्भ में की जा सकती है - यानी ₹76 लाख।

## 2.3 (ग) iii या iv

**कारण:**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार, लेनदेन मूल्य वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत होनी चाहिए यदि आपूर्ति असंबंधित पक्षों के बीच है और कीमत एकमात्र विचार है। धारा 15(4) के तहत जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य उपधारा (1) के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहीं इसे निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

**नियम 28(1)** धारा 25(4) और (5) के तहत निर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या अलग-अलग व्यक्तियों के बीच लेनदेन (माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति) के मूल्यांकन को रेखांकित करता है। मूल्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए:

(क) ऐसी आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य (ओपन मार्केट वैल्यू)

(ख) यदि ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है, तो समान प्रकार तथा गुणवत्ता वाली वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए।

(ग) यदि उपर्युक्त में से कोई भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो नियम 30 (जैसे, आपूर्ति की लागत का 110%) या नियम 31 (जैसे, अन्य उचित तरीकों से) के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

हालांकि, नियम 28 के पहले प्रावधान के अनुसार, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा वस्तुओं को आगे भी आपूर्ति हेतु रखा जाता है, तो आपूर्तिकर्ता के पास प्राप्तकर्ता द्वारा अपने ग्राहक को समान प्रकार और गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति के लिए लगाए गए मूल्य के 90% पर उनका मूल्यांकन करने का विकल्प होता है, बशर्ते कि ग्राहक संबंधित व्यक्ति न हो।

चूंकि जिरकोन लिमिटेड मुख्यतः रिटेल बिजनेस करता है, इसलिए विभागीय संरचना से यह स्पष्ट है कि आभूषण आइटम आगे किसी अन्य हो आपूर्ति हेतु हैं। इसलिए, डायमंड लिमिटेड इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकता है:

- ₹25 लाख का ओपन मार्केट वैल्यू
- जिरकोन लिमिटेड द्वारा अपने ग्राहकों को हीरे जड़े आभूषण आइटम (समान प्रकार व गुणवत्ता के) की आपूर्ति के लिए लगाए गए मूल्य का 90%, यानी ₹20.7 लाख, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है।

इसके अलावा, चूंकि जिरकोन लिमिटेड पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु पात्र नहीं है, इसलिए चालान मूल्य को नियम 28 के दूसरे प्रावधान के तहत ओपन मार्केट वैल्यू के रूप में नहीं माना जा सकता है।

### निष्कर्ष

जीएसटी की गणना के लिए, डायमंड लिमिटेड नियम 28 के तहत निर्धारित मूल्यांकन विधियों के अनुसार 25 लाख रुपये (ओपन मार्केट वैल्यू) या 20.7 लाख रुपये (समान प्रकार और गुणवत्ता की कीमत का 90%) चुन सकता है।

- 2.4 (ख) डिजाइन चरण ( ₹600 लाख); विनिर्माण चरण ( ₹2,010 लाख), संचालन चरण (₹135 लाख) और जीवन समाप्ति चरण ( ₹100 लाख)

कारण:

"ऑरोरा" के जीवन चक्र में चरणवार होने वाली लागत की गणना निम्नलिखित है:

<b>डिजाइन चरण ₹लाख</b>		
अनुसंधान	100	
विकास	300	
डिजाइन एवं परीक्षण	200	<b>600</b>
<b>विनिर्माण चरण ₹लाख</b>		
सामग्री	460	
श्रम एवं ओवरहेड्स	880	
प्रशिक्षण	500	
रखरखाव	170	<b>2,010</b>
<b>संचालन चरण ₹लाख</b>		
वितरण	50	
वारंटी दावे	85	<b>135</b>
<b>जीवन का अंतिम चरण ₹लाख</b>		
पर्यावरण स्वच्छता	70	
निपटान	30	<b>100</b>
<b>कुल</b>	<b>2,845</b>	<b>2,845</b>

- 2.5 (घ) संचालन जिम्मेदारियों को सौंपकर, डायमंड लिमिटेड सबसे अधिक संभावना क्षेत्रीय अनुकूलनशीलता और अपने व्यापक रणनीतिक लक्ष्यों के साथ प्रभागीय उद्देश्यों के संरेखण के बीच संतुलन बनाता है।

कारण:

डायमंड लिमिटेड की विकेन्द्रीकृत संरचना क्षेत्रीय अनुकूलनशीलता पर जोर देती है साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि प्रभाग कॉर्पोरेट रणनीति के साथ संरेखण में काम करते हैं, जिससे विकल्प घ सबसे संभावित परिदृश्य बन जाता है। विकल्प घ विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण का खंडन करता है, और विकल्प क और ख सटीक हैं लेकिन विकल्प घ की तुलना में कम व्यापक हैं।

वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर

2.6 भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" की आवश्यकता के अनुसार, संबंधित पक्षों का नाम, संबंधित पक्ष संबंध, लेन-देन और बकाया शेष राशि जिसमें प्रतिबद्धताएं शामिल हैं जहां नियंत्रण मौजूद है और जिनके साथ रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान लेन-देन हुआ है, निम्नानुसार हैं:

**संबंधित पक्षों की सूची**

**सहायक कंपनियां**

नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इक्विटी ब्याज	
			31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
एमेथिस्ट लिमिटेड	खुदरा परिचालन	भारत	80	80
जिरकोन लिमिटेड	खुदरा परिचालन	भारत	95	95
टोपाज लिमिटेड	खुदरा परिचालन	भारत	100	100
रिटेल जेम्स एस.पी.ए.	खुदरा एवं प्रसंस्करण	इटली	100	100

**संबंध कंपनीयां**

डायमंड लिमिटेड के पास एमराल्ड लिमिटेड में 25% हिस्सेदारी (31 मार्च 2024 तक: 25%) है। बदले में, एमराल्ड लिमिटेड अपनी सहायक कंपनी रूबी लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी (31 मार्च 2024 तक: 51%) रखता है।

**संयुक्त व्यवस्था जिसमें समूह एक संयुक्त उद्यमकर्ता है**

डायमंड लिमिटेड के पास एक संयुक्त उद्यम, कोरल लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी (31 मार्च 2024 तक: 50%) है। कोरल लिमिटेड, बदले में, अपनी सहायक कंपनी, सफायर लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का मालिक (31 मार्च 2024 तक: 51%) है। निम्न तालिका संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन की कुल राशि दर्शाती है।

**मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)**

डायमंड लिमिटेड के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) में शामिल हैं:

- सुश्री रत्ना मलिक, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

लेन-देन एवं बकाया शेष (उन प्रतिबद्धताओं सहित जहां नियंत्रण मौजूद है और जिनके साथ लेन-देन हुआ है)

₹ लाख

संबंधित पक्ष	वित्तीय वर्ष	वर्ष के अंत में बकाया शेष	संबंधित पक्षों को बिक्री (हीरे जड़ित आभूषण वस्तुएं)*	संबंधित पक्षों से खरीदारी (संपत्ति संयंत्र और उपकरण)	संबंधित पक्षों से खरीदारी (हीरे जड़ित आभूषण वस्तुएं)	संबंधित पक्षों से खरीदारी (हीरे की वस्तुएं)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ
<b>सहायक कंपनियां:</b>							
टोपाज़ लिमिटेड	31 मार्च 2025	—	17,076	—	—	—	—
	31 मार्च 2024	—	14,340	—	—	—	—
अन्य सहायक कंपनियां*	31 मार्च 2025	—	56 (इसमें 20 लाख रुपये शामिल हैं जो कि आर्म्स लेंथ से अधिक नहीं है)	—	—	—	—
	31 मार्च 2024	—	40	—	—	—	—
<b>एसोसिएट और उसकी सहायक कंपनी:</b>							
एमराल्ड लिमिटेड	31 मार्च 2025	—	—	6,960	5,030	—	—
	31 मार्च 2024	—	—	—	—	—	—
रूबी लिमिटेड	31 मार्च 2025	—	—	—	—	80	—
	31 मार्च 2024	—	—	—	—	75	—
<b>संयुक्त उद्यम और उसकी सहायक कंपनी:</b>							
कोरल लिमिटेड	31 मार्च 2025	—	—	—	1,416	—	—

	31 मार्च 2024	---	---	---	---	---	---
सैफायर लिमिटेड	31 मार्च 2025	---	186	---	---	---	---
	31 मार्च 2024	---	230	---	---	---	---
<b>प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:</b>							
सुश्री रत्ना मलिक	31 मार्च 2025	---	---	---	---	---	76
	31 मार्च 2024	---	---	---	---	---	---
<b>वे संस्थाएं जहां कंपनी के साथ लेनदेन करने वाले केपी/निदेशकों और/या अन्य रिश्तेदारों द्वारा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जाता है:</b>							
---	31 मार्च 2025	---	---	---	---	---	---
	31 मार्च 2024	---	---	---	---	---	---
*इंड एस 24, पैरा 24 के अनुसार, समान प्रकार की वस्तुओं का एक साथ प्रकटीकरण किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब कंपनी के वित्तीय विवरणों पर संबंधित पक्ष लेनदेन के प्रभावों को समझने हेतु अलग से प्रकटीकरण करना आवश्यक हो। इसके अलावा, पैरा 24क में कहा गया है कि अलग-अलग संबंधित पक्षों के साथ विशेष लेनदेन के विवरण का प्रकटीकरण अक्सर इतना बड़ा होगा कि उसको समझने में परेशानी होगी। तदनुसार, समान प्रकृति की वस्तुओं का संबंधित पक्ष के प्रकार के अनुसार एकसाथ प्रकटीकरण किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण लेनदेन का महत्व अस्पष्ट हो जाए। इसलिए, माल की खरीद या बिक्री को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद या बिक्री के साथ नहीं जोड़ा जाता है। न ही किसी व्यक्तिगत पक्ष के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन को समय प्रकटीकरण में शामिल किया जाता है।							

**टिप्पणी - प्रकटीकरण के उद्देश्य से, केस स्टडी में दिए गए लेनदेन पर ही विचार किया गया है।**

- 2.7 कोई कंपनी ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसमें विशिष्ट नियमों व शर्तों के तहत वाहनों या संरचनाओं या कुछ प्रकार के लेनदेन के संचालन के माध्यम से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने हेतु कंपनी और किसी अन्य पक्ष के बीच औपचारिक या अनौपचारिक समझौता शामिल हो। ऐसी व्यवस्थाएं जो संबंधित पक्ष संबंधों या लेनदेन के होने का संकेत दे सकती हैं, जिन्हें प्रबंधन ने पहचाना नहीं है या लेखा परीक्षकों के समक्ष प्रकट नहीं किया है।

एसए 550 के अनुसार लेखा परीक्षक को इस बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य हासिल करना आवश्यक होता है कि क्या संबंधित पक्ष संबंधों और लेन-देन को उचित रूप से चिन्हित किया गया है, उनका लेखा-जोखा रखा गया है और वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटीकरण किया गया है। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय, लेखा परीक्षक उन संबंधित पक्षों पर विशेष ध्यान देता है जो नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की अपनी क्षमता के आधार पर कंपनी या उसके प्रबंधन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षक रिकॉर्ड या दस्तावेजों का निरीक्षण करते समय, ऐसी व्यवस्थाओं या अन्य सूचनाओं को लेकर सतर्क रहेगा जो संबंधित पक्ष संबंधों या लेन-देन के होने का संकेत दे सकते हैं जिन्हें प्रबंधन ने पहले चिन्हित या लेखा परीक्षक को नहीं बताया है। विशेष रूप से, लेखा परीक्षक संबंधित पक्ष संबंधों या लेन-देन के होने के संकेतों के लिए निम्नलिखित का निरीक्षण करेगा जिन्हें प्रबंधन ने पहले पहचाना या लेखा परीक्षक को नहीं बताया है -

- लेखा परीक्षक की प्रक्रियाओं के भाग के रूप में प्राप्त बैंक, कानूनी और तीसरे पक्ष की पुष्टि;
- शेयरधारकों और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्तियों की कार्यवृत्त; और
- ऐसे अन्य रिकॉर्ड या दस्तावेज जिन्हें लेखा परीक्षक कंपनी की परिस्थितियों में आवश्यक समझता है।

यदि लेखा परीक्षक को ऐसी व्यवस्था या जानकारी पता चलती है जो अज्ञात संबंधित पक्ष संबंधों या लेन-देन के होने का संकेत देती है, तो लेखा परीक्षक को यह निर्धारित करना चाहिए कि अंतर्निहित परिस्थितियाँ उन संबंधों या लेन-देन के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं या नहीं। यदि लेखा परीक्षक संबंधित पक्षों या महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन की पहचान करता है जिसे प्रबंधन ने पहले चिन्हित नहीं है या लेखा परीक्षक को नहीं बताया है, तो लेखा परीक्षक को चाहिए कि वह -

- संबद्धता टीम के अन्य सदस्यों को प्रासंगिक जानकारी तुरंत संप्रेषित करें।
- लेखा परीक्षक के आगे के मूल्यांकन हेतु नए चिन्हित किए गए संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन की पहचान करने के लिए प्रबंधन से अनुरोध करें।
- संबंधित पक्ष संबंधों और लेन-देन पर कंपनी के नियंत्रण के बारे में पूछताछ करें, जो संबंधित पक्ष संबंधों या लेन-देन की पहचान या प्रकटीकरण को सक्षम करने में विफल रहे।

- ऐसे नए चिन्हित किए गए संबंधित पक्षों या महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित उचित मूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित करें।
- इस जोखिम पर पुनर्विचार करें कि अन्य संबंधित पक्ष या महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन मौजूद हो सकते हैं जिन्हें प्रबंधन ने पहले लेखापरीक्षक के सामने चिन्हित या प्रकट नहीं किया है, और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित करें; और
- यदि प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण जानबूझकर नहीं किया गया लगता है (और इसलिए धोखाधड़ी के कारण भौतिक मिथ्या विवरण के जोखिम का संकेत है), तो लेखापरीक्षा के लिए निहितार्थों का मूल्यांकन करें।

**2.8 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, "संबंधित पक्ष" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:**

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (76) के तहत संबंधित पक्ष; या
- लागू लेखांकन मानकों के तहत संबंधित पक्ष।

इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी शामिल है:

2.8.1 कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा है; या

2.8.2 कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी, जो सूचीबद्ध इकाई में इक्विटी शेयर रखती है:

2.8.2.1 20% या उससे अधिक, या

2.8.2.2 10% या उससे अधिक (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी),

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के अनुसार, किसी भी समय, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी आधार पर; संबंधित पक्ष माना जाएगा।

**विश्लेषण**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार

धारा 2(76)(viii) संबंधित पक्ष को परिभाषित करती है जिसमें शामिल हैं:

- सूचीबद्ध कंपनी की होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी;
- होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी जिसकी सूचीबद्ध कंपनी भी सहायक है;

- सूचीबद्ध कंपनी की निवेशक कंपनी या उद्यमकर्ता।  
हालाँकि, इस खंड में किसी सहयोगी के सहयोगी को शामिल करने हेतु परिभाषा का विस्तार नहीं किया गया है।
- एमराल्ड लिमिटेड, डायमंड लिमिटेड (25% हिस्सेदारी) का प्रत्यक्ष सहयोगी होने के नाते, संबंधित पक्ष के रूप में योग्य है।
- जेड लिमिटेड, एमराल्ड लिमिटेड (22% हिस्सेदारी) का सहयोगी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डायमंड लिमिटेड के लिए संबंधित पक्ष के रूप में योग्य नहीं है, क्योंकि धारा 2(76)(viii) के तहत परिभाषा में सहयोगी के सहयोगी को शामिल नहीं किया गया है।

सेबी एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 2(1)(जेडबी) के अनुसार

विनियमन निर्दिष्ट करता है कि सूचीबद्ध कंपनी में 10% या अधिक इक्विटी शेयर रखने वाली कोई भी कंपनी (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी) संबंधित पक्ष मानी जाती है।

- ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जेड लिमिटेड के पास डायमंड लिमिटेड में कोई इक्विटी है।
- इसके अलावा, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जेड लिमिटेड एक सूचीबद्ध कंपनी है या नहीं। इसलिए, जेड लिमिटेड इस विनियमन के तहत संबंधित पक्ष के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार

भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 9(ख)(ii) में कहा गया है कि यदि कंपनी दूसरी कंपनी की सहयोगी या संयुक्त उद्यम है या उस समूह के सदस्य की सहयोगी/संयुक्त उद्यम है जिसका दूसरी कंपनी सदस्य है, तो कंपनी रिपोर्टिंग कंपनी से संबंधित है।

पैराग्राफ 12 स्पष्ट करता है कि सहयोगी में सहयोगी की सहायक कंपनियां शामिल हैं। हालांकि, सहयोगी का सहयोगी भारतीय लेखा मानक 24 के तहत संबंधित पक्ष की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

इसके अनुसार, जेड लिमिटेड (एमराल्ड लिमिटेड की सहयोगी होने के नाते, जो खुद डायमंड लिमिटेड की सहयोगी है) भारतीय लेखा मानक 24 के तहत डायमंड लिमिटेड से संबंधित पक्ष नहीं है।

निष्कर्ष

चूंकि जेड लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय लेखा मानक 24 या सेबी एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 2(1)(जेडबी) के तहत संबंधित पक्ष नहीं है, इसलिए प्रस्तावित लेनदेन हेतु जेड लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

2.9 प्रश्न परिभाषा: यदि रिटेल जेम्स डिवीजन अहमदाबाद से खरीदता है, तो क्या इससे पूरी कंपनी को लाभ होगा?

मुख्य विचार: बाहरी और आंतरिक बिक्री विकल्पों के तहत प्रति वर्ष योगदान और कर प्रभाव।

कार्यप्रणाली:

भाग 1: अहमदाबाद डिवीजन को लाभ

वर्तमान में बाहरी बिक्री 1,00,000 यूनिट है। यदि अहमदाबाद डिवीजन रिटेल जेम्स की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सहमत होता है, तो बाहरी बिक्री में 30,000 यूनिट की कटौती करनी होगी। बिक्री मिश्रण बाहरी बिक्री 70,000 यूनिट और आंतरिक हस्तांतरण 50,000 यूनिट होगा। (कार्य टिप्पण 1 देखें)

अहमदाबाद डिवीजन पहले 1,00,000 यूनिट का उत्पादन कर रहा था। रिटेल जेम्स के ऑर्डर को स्वीकार करने पर, यह 1,20,000 यूनिट की पूरी क्षमता पर काम कर रहा है, अतिरिक्त 20,000 यूनिट का उत्पादन किया जा रहा है। कार्य टिप्पण 2 के अनुसार, प्रत्येक विकल्प से योगदान ₹28,000 प्रति वर्ष है।

अतिरिक्त योगदान

$$= 20,000 \text{ यूनिट} \times ₹28,000 \text{ प्रति वर्ष}$$

$$= ₹ 56,00,00,000$$

अहमदाबाद डिवीजन भारत में 30% की दर से कर का भुगतान करता है।

इसलिए, शुद्ध कर योगदान

$$= ₹ 56,00,00,000 \times (100\% - 30\%)$$

$$= ₹ 39,20,00,000$$

भाग 2: खुदरा रत्नों के लिए शुद्ध अतिरिक्त लागत

रिटेल जेम्स वर्तमान में इटली में जेम-मिलानो के समान आइटम ₹1,44,000 प्रति वर्ष (₹ समतुल्य मूल्य) पर खरीद रहा है। यदि वह अहमदाबाद डिवीजन से खरीदता है, तो उसे ₹9,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

अतिरिक्त खरीद लागत

$$= 50,000 \text{ यूनिट्स} \times (₹1,53,000 - ₹1,44,000)$$

$$= ₹ 45,00,00,000$$

हालाँकि, यह अतिरिक्त लागत 40% की दर से कर कटौती योग्य है, जो इटली में कर की दर है। इसलिए अतिरिक्त लागत (कर के बाद शुद्ध)

$$= ₹ 45,00,00,000 \times (100\% - 40\%)$$

$$= ₹ 27,00,00,000$$

भाग 3: कंपनी को कुल लाभ (कर पश्चात्)

अहमदाबाद डिवीजन को ₹39,20,00,000 का लाभ होता है जबकि रिटेल जेम्स को ₹27,00,00,000 की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है। इसलिए, कंपनी को कर पश्चात् शुद्ध लाभ ₹12,20,00,000 है। इसलिए, रिटेल जेम्स को अहमदाबाद डिवीजन से आंतरिक रूप से जेम-मिलानो खरीदना चाहिए।

कार्य टिप्पण

1. अहमदाबाद डिवीजन की क्षमता उपयोग का विवरण

क्र.सं.	विवरण	यूनिट्स की संख्या
1	अधिकतम क्षमता	1,20,000
2	बाह्य बिक्री	1,00,000
3 = 1 - 2	अतिरिक्त क्षमता	20,000
4	खुदरा रत्न की आवश्यकता	50,000
5 = 4 - 3	खुदरा रत्न की मांग को पूरा करने के लिए बाह्य बिक्री में कटौती = खुदरा रत्न की आवश्यकता - अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध = 50,000 यूनिट्स - 20,000 यूनिट्स	30,000

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अहमदाबाद डिवीजन के पास वर्तमान में 20,000 यूनिट्स की अतिरिक्त क्षमता है। हालाँकि, अगर इसे रिटेल जेम्स की आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो बाहरी बिक्री में 30,000 यूनिट्स की कटौती करनी होगी।

2. अंशदान का विवरण पी.यू.

आंकड़े ₹ में

क्र.सं.	विकल्प	बाह्य बिक्री	आंतरिक बिक्री
1	विक्रय मूल्य पी.यू.	1,08,000	1,26,000
2	परिवर्तनीय लागत पी.यू.	80,000	74,000
3	संशोधन लागत पी.यू.	---	24,000
4 = 1 - 2 - 3	योगदान पी.यू.	28,000	28,000

मई, 2025 की परीक्षा के लिए मानकों / मार्गदर्शन टिप्पणियों / विधायी संशोधनों आदि की प्रयोज्यता

मुख्य पाठ्यक्रम

प्रश्न-पत्र 4: प्रत्यक्ष कर कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान

मई, 2025 परीक्षा के लिए वित्त अधिनियम, निर्धारण वर्ष आदि की प्रयोज्यता

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान, जिनमें 31.10.2024 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं, परिपत्र तथा विधायी संशोधन शामिल हैं, मई, 2025 परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं। प्रासंगिक निर्धारण वर्ष नि.व.2025-26 है।

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों पर आधारित मुख्य प्रश्न-पत्र 4 की अध्ययन सामग्री मई 2025 परीक्षा के लिए प्रासंगिक है। उक्त अध्ययन सामग्री में मॉड्यूल 1 से 4 शामिल हैं। अध्ययन सामग्री को मई 2025 परीक्षा के लिए वैधानिक अद्यतन के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें 31.10.2024 तक जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र शामिल हैं, लेकिन जो अध्ययन सामग्री व मई 2025 परीक्षा के लिए न्यायिक अद्यतन में शामिल नहीं हैं।

*टिप्पणी - अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर कुछ विषयों के संबंध में, अर्थात्, मॉडल टैक्स सम्मेलनों का अवलोकन, कर संधियों का अनुप्रयोग व व्याख्या, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण के मूल सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में नए रुझान, अध्ययन सामग्री में शामिल विशिष्ट सामग्री मई, 2025 परीक्षा के लिए प्रासंगिक होगी।*

प्रश्न-पत्र 5: अप्रत्यक्ष कर कानून

मई 2025 की परीक्षा हेतु निम्नलिखित उपयुक्त हैं:

- (i) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधान, जिनमें जारी की गई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र तथा किए गए अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं।
- (ii) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधान, जिनमें जारी की गई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं और परिपत्र तथा किए गए अन्य विधायी संशोधन शामिल हैं, जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं।

**टिप्पणी** - वार्षिक केंद्रीय वित्त अधिनियमों द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017, आईजीएसटी अधिनियम, 2017, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में किए गए संशोधन बाद में अधिसूचित तिथि से प्रभावी किए गए हैं। प्रासंगिक वित्त अधिनियमों द्वारा किए गए केवल वे संशोधन जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं, मई 2025 की परीक्षा हेतु उपयुक्त हैं। इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2024 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 द्वारा किए गए वे संशोधन जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं, मई 2025 की परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं।

तदनुसार, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16, 109 और 171 में किए गए संशोधन, जो 31.10.2024 तक प्रभावी हो गए हैं, मई 2025 की परीक्षा हेतु उपयुक्त हैं और वित्त अधिनियम, 2024 और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 द्वारा किए गए शेष संशोधन उक्त परीक्षा हेतु उपयुक्त नहीं हैं।

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9, 9क और 9ग में और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में किए गए संशोधन और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में नई धारा 65क को सम्मिलित करना 31.10.2024 तक प्रभावी नहीं हुए हैं और इस प्रकार, मई 2025 की परीक्षा हेतु उपयुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(4), 95, 102, 103, 104, 105 और 106 में किए गए संशोधन और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में नई धारा 101क, 101ख और 101ग को शामिल करना 31.10.2024 तक प्रभावी नहीं हुआ है और इस प्रकार, मई 2025 की परीक्षा के लिए लागू नहीं हैं।

नीचे दिए गए अध्ययन दिशानिर्देश में मई 2025 की परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम से हटाए गए विषयों को दर्शाते हैं।

**पाठ्यक्रम से विषयवार बहिष्कृत विषयों की सूची**

(1)	(2)	(3)
पाठ्यक्रम में क्रम सं.	पाठ्यक्रम के विषय	बहिष्करण (प्रावधान जो पाठ्यक्रम के संबंधित विषय से बाहर रखे गए हैं)
<b>भाग-I: वस्तु एवं सेवा कर</b>		
(i)	निम्नलिखित पर आधारित केस अध्ययन:	(i) माल की आपूर्ति के लिए निर्धारित कर की दर*

	सीजीएसटी एवं आईजीएसटी का शुल्क और संग्रहण - सीजीएसटी/आईजीएसटी कानून का अनुप्रयोग; आपूर्ति की अवधारणा, अंतर-राज्य आपूर्ति, अंतर-राज्य आपूर्ति, प्रादेशिक जल में आपूर्ति; रिवर्स चार्ज सहित कर का प्रभार; कर से छूट; आपूर्ति का स्थान; आपूर्ति का समय; आपूर्ति का मूल्य; इनपुट टैक्स क्रेडिट; जीएसटी देयता की गणना	(ii) सेवाओं की आपूर्ति के लिए निर्धारित कर की दर* (iii) माल की आपूर्ति के लिए छूट (iv) उन मामलों में आपूर्ति का मूल्य जहां केरल बाढ़ उपकर लागू है। (v) इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण का तरीका और रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में इसके उलटफेर (vi) गोल्ड डोर बार के संबंध में अतिरिक्त सीमा शुल्क के क्रेडिट के उलटफेर का तरीका
(xii)	अन्य प्रावधान	संक्रमणकालीन प्रावधान

\*संयोजन लेवी के अंतर्गत देय कर की गणना हेतु निर्दिष्ट दरें पाठ्यक्रम में शामिल हैं।

**टिप्पणी :** उपरोक्त तालिका में, कॉलम (2) में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के विषयों के संबंध में संबंधित बहिष्करण कॉलम (3) में दिया गया है। जहां पाठ्यक्रम के किसी विषय में बहिष्करण निर्दिष्ट किया गया है, वहां अन्य विषयों में शामिल ऐसे बहिष्करणों के अनुरूप प्रावधान भी बहिष्कृत किए जाएंगे, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अध्ययन सामग्री में शामिल संपूर्ण सामग्री (सिवाय इसके कि जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सामग्री परीक्षा के लिए प्रासंगिक नहीं है) अकेले ही उक्त परीक्षा के लिए प्रासंगिक होगी।

#### प्रश्न-पत्र 6: एकीकृत व्यावसायिक समाधान

यह प्रश्न-पत्र कई विषयों की केस स्टडी-आधारित प्रश्न-पत्र है जिसमें मुख्य स्तर पर प्रश्न-पत्र 1 से 5 में शामिल अवधारणाओं और प्रावधानों के अनुप्रयोग के साथ-साथ

स्वाध्याय मॉड्यूल सेट क और ख शामिल हैं। मुख्य स्तर और स्वाध्याय ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न-पत्र की सूची निम्नानुसार है -

मुख्य पाठ्यक्रम	
प्रश्न-पत्र 1	वित्तीय रिपोर्टिंग
प्रश्न-पत्र 2	उन्नत वित्तीय प्रबंधन
प्रश्न-पत्र 3	उन्नत लेखा परीक्षा, आश्वासन एवं व्यावसायिक नैतिकता
प्रश्न-पत्र 4	प्रत्यक्ष कर कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान
प्रश्न-पत्र 5	अप्रत्यक्ष कर कानून
स्वाध्याय ऑनलाइन मॉड्यूल	
*समूह क	कॉर्पोरेट एवं आर्थिक कानून
समूह ख	रणनीतिक लागत एवं प्रदर्शन प्रबंधन

**टिप्पणी :** मई, 2025 परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र 6: एकीकृत व्यावसायिक समाधान के लिए मानकों / मार्गदर्शन टिप्पणियों / विधायी संशोधनों आदि की प्रयोज्यता / अप्रयोज्यता उपरोक्त प्रत्येक अलग-अलग प्रश्न-पत्र हेतु लागू के समान होगी।

\*अध्ययन सामग्री को मई 2025 की परीक्षा के लिए 31.10.2024 तक जारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों को कवर करने वाले प्रासंगिक संशोधनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।